हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 फरवरी, 2004

खण्ड–1, अंक–7

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार 16 फरवरी, 2004

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(7)1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नो के लिखित उतर	(7)22
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(7)23

अध्यक्ष द्वारा घोशणा	(7)28
ध्यानाकर्शण प्रस्तावो की सुचनाएं	(7)28
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य	(7)30
वाक आउट	(7)35
विधान सभा समितियो की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	(7)36
वर्श 2004–05 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)37
वाक आउट	(7)50
(वर्श 2004–05 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)50
वाक आउट	(7)52
(वर्श 2004–05 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)52
वर्श 2004–05 की अनुदानो की मांगो पर चर्चा तथा मतदान	(7)77

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 16 फरवरी, 2004

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्ड़ीगढ़ में प्रातः 11.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादयान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उतर

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

तारांकित प्र न संख्या– 1747

(इस समय माननीय सदस्य श्री राम भगत सदन मे उपस्थित नही थे इसलिए यह प्र न पूछा नही गया।)

तारांकित प्र न संख्या–1688

(इस समय माननीय सदस्य श्री नफे सिंह राठी सदन मे उपस्थित नही थे इसलिए यह प्र न पूछा नही गया।)

Amount allocated under Indra Awaas Yojana

***1722. Shri Ram Phal Kundu, Dr. Malik Chand Gambhir:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the details of amount allocated under Indra Awaas Yojana during the year 2002-2003 and 2003-2004 togetherwith the amountspend for the construction of houses therefrom separately; and

(b) the district wise number of houses construced under the scheme referred to in part 'a' above during the said period?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा):

(क) वर्श 2002–2003 तथा 2003–2004 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अधीन कम ाः 1563.92 लाख रुपये तथा 171.10 लाख रुपये की रा ि ा आबंटित की गई थी। इसके विरुद्ध वर्श 2002–2003 के दौरान मकानो के निर्माण के लिए 1927.659 लाख रुपये तथा वर्श 2003–2004 (दिसम्बर 2003 तक) के दौरान 1213.896 लाख रुपये की रा ि ा खर्च की गई।

(ख) एक विवरणी सदन के पटल पर रखी गई है।

विवरणी

कम संख्या	**जिले का नाम**	**वर्श 2002–03 के दौरान निर्मित किये गये मकानो की संख्या**	**वर्श 2003–04 (दिसम्बर 2003 तक) के दौरान निर्मित किये गये मकानो की संख्या**
1	अम्बाला	892	441
2	भिवानी	735	301

3	फरीदाबाद	719	569
4	फतेहाबाद	266	225
5	गुडगांव	717	253
6	हिसार	602	301
7	झज्जर	202	176
8	जीन्द	330	280
9	कैथल	330	194
10	करनाल	627	268
11	कुरुक्षेत्र	522	130
12	महेन्द्रगढ	270	121
13	पंचकुला	109	40
14	पानीपत	445	73
15	रिवाडी	401	187
16	रोहतक	384	323
17	सिरसा	563	395

18	सोनीपत	605	183
19	यमुनानगर	1121	433
	कुलः	**9840**	**4893**

चौ0 रामफल कुण्डूः स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से माननीय सी0 पी0 एस0 महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इनको बताने के लिए नार्म्ज क्या है? स्पीकर सर, जिस प्रकार से 5100 रुपए कन्यादान के रुप मे हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे वाले चाहे वे किसी भी वर्ग से संबंधित हो, को देने का फैसला किया है। क्या उसी तरह से गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले हर वर्ग को ये मकान देने का सरकार का कोई विचार है?

श्री रामपाल माजराः अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम केन्द्र सरकार की 75 प्रति ात की और राजय सरकार को 25 प्रति ात की भागीदारी से चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत गरीब लोगो के लिए रहने के मकान बनाने की योजना है। स्पीकर सर, इसमे 60 प्रति ात ि ाडयूल्उ कास्टस के लिएऔर 40 प्रति ात दूसरी जाति के गरीब लोगो के लिए मकान बनाने का पहले से ही पैरामीटर बना हुआ है। हमारे पास जितनी रा ि ा आती है उसका 60 प्रति ात ि ाडयूल्ड कास्ट के मकानो पर और 40 प्रति ात

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दूसरे वर्गो के लिए मकान देने के लिए है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 31 मार्च तक यह साल खत्म हो जाएगा और जो अब तक अम्बाला मे 892 हाउसिज कंस्ट्रक्ट किए जाने थे लेकिन इसमे 442 हाउसिज़ ही कन्सट्रक्ट किए गए है। लगभग आधे का फर्क है ओर अब यह सरकार मार्च खत्म होने पर हडबडाहट मे पैसा देकर मकानो को बनवाने का काम करेगी। ये जो मकान इन्कम्पलीट रह गए है तो इसका क्या कारण है?

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि सभी कार्य प्रोग्रैस मे है। 2003.04 के अंत का लेखा जोखा अप्रैल मे आएगा। स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से सदन मे यह बताना चाहूंगा कि 1991 से लेकर अप टू दिसम्बर 2003 तक 37361 रिकार्ड तोड मकान बने है। (विघ्न) इकटठा मिलाने के बाद भी ये मकान इनके समय के मुकाबले ज्यादा बनते है। इनहोन हडबडाहट वाली बात कही है लेकिन मै इनको बताना चाहूंगा कि हडबडाहट मे कुछ नही होगा। जो लाभार्थी है उनकी मर्जी है, कई बार तो वह सामान ले लेते है और कई बार वे लिखकर अपनी इच्छा जाहिर करते है कि उनको सामान नही चाहिए। कई बार वे डिपार्टमैंट से मैटीरियल लेकर भी बना लेते है क्योंकि अगर वे डिपार्टमैंट के थ्रू मैटीरियल लेते है

तो उनको सीमेंट और ईटों के दामो मे फायदा होता है लेकिन अगर वे चाहे तो मैटीरियल के स्थान पर कै ा भी ले सकते है इस तरह से वे अपनी इच्छा जाहिर करते है।

तारांकित प्र न संख्या–1680

(इस प्र न पूछा नही गया कयोंकि इस समय माननीय सदस्य श्री भाि ा परमार सदन मे उपस्थित नही थे।)

Improvement in burnout rate of transformers

***1765 Sh. Ramesh Rana:** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is fact that a large number of distribution transformers are burnt in the State; if so the improvement, if any, made in burnout rate of such transformers alongwith the details thereof?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा): हां श्री मान जी, यद्यपि विभिन्न उपयुक्त कदमो के परिणामस्वरुप राजय मे वितरण ट्रांसफार्मरो की क्षतिग्रस्त दर वर्श 1996–97 मे 31.21% से घटकर वर्श 2003–04 (दिसम्बर तक) मे 12.18% हो गई है। पिछले आठ वर्शो के दौरान वितरण ट्रांसफार्मरो के क्षतिग्रस्त होने की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्श	स्थापित किए गए ट्रांसफार्मरो की संख्या	क्षतिग्रस्त हुए ट्रांसफार्मरो की संख्या	क्षति का प्रति ात

1996—97	95221	29721	31.21
1976—98	98500	33266	33.77
1998—99	103507	27635	26.70
1999—2000	107011	24902	23.27
2000—01	111476	21133	18.96
2001—02	117301	18457	15.73
2002—03	125368	18229	11.90
2003—04 दिसम्बर तक	131647	16034	12.18

श्री रमे ा राणाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा माननीय सी0 पी0 एस0 महोदय से जानना चाहता हूं कि जो यह ट्रासफार्मज का डैमेज रेट दिसम्बर 2003 तक 12.18 प्रति ात से घटकर आया है तो क्या और भी कोि ा ा की जा रही है कि यह रेट इसे भी कम आए?

श्री रामपाल माजराः हां, स्पीकर सर, जब से माननीय औम प्रका ा चौटाला जी की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक 26342 नये ट्रांसफार्मर और इसमे जोडे गये है। इसकी वजह से ही उपर कंट्रोल किया जा रहा है। इसके अलावा भी और कदम

उठाए जा रहे है, नये ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे है। इसी प्रकार से वितरण लाईनो मे कंडक्टर लगा जा रहे है, फीडरो का द्विविभाजन और त्रिविभाजन किया जा रहा है और एल0 टी0 प्रणाली मे भी सुधार किया जा रहा है। एल0 टी0 प्रणाली मे केवल क्षमता बढाने के लिए कदम उठाए जा रहे है। इसी प्रकार से वितरण ट्रांसफार्मर का नियुक्ति अनुरक्षण किया जा रहा है और वितरण ट्रांसफार्मर्ज का तीन फेज का भार भी संतुलित किया जा रहा है तथा चैकिंग भी की जा रही है ताकि कोई कम्पेस्टर न लगा सके। इस तरह से ये जो सार`पग उठाए जा रहे है। उनकी वजह से ही ट्रांसफार्मज का बरैन्ट रेट 12.18 प्रति ात रह गया है जो कि हमारी उल्लेखनीय उपलब्धि रही है।

श्री पूर्ण सिह डाबडाः अध्यक्ष महोदय, पी0 यू0 सी0 ने एक बार कई जगहो पर ट्रांसफार्मर्ज का और वर्क ाप वगैरह का इंस्पैक ान किया था। जब पी0 यू0 सी0 ने इनका कार्ड मैनटेन करने के लिए कहा था तो बिजली महकमे ने इसके लिए हां भरी थी तो मै आपकी मार्फत इनसे जानना चाहूंगा कि क्या अब इनकी मैंटनैंस के लिए वे कार्ड मैनटेन किए जा रहे है?

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, जहां तक पी यू सी की रिकमंडे ान का प्र न है उसके लिए अभी तक कोई कार्ड मैनटेन करने की बात नही आई। किसी भी प्रकार से बरन्ट टरांसफार्मर को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए इसके लिए हम और योजना भी बना रहे है ताकि किसी प्रकार से प्राईवेट आदमी

को देकर, बेाली आमंत्रित करके जल्दी से ठीक करके दिया जा सके।

श्री कृश्ण लाल पंवारः स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से सी पी एस महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से रमे ा राधा जी ने टरांसफार्मर कू बारे मे प्र न पूछा है। क्या विभाग ने प्रदे ा मे कोई ऐसा सर्वे कराया है कि जो ओवरलोड टरांफार्मर जैसे 25 के वी के है, 63के वी ए और 100 के वी ए के है क्या ऐसा कोई सर्वे कराया है कि उनको जलने से पहले उनमे इम्प्रूवमैंट करके उनकी कपैसिटी बढा दी जाए।

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, इतनी ज्यादा संख्या मे ट्रासंफार्मर लगाए है और यह लोगो की ि ाकायत पर लगाए गए है जब लोग यह कहते है कि हमारे बल्ब नही जलते है, हमारी म ाीने नही चलती है, हमारी इंडस्ट्री नही चलती। कंज्यूमर की तरफ से कोई ि ाकायतकी जाती है तो चैकिंग की जाती है और जहां लगता है कि वास्तव मे आगॅमैंट करने की जरुरत है वहां पर किया जाए और इसमे लोगो की ि ाकायत के उपर यह अंदाजा लगा लिया जाता है। वह ट्रांसफार्मर जो आलरेडी कमी ांड है वह ओवरलाडिड है और बल्ब तक नही जल रहे है, इंडस्टरी नही चल रही है, टयूबवैल नही चल रहे है, म ाीनरी नही चल रही है तो इस बात को लेकर यह लोगो की ि ाकायत पर किया जाता है।

चौ0 रामफल कुण्डुः स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से सी पी एस महोदय से जानना चाहूंगा कि जिस तरह ट्रांसफार्मर जल जाता है लोग ि ाकायत करने जाते है जैसे उस ट्रांसफार्मर पर 8–10 कनैक ान हैउनमे से यदि किसी एक का बिल बकाया रह जाता है तो महकमे वाले यह कह देते है कि पहले उसका बिल भरवाओ।

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, रिकवारी तो बहुत ही जरुरी है एक दो लोग के बिल जमा न हुए हो तो उनका कहा जाना जरुरी है, हां यदि किसी एक दो का बिल बकाया रह जाता है तो ट्रांसफार्मर बदलने पर रोक नही लगायी जाती। आपका ट्रांसफार्मर एक व्यक्ति के बिल अदा न करने से नही बदला जाएगा, ऐसी कोई योजना नही है। दस कंज्यूमर है उनमे से आठ बिल जमा कर देते है दो बिल नही जमा करते है तो ट्रांसफार्मर बदला न जाए, ऐसी नही है।

श्री पूर्ण सिंह डाबडाः स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से सी पी एस महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या किसी की रिस्पैंसिबिल्टी फिक्स की जाती है जब ट्रांसफार्मर जलता है कि किस कारण से जला, इवन डिस्ट्रिब्यू ान आफ लोड, नान मैंटेनैंस की वजह से जला या जी ओ सी स्विच को फाल्ट से जला, क्या कही किसी की जिम्मेदारी फिक्स की जाती है। मैने कार्ड का जिक किया था और पहले भी प्वायंट आउट किया था यदि मुझे याद है तो इस हाउस के अंदर आ वासन दिया गया था कि यह कार्ड

प्रणाली चालू की जाएगी ताकि किसी को जिम्मेदारी नि चत की जाए कि उस व्यक्ति की वजह से यह ट्रांसफार्मर जला है।

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, जहां तक ग्रामीण क्षेत्र की बात है लोग जब उनकी लाइट चली जाती है तो अपने आप मोटा फयूज लगा लेते है क्योंकि उनको टैक्नीकल नालेज तो होती नही जिसकी वजह से ओवरलोड होने के कारण ट्रांसफार्मर जल जाता है। जैसे किसी गांव मे दस ट्रांसफार्मर्ज है और उनमे से दो ट्रांसफार्मर जल गये है तोउन दो ट्रांसफार्मर वाले लोग दूसरे ट्रांसफार्मरज पर कुण्डियां डाल लेते है। जिसकी वजह से वे दूसरे ट्रांसफार्मर भी जल जाते है। अब देहात मे पता नही किसकी वजह सेट्रांसफार्मर जला है इसकी रिस्पौंसेबिलिटी तो फिक नही की जा सकती। सरकार की कोि ा ा यह रहती है कि जहां पर ट्रांसफार्मर जल गये है वहां 48 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफार्मर चेंज होने चाहिए। ट्रांसफार्मर को जल्दी बदलने की नीति सरकार की है।

श्री रमे ा कुमार खटकः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे कि मंत्री जी ने अपने जवाब मे अभी बताया है कि गांव के देहात मे जो लोग कुण्डी लगा लेते है और कुण्डी लगाने की वजह से ट्रांसफार्मर जल जाता है तो क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि कितनी जनसंख्या पर एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है?

श्री राम पाल माजराः अध्यक्ष महोदय, जब लोग अपना कनैक ान लेने के लिए सिक्योरिटी जमा करते है तो उसमे अपना लोड द ार्ति है उसके हिसाब से ही ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते है। लेकिन उससे ज्यादा तो कनैक ान बढ जाते है उनको अनएथोराईज्ड कनैक ान कहा जाता है।

चौ0 नफे सिंह राठीः स्पीकर सर, मै माननीय सी पी एस महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जैसे कि कुण्डू साहब ने अभी बिजली के बिल भरने के लिएसवाल उठाया। मै माजरा साहब से जानना चाहता हूं कि सरकार ने बिजली बिल भरने के लिएजो बिल काउंटर खोले है क्या उसके बारे मे कोई पहले सर्वे कराया गया है? जैसे बहादुरगढ मे 35 हजार कंज्यूमर्ज है और सिर्फ दो ही बिल काउंटर खोले गए है अगर वहां पर रोजाना आठ घंटे भी काम किया जाये तो 30 दिन मे 14400 बिल ही भरे जायेंगे। इसलिए लोगो को भारी दिक्कत का सामान करना पउ रहा है। लोगो को घंटो लाईन मे खडा होना पडता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि पूरी हरियाणा मे एक सर्वे करवा कर बिल काउंटर खोलने की स्कीम पर सरकार विचार करे।

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, वैसे तो यह प्र न ट्रांसफार्मरसे संबंधित था बिलो की रिकवरी के बारे मे नही है। फिर भी मै राठी साहब से कहना चाहूंगा कि वे पहले लोगो से रिकवारी करवाये, काउंटर तो और खोल दिए जायेंगे। हमने सब डिवीजन लेवल पर अधिकारियो को निर्दे ा जारी कर रखे है और

हमारे अधिकारी उन गावों मे बिल लेने जाते भी है जिन गावो की तरफ से यह मांग आयेकि हमारे बिल तो हमारे गांव मे ही लिए जाएं इस बारे मे एक तिथि निर्धारित कर दी जाती है ओर ईवर डोर पर जाकर बिलो की रिकवरी की जाती है।

श्री कृश्ण लाल पंवारः स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से सी पी एस महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो ट्रांसफार्मर डैमेज का मामला है ये ओवरलोड की वजह से प्लेटस हीट अप होकर जल जाती है। बहुत सेट्रांसफार्मर आयल की कमी के कारण भी जल जाते है। इस बारे में मै सी पी एस महोदय से पूछना चाहूंगा कि ट्रांसफार्मरो की ऑयल चैकिंग के लिए कोई कमेटी गठित की गई है तो समय समय पर ट्रांसफार्मरो की चैकिंग करे और ऑयल की कमी हो तो वह समय रहते पूरी की जाये ताकि कम ट्रांसफार्मर जलें।

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि जब ट्रांसफार्मर लगाये जाते है तब उनकी प्लेटे, फयूज, ऑयल आदि पूरी तरह से चैक करके लगाये जाते है। उसके बाद भी बकायदा ट्रांसफार्मरो की चैकिंग समय समय पर होती रहती है। जब लोग ि ाकायत करते है तो ईनि ियल स्टेज पर कोि ा ा यही रहती है कि वही पर ट्रांसफार्मर ठीक कर दिए जायें। यदि वहां ईक नही होते है तो ट्रांसफार्मर उतारकर दूसरा ट्रांसफार्मर रिप्लेस कर दिया जाता है

और जो ट्रांसफार्मर खराब होते है उन्हे ठीक करवाने के लिए वर्क ाप में भेज दिया जाता है।

Adoption of Villages for Agricultural Technology

***1659. Sh. Puran Singh Dabra:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to adopt the villages of the State to impart training and to give know-how of the latest Agricultural Technology to the farmers?

कृशि मंत्री (स0 जसविन्द्र सिंह संधु): नही श्रीमान् जी। तथापि चौ0 चरण सिंह हरियाणा कृशि वि वविद्यालय, हिसार के कृशि ज्ञान केन्द्रो/ कृशि विज्ञान केन्द्रो द्वारा किसानो को प्रि ाक्षण देने हेतु गावों को अपनाया जाता है।

श्री पूर्ण सिंह डाबडा: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से कृशि मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से कार्पोरे ान है और दूसरी बडी बडी जो कम्पनीज़ है वे खेल टीमो को ऐडोप्ट करती है, कई कंपनी सार्वजनिक तौर पर चौराहो या फव्वारे ऐडौप्ट करती है। क्या इसी तरह किसी कंपनी या कार्पोरेान की तरफ से किसी गांव को एडोप्ट करने का कोई प्रपोजल सरकार के पास आया है ताकि लेटैस्ट टैक्नोलोजी की खेती के बारे मे लोगो को जानकारी हो। सरकार भी चाहती है कि कौप पैटर्न मे चेंज हो और किसान अच्छी फसल ले सके। क्या सरकार के पास किसी गांव को एडोप्ट करने का कोई प्रस्ताव किसी

कंपनी की तरफ से आया है यदि आया है तो क्या सरकार उसे कंसीडर कर रही है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधुः अध्यक्ष महोदय, यह बातसही है कि स्पोर्टस को बढावा देने के लिए कार्पोरे ान और अन्य बडी बडी कंपनीज़ टीमें ऐडोप्ट कर रही है।मेरे माननीय साथी डाबडा साहब ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। हम इस पर विचार करेंगे कि विभिन्न कार्पोरे ांज की तरफ से इसके लिए गांव ऐडोप्ट किए जायें।

Number of Trees Plantd in Pataudi Constituency

***1671. Sh. Rabir Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the number of trees planted in the Pataudi Constituency during the year 2000-01, 2001-02 and 2002-03 together with the amount incurred thereon; and

(b) the present position of the above said trees?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा):

(अ) वर्श 2000–01, 2001–02 तथा 2002–03 के दौरान पटौदी हल्के मे 255770 वृक्ष लगाये गये और उन पर 22.67 लाख रुपये खर्च किये गये। विवरण निम्न प्रकार से है:–

वर्श	लगाये गये पौधौ की	किया गया खर्च

	संख्या	(लाखो में)
2000–01	34000	4.06
2001–02	65570	7.41
2002–03	156200	11.20

(ब) इन वृक्षो की औसत जीवित प्रति ात 80 से 90 प्रति ात है और पौधारोपण स्थिति बहुत अच्छी है।

श्री रामबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सी पी एस महोदय से कहना चाहूंगा कि इन्होने जो आंकडे प्रस्तुत किये है मुझे लगता है कि ये सही नही है क्योंकि इन्होने जीवित प्रति ात 80 से 90 प्रति ात बताई है। मै सी पी एस महोदय से पूछना चाहूंगा कि गावों मे सरकार की तरफ से जो वृक्ष लगाये गये है उनकी देखभाल के लिए संबंधित गावों का पंचायतो को कोई अधिकार दे रखे है ताकि वृक्षो की सुरक्षा हो सके। कही ऐसा तो नही हो रहा एक दफा मैने अखबार मे एक चुटकुला पढा था कि तीन आदमियो की पेड लगाने की डयूटी लगाई गई। एक आदमी की डयूटी गढढा खोदने की थी दूसरे आदमी की डयूटी पेड लगाने की थी और तीसरे आदमी की डयूटी मिटटी से गडडा भरने की थी। एक दिन गढढा खोदने वाला गढढा खोद रहा था और मिटटी डालने वाला मिटटी डाल रहा था किसी ने उनसे पूडा कि आप लोग यह क्या कर रहे हो। उन्होने जवाब दिया कि पेड लगाने वाला छुटटी पर है। कहीं ऐसा तो अब नही हो रहा है। यह

पर्यावरण से संबंधित मामला है। इन आंकडो की जांच की जाये की पेड सही मे लगाये गये है या नही लगाये गये?

श्री राम पाल माजराः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने इन पौधो के सरवाईवल रेट पर वि ोशतौर पर आक्षेप किया है। मै सदस्य महोदय की जानकारी मे लाना चाहता हूं कि इन पर माननीय मुख्य मंत्री जी खुद अपनी निगरानी रखते है। इन पौधो के सरवाईवल के लिए पहले तो महकमे की तरफ से चैकिंग होती है। इसके अलावा सरकार द्वारा इसके लिए एक कमेटी कान्सटीच्यूट की गई जिसमे प्रोमिनैन्ट आदमी भाामिल किए गए, जिनमे अखबार के एडिटर, साइंटिस्ट ओर विभाग के एक्सपर्ट लगाये गए। इस कमेटी ने इन पौधो के बारे मे जो अपनी रिपोर्ट दी है वह ही मैने आपको बताई हैं। डिपार्टमैंट वाली रिपोर्ट तो हो सकता है कुछ मिथ्या भी हो लेकिन इसकी निगरानी के लिए एक निश्पक्ष कमेटी कान्स्टीच्यूट की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट मे माना है कि जो प्रति ात रेट दिया है वह सही है। मै कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट जिलावाईज आई है वह भी बता देना उचित समझता हू। इस कमेटी मे एक श्री प्रेम कुमार, प्रेजीडेन्ट, ऐडीटर रिटायर्ड इंडियन एक्सप्रैस थे, दूसरे आर एस भार्मा भी रिटायर्ड एडीटर, दैनिक ट्रिब्यून और तीसरे सदस्य श्री आर एन कौल एक्सपर्ट फोरेस्टरी को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया था। इस कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि पंचकुला मे सरवाईकल रेट 90 से 95 प्रति ात, यमुनानगर मे 90 से 95, कैथल मे 95 से 98, रिवाडी मे

90, महेन्द्रगढ मे 95, झज्जर मे 95 से 95, हिसार मे 95, सिरसा मे वैरी गुड और भिवानी मेभी वैरी गुड सरवाईवल की रिपोर्ट आई है। स्पीकर सर, यह रिपोर्ट निश्पक्ष है जिसमे सरवाईवल रेट बहुत अच्छा बताया गया है।

डा0 रघूबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सी पी ए महोदय ने जो डेटा इन पौधो की सरवाईवल का सदन की टेबल पर रखा है और जितने प्लांट हरियाणा बनने के बाद लगे है अगर इनका सरवाईवल रेट इतना अच्छा होता तो आज के दिन सारे हरियाणा मे ग्रीनरी नजर आती। अध्यक्ष महोदय, जैसे इन्होने डाटा दिया इस बारे मे मेरा सजै ान हैकि इसकी सही जांच पडताल के लिए एक हाउस की कमेटी बनाई जाये ताकि वह कमेटी पता लगा सके कि जो डेटा दिया गया है उसकी करैक ान क्या है। यदि इस डेटा पर सुओ–मोटो वि वास करे तो अलग बात है लेकिन मै चाहता हूं कि सइकी जांच पडताल के लिए एक हाउस की कमेटी बनायी जाये जो इस सरवाईवल रिपोर्ट के बारे मे पता लगा सके कि सही फैक्ट्स क्या है?

मुख्य मंत्री (श्री औम प्रका ा चौटाला): अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मानित सदस्य को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जब विधान सभा मे किसी प्र न का उतर दिया जाता है तो वह सही दिया जाता है। और अगर किसी सदस्य को ऐसा महसूस हो कि गलत जवाब है तो उसके खिलाफ प्रिविलेज मो ान लाया जा सकता है, ऐसे मौको पर सुझाव नही दिये जा सकते।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो रिपोर्ट हाउस मे दी है इनकी वह रिपोर्ट अच्छी है। मै इनकी जानकारी मे लाना चाहता हूं कि जो नये पौधे लगाने से पहले के पौधे लगाये हुए है उनमे से बहुत भारी मात्रा मे सूख भी गए है। उन सुखे हुए पौधो को महकमे के लोगो द्वारा काट लिया जाता है। मै इनकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि आदरणीय स्वर्गीय चौ0 देवी लाल जी ने यह आदे ा दिये थे कि इन काटे जाने वाले पौधो मे से आधा हिस्सा किसान को दिया जायेगा। किसी किसान के खेत के 1 से लेकर 5 तक पौधे सूख जाते है और फोरेस्ट विभाग वाले काट कर उन पौधो को अपने स्टोर मे ले जाते है लेकिन उनमे से जो किसान का हिस्सा होना चाहिए, वह उनको नही देते। मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी बात इनके नोटिस मे है, यदि है तो क्या किसान को उसका आधा हिस्सा उन पौधो का मिलेगा?

श्री औम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बात अगर किसी के नोटिस मे आती है तो वह ि ाकायत करे और यदि कोई ि ाकायत आये तो उसकी इनकवायरी की जाती है। वैसे जो पौधे किसान को दिए जाते है वे लाईन बांट कर दिये जाते है और जो लाईन किसान के हिस्से मे आएगी अगर उसमें कोई दरख्त सूखा है तो किसान का है। अगर कोई व्यक्ति उस दरख्त को उठाकर ले जाए तो उसके खिलाफ ऐक ान लिया जा सकता है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि स्टेट मे पेडो के लिए कितना बजट रखा गया है, कितना खर्च हो गया है ओर टोटल कितने पेड लगाने की सरकार की योजना थी औरकितने पेड स्टेट मे लगे है? इसी से संबंधित मेरा दूसरा प्र न हैकि इन्होने कहा कि 95% पौधे कामयाब हो गये है और कई जगह पर तो 100% कामयाब हो गये है और वेरी गुड कह दिया। अध्यक्ष महोदय, सारे दे ा की जो एवरेज है वह 80% से उपर नही है। मैने भी यह महकमा सैंटर मे चार साल तक सम्भाला है और स्टेट मे भी 5–6 साल यह महकमा मेरे पास रहा है इसलिए मै इसके बारे मे जानता हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार यह बताने की कृपा करे कि टोटल कितने पेड लगाने थे और कितने पेड लगे?

श्री औम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय,हाउस के सम्मानित सदस्य चोधरी भजन लाल जी स्टेट के मुख्य मंत्री रहे है। केन्द्र मे भी यह मन्त्रालय देखते रहे है और यह महकमा भी इनके पास रहा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने एक टारगेट मुकर्रर करके रखा है ताकि वह पौधे लगाए और इससे स्टेट को लाभ होगा तथा किसान को भी लाभ होगा। पिछले साल स्टेट मे भयंकर सूखा पडा और भयंकर सूखा पडने के बावजूद भी भंयकर सूखे की स्थिती होते हुए भी जो पौधे लगाए थे उनमे से बहुसंख्यक पौधे लगे है इसके लिए इन्हे प्रदे ा सरकार के अधिकारियो तथा प्रदे ा सरकार की सराहना करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इस साल भी हमारी सरकार ने साढे चार करोड पौधे लगाए है और अगर जनाब की सरकार का लेखा जोखा किया जाए तो यह अंतर एक से सौ के बीच भी मिल सकता है।

चौ0 भजन लालः अध्यक्ष महोदय, **********

श्री अध्यक्षः भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठें (विघ्न)इनकी कोई भी बात रिकार्ड न की जाए।

Repair of Roads

***1656. Sh. Krishan Lal:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following damaged roads of district Panipat:-

(i) Balijatan to Dharamgarh;

(ii) Matlodha to Sehra; and

(iii) Matlodha (Bus-stand) to Grain Market, Matlodha; if so, the time by which the said roads are likeluy to be repaired?

कृशि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह संधू): हॉ श्रीमानफ जी, उक्त सडको की मरम्मत 30–09–2004 तक कर दिए जाने की सम्भावना है।

श्री कृश्ण लाल पंवारः अध्यक्ष महोदय, हालांकि मेरा सवाल माननीय कृशि महोदय से था लेकिन रिप्लाई माननीय सी

पी एस महोदय दे रहे है इसलिए मै माननीय सी पी एस महोदय से कहना चाहूंगा कि तीन रोडज का जिक आया है और बताया गया है कि 30–9–2004 तक उनकी मुरम्मत करवा दी जाएगी। मतलौडा बस स्टैंड से मतलौडा अनाज मण्डी तक की सडक की हालत बहुत ही खस्ता है। यह रोड बी एण्ड आर विभाग ने बनाई थी लेकिन पिछली बार इस रोड की रिपेयर एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड ने की थी। जब इस रोड की रिपेयर के लिए उनके अधिकारियो से बात करता हू तो बोर्ड के अधिकारी यह कहते है कि हमने यह रोड बी एण्ड आर डिपार्टमैंट का ट्रांसफर कर दी है और बी एण्ड आर डिपार्टमैंट वाले कहते है कि इसकी रोड रिपेयर मार्किटिंग बोर्ड करेगा। अध्यक्ष महोदय, मै माननीय कृशि मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि मतलौडा बस स्टैंड से मतलौडा अनाज मण्डी तक जो रोड है उसकी रिपेयर मार्किटिंग बोर्ड करेग या बी एण्ड आर महकमा करेगा?

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, मे अपने माननीय साथी श्री कृश्ण लाल पंवार जी को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी के आदे ा के मूताबिक जिन रोडज की हालत बहुत ज्यादा खस्ता थी उनमे से करीब एक हजार किलोमीटर रोड्ज की मुरम्मत हमने मार्किटिंग बोर्ड के श्रू करवाई थी और वे रोडज वापिस पी डबल्यू डी को दे दी थी। जहां तक मतलौडा बस स्टैंड से मतलौडा अनाज मण्डी तक की सडक की बात है, इसके बारे मे मै अपने माननीय साथी

कृश्ण लाल पंवार जी को यह आ वासन देता हूं कि यह रोड सितम्बर 2004 तक पूरी कर दी जाएगी और इसके लिए उन्हे किसी दूसरे विभाग के पास जाने की जरुरत नही है।

श्री रमे ा राणाः स्पीकर सर, यह बात तो ठीक है कि आज हरियाणा के अंदर सडको की बहुत अच्छी हालत है लेकिन स्पीकर सर, जैसे कि हरियाणा गवर्नमैंट ने एक स्कीम बनाई थी कि गावों के अंदर जहां पर पानी ठहरता है वहां सीमेन्ट के पैच लगा दिए जाएंगे। मेरे हलके के अंदर सडके बहुत ही अच्छी है लेकिन कई जगो पर पैच लगाने बाकी रह गये है, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा किये पैच उन सडको पर कब तक लग जाएंगे? इसके साथ ही गानजबड से बढौली तक जो रास्ता जाता है उस पर ठेकेदार ने काम करना रोक रखा है। उस सडक पर रोडी, मिटटी आदि डाल रखी है। पता नही क्यों वह ठेकेदार बीच मे ही काम रोक कर चला गया है।

श्री अध्यक्षः राणा जी, यह प्र न तारांकित प्र न से अलग है इसलिए आप इस प्र न को अलग से लिखकर भेज देना और मंत्री जी इसका जवाब आपको दे देंगे।

मुख्यमंत्री (श्री औम प्रका ा चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मै सदन मे जानकारी देना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदे ा की मौजूदा सरकार की पॉलिसी है कि जहां कही पर भी पानी खडा रहता है वहां पर सीमेंटिड पैच लगाए जाएंगे। चाहे वह स्टेट हाईवे हो,

लिंक रोडज हो या दूसरी सडके हो, चाहे फिरनी ही क्यों न हो वहां पर सीमेंटड रोड बनाएंगे क्योंकि पानी और तारकोल का कोई मेल नही होता है। मै इनको यह बताना चाहूंगा कि महंगा रोड एक बार और सस्ता रोए बार बार।

Number of New Power Generation Projects

***1731. Shri Nafe Singh Jundla:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there are any new power generation projects in hand, in the State; if so, the number thereof togetherwith the time by which the said projects are likely to be completed?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा): हां श्रीमान जी। राज्य मे तीन नई बिजली उत्पादन परियोजनाएं हाथ मे है। ये इस प्रकार है:—

1. 500 मैगावाट क्षमता को ताउ देवी लाल थर्मल पावर स्टे ान, पानीपत मे 7वीं तथा 8वीं इकाई।

2. 14.4 मैगावाट क्षमता की पि चमी यमुना नहर, हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना चरण—2।

3. 500 मैगावाट क्षमता की यमुनानगर थर्मल पावर परियोजना चरण—2।

500 मैगावाट थर्मल क्षमता की पानीपत परियोजना वर्श 2004—05 के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है। पि चमी

यमुना नहर, हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना, चरण–2, मार्च 2004 तक तथा 500 मैगावाट क्षमता की यमुनानगर थर्मल पावर परियोजना चरण–2, 10वीं पंचवर्शीय योजना के लगभग पूरा होन का अनुमान है।

श्री नफे सिंह जुण्डला: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सी पी एस महोदय ने अपने उतर मे द ार्या है कि पानीपत की ताउ देवी लाल थर्मल पावर स्टे ान, पानीपत की 250–250 मैगावाट की दो यूनिट्स का काम चल रहा है और यह 2004–05 मे बन कर तैयार हो जाएगी। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह सवाल है कि ये यह बताएं कि ये यूनिटस किस एग्जैक्ट टाईम पर कम्पलीट हो जाएंगी, कौन से महीने मे कम्पलीट हो जाएंगी। मेरा दूसरा प्र न यह है कि इसके अलावा 14.4 मैगावाट की क्षमता की पि चमी यमुना नहर, हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना चरण–2 तथा 500 मैगावाट क्षमता की यमुनानगर थर्मल पावर परियोजना चरण–2 पर टोटल कितना खर्च आएगा? मंत्री जी इस बारे मे बताने का कश्ट करे।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, जुण्डला जी का प्रथम सवाल यह है कि पानीपत की 7वीं और 8वीं युनिट कब चालू हो जाएगी। 7वीं और 8वीं यूनिट की कोमैंसिंग डेट 25.10.04 और 25.02.2005 है। इस पर 945.33 करोड रुपये खर्च हो चुके है। इसके अलावा मानिटरिंग भी की जा रही है, बार बार सर्वे किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि जो समय निर्धारित किया गया

है उससे पहले ही ये यूनिटस भाुरु होने जा रही है। मय से पहले काम कम्पलीट करने के लिए कंपनी को 2 करोड रुपये प्रति महीने के हिसाब से इन्सैंटिव भी दिया जाएगा। इस बात का ऐलान किया गया है। जहां तक माननीय साथी ने जो यह जानना चाहा कि हाइडल प्रोजैक्ट की प्रोग्रैस रिपोर्ट क्या है तो अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर बहुत लम्बा रिप्लाई होगा। मै इसके काम के बारे मे इनको बताना चाहूंगा कि कितना कितना काम कि किस जगह पर अभी तक हुआ है। टर्बो जनरेटर की स्थापना का काम 65 प्रति ात तक पहंच गया है, एग्जलरी की स्थापना का काम 50 प्रति ात, 66 के वी रिचर्ड यार्ड पावर की वैक्यूए ान प्रणाली का काम 80 प्रति ात हो गया है, ग्गजलरी सप्लाई के 11 के वी फीडर का 70 प्रति ात का काफी काम हुआ है। इसी तरह से और भी काफी काम सिविल वर्क्स के हुए है जैसे हाईडल चेनल को 1. 5.2000 को चालू कर दिया गया है। इसी प्रकार से सिल इग्जैक्टर के बाई पास के चैनल का डी आर ब्रिज जंक ान ज्वाइनिंग चैनल का कार्य प्रगति पर है। इसी तरह से इन्होने हाईड्रल प्रोजैक्ट के बारे मे भी जानना चाहा है। मै थोडा सा इसके बारे मे इनको बताना चाहूंगा कि चरण दो के दो यूनिट 7.2 मैगावाट के है। केन्द्रीय प्राद्योगिकरण से 1990 मे 28.80 करोड रुपयेकी अनुमानित लागत से इसकी तकनीकी स्वीकृती मिली थी। परंतु यमुना पानी कें बंटवारे पर इंटर स्टेट डिस्प्यूट होने की वजह से यह रुक गया था लेकिन फिर इसका विवाद हल हो गया था इसलिए पहली अप्रैल 1996 को इसका कार्य फिर से भाुरु हुआ। यह कार्य योजन

के लिए और परियोजन के लिए भाुरु किया गया था लेकिन इसके लिए ऋण जुटाने का कार्य पोखरण मे विस्फोट के मामले को लेकर डिले हो गया। फिर पावर फाईनैंस कार्पोरे ान ने इसको कियान्वित करने के लिए इसके लिए 56 करोड रुपयेके ऋण की स्वीकृती दी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1998 के आधार पर अब 70 करोड रुपये हो गयी है। इसमे ब्याज आदि के लिए 24 करोड रुपये और अतिरिक्त भाामिल किए गए। इस योजना का सिविल कार्य 7.8.2000 को 20.99 करोड रुपये की लागत पर मैसर्ज हरि चंद्र इंडिया लिमिटेड को दिया गया था। इस कंपनी ने दिसम्बर, 2000 मे पावर हाउस का निर्माण का कार्य भाुरु कर दिया है और अब इस का 90 प्रति ात कार्य पूर्ण हो गया है। 1.5. 03 को हाईड्रल चैनल का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल ने इलैक्ट्रिकल और मैकनिकल कार्य 19.12.03 को आरम्भ कर दिये है इसका भी 65 प्रति ात का काम पूरा हो गया है। इस परियोजना पर अब तक 44.77 करोड रुपये खर्च हो चुके है। यह परियोजना मार्च, 2004 मे चालू हो जाएगी। इसके बाद राज्य को प्रतिदिन लगभग दो लाख से लेकर तीन लाख यूनिट बिजली अतिरिक्त मिलेगी।

Transfer of patients from one Hospital to another

***1713. Sh Suraj Mal**: Will the Minister of State for Health be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to provide facilities to

transfer of patients from one hospital to another, if so, the details thereof?

स्वास्थय राज्य मंत्री (डा0 एम. एल. रंगा): हॉ श्रीमान् जी। सैक्अर निवे ा प्रोग्राम के अंतर्गत सभी 64 सामुदायिक स्वास्थय केन्द्रो मे मरीजो को एक से दूसरे अस्पताल मे लाने ले जाने के लिए एक एम्बूलैंस उपलब्ध करना विचाराधीन है।

Construction of Power Sub-Stations

***1635. Sh. Karan Singh Dalal:** Will the Chief Minister be pleased to state the number of Power Sub-stations constructed in the State during the year 2000-2001, 2001-02 , December-2003 togetherwith the capacity and location of these Power-Sub-stations along with expenditure incurred on each Sub-station?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

राज्य मे वर्श 2000–01, 2001–02, तथा 2003–04 (दिसम्बर 03 तक) के दौरान निम्नलिखित उप–केन्द्रो का निर्माण किया गया है।

वर्श	220 के वी	132 के वी	66के वी	33 के वी	योग	लागत (रु

						करोड)
2000–01	–	2	–	3	5	7.02
2001–02	–	1	6	5	12	28.35
2002–03	3	5	3	4	15	98.62
2003–04 (दिसम्बर 2003)	2	11	2	14	29	114.08

प्रत्येक उप–केन्द्र की क्षमता स्थल, खर्च को दर्शाने वाला वर्षानुसार विवरण निम्न प्रकार से है:–

अप्रैल 2000 से मार्च 2001तकचालू किए गए नए उप–केन्द्र

क्रम	उप–केन्द्र का नाम	जोडी गई क्षमता	लागत (रु लाखो में)	चालू होने की तिथि	जिला का नाम
1	**132 के वी**				
	कुण्डली	16 एम वी ए	273	30.05.2000	सोनीपत
	पाली/गोठडा	16 एम वी ए	229	22.12.2000	रेवाडी
	योग	**32 एम वी ए**	**502**		

क्रम	उप–केन्द्र का नाम	जोडी गई	लागत (रु लाखो में)	चालू होने की तिथि	जिला का नाम
2	33 के वी				
	आई ए सिरसा	4 एम वी ए	56	27.05.2000	सिरसा
	जहाजगढ	6.3 एम वी ए	78	19.01.2001	झज्जर
	कवारतन	4 एम वी ए	66	22.03.2001	कैथल
	योग–II	**14.3 एम वी ए**	**200**		
	योग I-II	**46.3 एम वी ए**	**702**		

अप्रैल 2001 से मार्च 2002 तक चालू किए गए नए उप–केन्द्र

क्रम	उप–केन्द्र का नाम	जोडी गई	लागत (रु लाखो में)	चालू होने की तिथि	जिला का नाम

I	**132 के वी**				
	सैक्टर 27 / 28 हिसार	16 एम वी ए	234	27.08.2001	हिसार
	योग	**16 एम वी ए**	**234**		

II	**66 के वी**				
	सैक्टर 46 फरीदाबाद	16 एम वी ए	332	28.04.2001	फरीदाबाद
	एन एच 3 फरीदाबाद	16 एम वी ए	428	30.06.2001	फरीदाबाद
	सैक्टर 31 फरीदाबाद	16 एम वी ए	320	31.10.2001	फरीदाबाद
	रायपुरानी	16 एम वी ए	295	30.11.2001	पंचकूला
	सैक्टर 34 गुडगांव	16 एम वी ए	340	25.12.2001	गुडगांव
	सैक्टर 55 / 56	16 एम वी ए	345	28.02.2002	गुडगांव

	गुडगांव				
	योग (II)	**96 एम वी ए**	**2060**		

III	**33 के वी**				
	बीआना	6.3 एम वी ए	128	20.07.2001	करनाल
	खु ापुरा	5 एम वी ए	108	30.09.2001	रिवाडी
	अजित नगर	4 एम वी ए	130	31.08.2001	फतेहाबाद
	बवानीयां	5 एम वी ए	86	08.02.2002	महेन्द्रगढ
	डबलाना	5 एम वी ए	89	09.02.2002	महेन्द्रगढ
	योग (II)	**25.3 एम वी ए**	**541**		
	योग (I-II-III)	**137.3एम वी ए**	**2835**		

अप्रैल 2002 से मार्च 2003 तक चालू किए गए नए उप–केन्द्र

कम	उप–केन्द्र का नाम	जोडी गई	लागत (रु लाखो में)	चालू होने की तिथि	जिला का नाम

I	**220 के वी**				
	यमुनानगर	100 एम वी ए	1375	23.07.2002	यमुनानगर
	महेन्द्रगढ	100 एम वी ए	2068	29.12.2002	महेन्द्रगढ
	फतेहाबाद	100 एम वी ए	2458	31.01.2003	फतेहाबाद
	योग (I)	**300 एम वी ए**	**5901**		

II	**132 के वी**				
	करीवाला	16 एम वी ए	543	11.04.2002	सिरसा
	मुडियाखेडा	16 एम वी ए	442	03.09.2002	महेन्द्रगढ
	जलमाना	16 एम वी ए	437	24.10.2002	करनाल
	सतनाली	16 एम वी ए	508	09.11.2002	महेन्द्रगढ
	नेवल	16 एम वी ए	449	14.02.2003	करनाल
	योग (II)	**80 एम वी ए**	**2379**		

III	**66 के वी**				
	भौराकलां	12.5 एम वी ए	215	30.10.2002	गुडगांव
	छेन्सा	16 एम वी ए	611	01.05.2002	फरीदाबाद
	मनसा देवी काम्पलैक्स पंचकूला	16 एम वी ए	341	26.03.2003	पंचकूला
	योग (III)	**44.5 एम वी ए**	**1167**		

IV	**33 के वी**				
	केहरवाला	4 एम वी ए	128	11.04.2002	सिरसा
	जी टी रोड पानीपत	6.3 एम वी ए	112	03.09.2002	पानीपत
	झांसा	6.3 एम वी ए	81	24.10.2002	कुरुक्षेत्र

	जखौली	8 एम वी ए	94	09.11.2002	कैथल
	योग (IV)	**24.6 एम वी ए**	**415**		
	योग (I to IV)	**449.1 एम वी ए**	**9862**		

अप्रैल 2002 से मार्च 2003 तक चालू किए गए नए उप–केन्द्र

क्रम	उप–केन्द्र का नाम	जोडी गई	लागत (रु लाखो में)	चालू होने की तिथि	जिला का नाम
I	**220 के वी**				
	चीका	100 एम वी ए	1411	29.07.2003	कैथल
	टेपला	116 एम वी ए	1624	03.10.2003	अम्बाला
	योग (I)	**216 एम वी ए**	**3035**		

II	**132 के वी**				
	अहेरवान	66 एम वी ए	966	14.05.2003	फतेहाबाद
	हरसानाकलां	16 एम वी ए	603	04.06.2003	सोनीपत
	कंगथली	32 एम वी ए	507	09.06.2003	कैथल
	पाडला	32 एम वी ए	740	25.06.2003	कैथल
	ऐलनाबाद	16 एम वी ए	447	23.07.2003	सिरसा
	मतलौडा	16 एम वी ए	647	24.07.2003	पानीपत
	भागल	16 एम वी ए	515	25.08.2003	कैथल
	खरखौदा	16 एम वी ए	484	29.08.2003	सोनीपत
	चाकुलदाना	32 एम वी ए	616	08.09.2003	कैथल
	लोहारु	26.3 एम वी ए	499	26.11.2003	सिरसा
	ओढान	16 एम वी ए	490	31.12.2003	भिवानी
	योग (II)	**284.3 एम वी ए**	**6514**		

III	**66 के वी**				

	मुलाना	8 एम वी ए	215	30.10.2002	गुडगांव
	कालका	16 एम वी ए	274	01.05.2002	फरीदाबाद
	योग (III)	**24 एम वी ए**	**489**		

IV	**33 के वी**				
	खेवडा	8 एम वी ए	114	04.06.2003	सोनीपत
	मुरथली	8 एम वी ए	93	12.06.2003	कुरुक्षेत्र
	नेसी	8एम वी ए	88	12.06.2003	कुरुक्षेत्र
	क्योडक	8 एम वी ए	97	17.06.2003	कैथल
	दरीयापुर	8 एम वी ए	125	25.06.2003	फतेहाबाद
	मंजूरा	8 एम वी ए	87	10.07.2003	करनाल
	साधनवास	5 एम वी ए	78	21.07.2003	फतेहाबाद
	कुतानी रोड	16 एम वी ए	123	10.08.2003	पानीपत
	पाडा	8 एम वी ए	118	28.08.2003	करनाल

	सीवाह	8 एम वी ए	77	16.10.2003	पानीपत
	बरवाला रोड, हांसी	8 एम वी ए	85	03.11.2003	हिसार
	सिसाय	8 एम वी ए	90	19.11.2003	हिसार
	रसूलपूर खेडी	8 एम वी ए	85	21.11.2003	सिरसा
	जेरपुर	8 एम वी ए	110	25.11.2003	महेन्द्रगढ
	योग (IV)	**117 एम वी ए**	**1370**		
	योग (I to IV)	**641.3 एम वी ए**	**11408**		

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, हमारा फरीदाबाद जिला हरियाणा का सबसे ज्यादा हैवी जनसंख्या वाला जिला है अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज भी फरीदाबाद के अंदर है और गावों मे लोगो को सब–स्टे ान सही न होने की वजह से बिजली पर्याप्त मात्रा मे नही मिलती और ओवरलोड होने की वजह से कई दफा ज्यादा बिजली आती है जिससे टेलीविजन, फ्रिज और अन्य म ाीने है उनको खराब कर देती है। एक तो मै अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि फरीदाबाद मे क्षमता के मुताबिक जितने सब–स्टे ान होने चाहिए वह क्यों नही

लगाए जा रहे है दूसरे जो सब–स्टे ान लगाए गए है उनकी जो कॉस्ट बताई है अगर आंकडो से देखें तो 2002–03 मे 30 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैऔर उनकी कास्ट 98.62 करोड है और 2003–04 मे 58 ट्रांसफार्मर लगए गए है उनकी कास्ट 114.08 करोड है तो क्या माजरा साहब यह बतायेंगे कि जो ये ट्रांसफार्मर हरियाणा मे लगाए जा रहे है हमारी इनफर्मे ान के मुताबिक जो कास्ट इन सब–स्टे ानो पर आती है सही मायनो मे इतनी कास्ट नही आती है। यह जो भारी मात्रा मे बिना जरुरत के धन खर्च किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है जबकि ये कम कीमत पर लगाए जा सकते हैं

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, पहला प्र न तो माननीय सदस्य ने यह किया है कि जिला फरीदाबाद मे आव यकता के मुताबिक सब–स्टे ंज क्यों नही लगाये गये है? स्पीकर सर, आव यकता के मुताबिक ही सब–स्टे ान लगाये हैं पहला उप–केन्द्र पाला मे 220 के वी का जो 3–2–2000 को कमी ान हुआ, इसी प्रकार से 66 के वी का उप–केन्द्र सैक्टर 46 फरीदाबाद मे 15 एम वी ए की क्षमता का लगाया है जो 28–4–2001 को कमी ान हुआ और जिस पर 322 लाख रुपये खर्च आया। 66 के वी का उप–केन्द्र एन एच 3 फरीदाबाद मे लगाया है जो 3–6–2001 को कमी ान हुआ और जिस पर 416 लाख रुपये का खर्च आया। 66 के वी का उप–केन्द्र सैक्टर 31 फरीदाबाद मे लगाया हैजो 31–10–2001 को कमी ान हुआ ओर

जिस पर 225 लाा रुपये का खर्च आया। इसी प्रकार से 66 के वी का सब–स्टे ान छायसा मे 1–12–2001 को कमी ान हुआ और 66 के वी का सब–स्टे ान अलेवा मे 20–1–2001 को कमी ान हुआ जिस पर 462 लाख रुपये खर्च आया। इसी बात को मददेनजर रखते हुए कि वहां की जनता को बिजली की और जरुरत है तो 2004705 मे 351 करोड रुपये की लागत से जो संयंत्र लगायेगे उससे भी फरीदाबाद को बिजली और मिलेगी। 220 के वी का पाली मे, 66 के वी का हसनपुर मे, 66 के वी का बगोल में, 66 के वी का पुन्हाना में, 66 के वी का भोपानी में और 66 के वी का फतेहपुर बिलोच मे यह सब–स्टे ान 2004–05 तक लग जायेंगे, जिसके बाद किसी प्रकार की कोई समस्या नही रहेगी। जहां तक 33 के वी, 66, 132, 220 के वी के सब–स्टे ांज पर ज्यादा खर्च कराने की माननीय सदस्य बात कर रहे है, स्पीकर सर, मै पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि बिड मांगी जा रही है और पूरी पारदि ाता बरती जा रही है और इस बारे मे किसी प्रकार की कोई ि ाकायत नही है। सारे काम में पूरी पारदि ाता अपनाई गई है।

श्री भगवान सहाय रावतः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आज के जमाने मे बिजली एक महत्वपूर्ण और आव यकता का प्र न है और इससे पहले प्र न संख्या 1731 जो माननीय दस्य श्री नफे सिंह जुण्डला जी द्वारा पूछा गया था और बिजली के उत्पादन के

बारे मे था और प्र न संख्या 1635 जो श्री कर्ण सिंह दलाल जी ने पूछा है वह वितरण के बारे में है। ये दोनो ही प्र न बहुत महत्वपूर्ण है। मै इन प्र नो की आरे माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्शित करता चाहूंगा। क्योंकि सन् 1987 मे जब चौधरी देवी लाल जी की सरकार थी उस समय सरकार लोगो को 24 घंटे बिजली देती थी और आव यकता पडी तो अब सातवीं और आठवी यूनिट पूरी होने के बाद यह सरकार जनता को 24 घंटे बिजली देने में सक्षम हो जाएगी। दुर्भाग्य है कि पिछली सरकारो ने40 वर्शो के दौरान इस बारे मे कोई प्रयास नही किए जबकि हिमाचल प्रदे ा आज अकेला सारे प्रदे ा को बिजली देने मे सक्षम हो गया है और राजस्थान का मरुस्थल भी अपने आप मे बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। मै माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस बारे मे सरकार ने क्या कदम उठाये है और क्या हरियाणा प्रदे ा भी कभी बिजली के क्षेत्र मे आत्मनिर्भर हो पायेगा और हम जनता को 24 घंटे बिजली का वितरण कर सकेंगे। इस बारे मे सरकार को क्या योजना है?

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, जैसा कि पहले प्र न के जवाब मे जो कि श्री नफे हि जुण्डला जी ने किया था तब मैने बताया था कि सातवीं और आठवीं यूनिट 2004–05 तक पूरी हो जायेगी जिनमे 500 मैगावाट अतिरिक्त बिजली इस प्रदे ा को मिलेगी। इसके अलावा जो दूसरी यूनिटस भी जो अधुरी रह गई थी उनको यह सरकार आने के बाद पिछले चार सालो मे पूरा

किया है और यमुनानगर का हाईडल प्रोजैक्ट पूरा हो गया है और उससे भी हमें बिजली मिलेगी और पूरे हरियाणा मे बिजली निरंतर सप्लाई की जायेगी ओर जनता को इससे अत्यधिक बिजली मिलेगी।

Construction of Bye-pass in Sonipat

***1610. Sh. Dev Raj Dewan:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bye-pass in Sonipat City which is to be linked to Bahalgarh road passing through over-bridge across Rathdhana Road Chowk: and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा):

(क) तथा (ख) हॉ, श्रीमान् जी यह कार्य पहले ही कार्यन्वित है और अगले तीन महीनो मे पूरा होने की संभावना है।

श्री देवराज दीवान: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वहां पर कई महीनो से काम बन्द है। इस बारे मे जब माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत हमारे वहां आये थे तब उनको बताया था। वहां पर जल्दी से काम भाुरु करवाया जाये ताकि भाहर के लोगो को दिक्कत न हो।

श्री राम पाल माजराः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैने अपने जवाब मे बताया है कि वहा ंपर बाईपास का काम तीन महीने मे पूरा हो जायेगा। इसके लिए तिथि निर्धारित की हुई है यह का टाइम बाउंड है।

तारांकित प्र न संख्या 1624

(यह प्र न पूछा नही गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री कंवरपाल सदन मे उपस्थित नही थे)

Repair of Bhagvi Road

***1648. Ch. Jagjit Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the main road of Village Bhagvi, Tehsil Charkhi Dadri, District Bhiwani has been damaged badly; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the said road?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा):

(क) हां श्रीमान् जी।

(ख) हो श्रीमान् जी।

चौ0 जगजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह काम कब तक पूरा होगा, क्या इसके लिए कोई तिथि निर्धारित की गई है, क्या इसको टाइम

बाउंड किया गया है। क्या यह सडक इसी 31मार्च तक बनाई जाएगी या अगले 31 मार्च 2004–05 तक बनाई जाएगी?

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इसका जवाब हमने हां मे दिया है इसके लिए निर्धारित समय नही रखा गया है। लेकिन मै इनको बताना चाहूंगा कि कन्क्रीट की सउके जहां भी बनाई जाती है वे 2004–05 मे पूरी कर दी जायेंगी।

डा0 रघुबीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से माजरा साहब से जानना चाहूंगा कि क्या इनकी नालेज मे बेरी हलके की ऐसी सडके है जिन पर बनने के बाद रिपेयर नही हुई है। अध्यक्ष महोदय, 1995 मे जब बाढ आई थी उसके बाद बेरी हलके की बहुत सी सडको पर रिपेयर का काम नही हुआ है। कुछ सडको का नाम मै बताना चाहूंगा जैसे डीघल से कलावट, बेरी से बसीन, बेरी से पलडा और बेरी से सेरिया आदि सडके बनने के बाद इन पर रिपेयर का काम नही हुआ है। इस समय ये खराब हालत में है।

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, प्लीज आप बैठे। इन सडको को जिक आपने बजट पर बोलते हुए भी किया था।

मुख्यमंत्री (श्री औम प्रका ा चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मै डा. साहब की इस बात की सराहना करुंगा कि ये आपके obedient student बन गये है ओर एक बार कहने पर ही आपकी

बात मान ली है। अध्यक्ष महोदय, मै इनको बताना चाहूंगा कि जहां तक बेरी की सडको का ताल्लुक है केवल बेरी ही नही बल्कि हमारी सरकार इस बात के लिए पूर्ण रुप से वचनबद्ध है कि पूरे प्रदे ा की सडको को जल्दी से जल्दी मरम्मत की जायेगी और हमारे प्रदे ा की सडको की हालत ऐसी होगी कि इन पर हवाई जहात को भी उतारा जा सकेगा।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, मै बेरी हलके के बारे मे कादियान साहब को बताना चाहूंगा कि जब चौधरी भजन लाल जी की सरकार पांच साल तक रही तब बेरी हलके मे एक पैसा भी सडको पर खर्च नही किया गया। इसी तरह चौधरी बंसी लाल जी की भी साढे तीन साल तक सरकार रही लेकिन बेरी हलके मे सडको के लिए एक पैसा भी खर्च नही किया गया लेकिन हमारी सरकार के चार साल के भाासन काल मे बेरी हलके मे 1.8 करोड रुपया सडको की रिपेयर पर खर्च किया जा चुका है और यह पैसा मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से खर्च किया गया है।

तारांकित प्र न संख्या 1649

(यह प्र न पूछा नही गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री तेजवीर सिंह सदन मे उपस्थित नही थे)

Commissoning of Grid Sub-stations

***1729 Sh. Balbir Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of new Grid Sub-station Commissioned during the period from 1-8-1999 up till now, in comparison to the period from March, 1991 to April, 1996 and May, 1996 to July, 1999?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा): वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान दिनांक 24–07–1999 से 31–01–2004 तक 71 नए ग्रिड उप–केन्द्र चालू किए गए है।

मार्च 1991 से अप्रैल 1996 तक की अवधि के दौरान 69 नए उप–केन्द्र निर्मित किए गए और मई 1996 से जुलाई 1999 के दौरान 34 नए उप–केन्द्र निर्मित किए गए है।

Shortage of Drinking Water

***1674 Smt. Anita Yadav:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of the fact that there is acute shortage of drinking water in the villages of Kosli station, Jhanswa, Mohanbadi, Khanpur Kalan, Niokheri, Mundahera in Salhawas constituency; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to meet out the shortage of drinking water of the said villages?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा):

(क) नही, श्रीमान् जी। गांव कोसली स्टे ान, झांसवा, मोहनबाडी, नीलोखेडी तथा मुडाहेडा मे पेयजल स्तर 70 लीटर

प्रति व्यक्ति देनिक है, जबकि गांव खानपुर कला मे पेयजल स्तर 40 लिटर प्रति व्यक्ति दैनिक है।

(ख) सवाल ही नही उठता।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण अब प्र न काल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र न के लिखित उतर

Construction of Bridges on Kutcha Tracks on Gatauli Karela Drain

***1719. Sh. Sher Singh;** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct bridges on Gatauli Karela Drain at various kutcha track locations to facilitate the movement of farmers of villages:-

(i) Ghadwali;

(ii) Bhakta Khera; and

(iii) Karela-Jhamola;

if so, the details thereof?

मुख्य मंत्री (श्री औम प्रका ा चौटाला):

(i) हां श्रीमान जी।

(ii) नही, श्रीमान् जी।

(iii) हां, श्रीमान् जी।

गतौली करेला ड्रेन पर एक गांव से दूसरे गांव को जाने वाले 9 कच्चे रास्ते और इन गावों के 9 खेतो के रास्ते है।

एक गांव से दूसरे गाव को जाने वाले 9 कच्चे रास्तो मे से 6 रास्तो पर पहले ही पुल बनाये हुए है, 2 पुल जो गांव करेला व घुडवाली के लिए है, के निर्माण हंतु प्र ाासनिक स्वीकृति पहले ही प्रदान की जा चुकी है और निर्माण कार्य भीध्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा। एक पुल का निर्माण सरकारी नीति के अनुसार योग्य नही पाया गया है।

खेतो के 9 कच्चे रास्तो मे से 2 कच्चे रास्तो पर पहले से ही पुल का निर्माण किया हुआ है और भोश 7 कच्चे रास्तो पर पुल का निर्माण सरकारी नीति के अनुसार योग्य नही पाया गया है।

National Programme for Education for Girls

***1758. Sh. Ramesh Kumar Khatak:** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether the national programme for education of girls has been startes in the State at elementary level, if so, the details thereof?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (चौ0 बहादुर सिंह): जी हां।

राज्य के 10 जिलो के भौक्षिक दुश्टी से पिछडे 38 खंडो को इस कार्यकम के अंतर्गत लिया गया है।

भारत सरकार ने चालू वर्श के लिए जनवरी 2004 मे 1. 09 करोड की योजना अनुमोदित की है।

Roads constructed in Badhra Constituency

***1701. Sh. Ranbir Singh:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the new roads, constructed in kilometers in Badhra Constituency during the last foru years?

कृशि मंत्री (स0 जसन्द्रिर सिह संधु): गत चार वर्शो (24.07.199से 31.12.2003) के दौरान बाढडा निर्वाचन क्षेत्र मे 5. 646 किलोमीटर लम्बाई की चार नईसडके निर्मित की गई है।

अतारांकित प्र न एवं उतर

Selectin of Lecturers by Haryana Public Service Commission

***186. Sh. Karan Singh Dalal:** Will the Chief Minister be pleased to state the detail of lecturers selected by Haryana Service Commission in various subjects durint the year 2001-2001 and 2002-2003.

मुख्य मंत्री (श्री औम प्रका ा चौटाला): हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा वर्श 2001–02 और वर्श 2002–03 मे विभिन्न विशयो के प्राध्यापको के चयन से संबंधित सूचना कम ाः अनुबन्ध 'क' और 'ख' मे सदन के पटल पर रखी जाती है।

अनुबन्ध 'क'

हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा वर्श 2001–02 मे प्राध्यापको (कालेज काडर) के पदो की स्फिारि ाो का विवरण

वर्गवार रिक्तियो का विवरण								वर्गवार सिफारि ाो का विवरण						
य	सामा	अनुजाए	अनुजाबी	पिछडी जाति	भूपूसै	विकलांग	योग	सामा	अनुजाए	अनुजाबी	पिछडी जाति	भूपूसै	विकलांग	योग
बी	4	1					5	4	1					5
ज्य	23	4	4	4	2	1	38	23	4	4	4	2	1	38
ूटर न	3	2	2	2	1		20	13						13
विज्ञान	4	1					5	4	1					5
न	4	1					5	4	1					5
जी	48	8	7	8	4	2	77	48	3	3	8	4	2	68
ल	32	5	5	5	2	1	50	32	5	5	5	2	1	50
तिक	8	1	1	1	1		12	8	1	1	1	1		12

न														
ास	34	6	5	6	3	2	56	34	6	5	6	2	1	54
रिक ा	13	2	2	2	1		20	13	2	2	2	1		20
	2						2	2						2
ासन														
ज न	7	1	1				9	7	1	1				9
	192	**32**	**27**	**28**	**14**	**6**	**299**	**192**	**25**	**21**	**26**	**12**	**5**	**281**

अनुबन्ध 'ख'

हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा वर्श 2001–02 मे प्राध्यापको (कालेज काडर) के पदो की स्फिारि ाो का विवरण

वर्गवार रिक्तियो का विवरण								वर्गवार सिफारि ाो का विवरण						
य	सामा	अनुजाए	अनुजाबी	पिछडी जाति	भूपूसै	विकलांग	योग	सामा	अनुजाए	अनुजाबी	पिछडी जाति	भूपूसै	विकलांग	योग
ृत	4	2	2				8	4	2	2				8
ल	10	2	1	2	1		16	10	2	1	2			15
त्र	3	1	1				5	3	1	1				5
त	5	7	7				19	5		1				6
पति न	6	2	2				10	6	1	2				9
विज्ञान	10	4	3	2	1		20	10	2	2	2			16
न	2	1					3	2	1					3

त्र														
जी	28	13	13	4	2	1	61	28	1	4	4		1	38
न	7	1	1	1			10	7			1			8
न		1	1				2		1					1
हास		1	1				2		1	1				2
नैतिक न		2	1				3		2	1				3
क न		1	1				2			1				1
	75	**38**	**34**	**9**	**4**	**1**	**161**	**75**	**14**	**16**	**9**		**1**	**115**

अध्यक्ष द्वारा घोशणा

Mr. Speaker: I read out the following directive dated 29th July, 2003 from the Preseident of India received through the Secretary to Governor of Haryana Chandigarh:-

Directive by the President of India

"I A.P.J Abdul Kalam, President of India, having considered the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1996, which was reserved for my consideration under the provisions of Article 200 of the Constitution of India, do hereby direct, in pursuance of the provisio to Article 201 of the Constitution, that the Bill be returned to the Legislative os State of Haryana, together with a message to re-consider it and incorporate the following in the Bill:-

No persons shall erect or re-erect any building or make or extend any excavation or lay out any means of access to a road within 30 meters on either side of the road reservation of a bye-pass or any scheduled road, provided that in case of National Highways the minimum distance from centre of the road reservation upto the point of erecting or re-reecting an building or making or extending any excavation or laying out by any means or access shall not be less than 60 meters." **ध्यानाकर्शण प्रस्तावो की सूचनाएं**

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडडाः स्पीकर साहब, मैने और डाक्टर रघुबीर सिंह कादियान ने एक काल अटैं ान मो ान रिगर्डिग

मिसिंग आफ श्री कर्ण सिल दलाल सरपंच, विपेज महरावन, डिस्टिक्ट रोहतक के बारे मे दिया था, उसका क्या फेट है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आपका यह काल अटैं ान मो ान मुझे मिल गया है और वह अंडर कंसीड्रे ान है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरा एक काल अटैं ान मो ान रिगार्डिग बर्थ एण्ड डैथस आफ न्यू बोर्न बेबीज इन हरियाणा के बारे में था। उसका क्या हुआ है? (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप बैठिए, वह अभी अंडर कंसीड्रे ान है।

श्री कर्ण सिंह दलालः मेरा भी एक काल अटैं ान मो ान रिगार्डिग बर्थ एण्ड डैथस आफ न्यू बोर्न बेबीज इन हरियाणा के बारे में था। उसका क्या फेट है?

श्री अध्यक्षः आपका वह मो ान अंडर कंसीड्रे ान है। (ाोर एवं विघ्न) आप सभी बैठिए।

श्री भाादी लाल बतराः स्पीकर सर, मैने भी आपकी सेवा मे एक मो ान दिया था। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः बतरा जी, आप बैठिए। आपने लिखकर कुछ नही दे रखा। (शोर एवं विघ्न)जबानी कुछ नही चला करता। आपने जो देना है लिख कर दें। अब आप बैठ जाएं।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, **********

श्री अध्यक्षः आप बैठिए। (शोर एवं विघ्न) कैप्टन साहब की कोई बात रिकार्ड न की जाए। (शोर एवं विघ्न)

श्री भाादी लाल बतराः अध्यक्ष महोदय, मै आपकी रुलिंग चाहता हूं। (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः रुलिंग की कोई बात नही है जब कोई इ ू उठाएंगे तो मै अपना जवाब दूंगा। बतरा जी आपने कोई इ ू के बारे मे लिखकर ही नही दिया हुआ तो फिर आपके पूछने का कोई सवाल ही पैदा नही होता। (विघ्न एवं भाोर) कोई भी बात जुबानी नही होती है। जब तक कोई लिखकर नही देगा मुझे क्या मालुम कि वह क्या इन्फर्मे ान चाहता है? जिन दो मैम्बर्ज ने लिखकर दिया था उन्होने उसके बारे मे जानकारी चाही है और वह मैने उनको बता दिया है। (शोर एवं विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मै आपकी प्रोटैक ान चाहता हूं आप इन माननीय सदस्यो को बिठाएं। जब ये बैठेंगे तभी बोलूंगा।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, आप बैठें।

डा0 रघुबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, **********

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, आप बैठें। कादियान साहब की कोई भी बात रिकार्ड न करे।

श्री कर्ण सिह दलालः अध्यक्ष महोदय, मै तो बोलने के लिए खडा हूं लेकिन जब तक ये नही बैठेंगे मै कैसे बोलूंगा? आपसे निवेदन है कि आप इन लोगो को बैठाएं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप सभी लोग अपनी अपनी सीटो पर बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मै एक बात कहना चाहतां हमं कि ट्रिब्यून मे यह खबर छपी है और इसके बारे मे मैने एक कालिंग अटें ान मो ान आपकी सेवा मे दिया है आप उसको भी कल के लिए एडमिट करने की मेहरबानी करे।

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव

हरियाणा राज्य मे तथा वि ोशकर फरीदाबाद मे मुहं तथा खुर की बीमारी फैलने संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a calling attention notice from Sarvshri Karan Singh Dalal and Jagjit singh, MLAs regarding a disease of mouth and foot in cattle is spreading in the district Faridabad in particular and in the State of Haryana in general. I admit it. Now, Shri Karan Singh Dalal may read his notice.

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, मै इस महान सदन का ध्यान लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि आमतौर पर हरियाणा राज्य मे तथ वि ोशकर जिला फरीदाबाद मे प ुाओ में मुहं तथा खुर की बीमारी फैल रही है। इसके

परिणामस्वरुप सैंक्उो प ा पर रहे है तथा प ा पालन विभाग इस संबंध मे कुछ नही कर रहा हैं।

इसलिए वे सरकार से निवेदन करते है कि वह इस संबंध मे सदन के पटल पर एक वक्तव्य दे।

वक्तव्य

उपरोक्त ध्यानाकर्शण संबधंी

Mr. Speaker: Now, a Minister will make a statement.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा): श्रीमान् जी।

राज्य की अर्थव्यवस्था मे प ाुधन के योगदान के व्याख्यान की आव यकता नही है। हरियाणा को वि व प्रसिद्ध मुर्राह नस्ल की भैंसो एवं देसी नस्ल की गायो 'साहीवाल' व 'हरियाना' का घर होने पर गर्व है और इसे भारत के दुध के भंडार के रुप मे ही जाना जाता है।

राज्य के अस्तित्व मे आने के बाद दुग्ध उत्पादन मे अत्यंत वृद्ध हुई हैं राश्ट्रीय दुध उपलब्धता 226 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की तुलना मे राज्य मे प्रति व्यक्ति 656 ग्राम है और यह पंजाब के बाद दे ा मे उच्चतम है। यद्यपि प्रगति उल्लेखनीय है, फिर भी सुधार की संभावना हमे ाा बनी रहती है और इसलिए

राजय सरकार ने प ाुधन उत्पादन मे निरंतर वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए है।

यह कहना अनुचित है कि मुह खुर बीामरी के कारण राज्य मे आम तौर पर और जिला फरीदाबाद मे विशेश रुप से प ाु मर रहे है। निस्सन्देह हम मुह खुर की बीमारी से मुक्त नही है और यही कारण है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए हरियाणा राज्य ही भाायद प्रथम राज्य था जिसने इस दि ाा मे एक विस्तृत प्रस्ताव बना कर प्रभावी कदम उठाये जो कि न केवल राज्य के लिए ही अपितु पूरे दे ा के लिए महत्वपूर्ण है। हमे यह बताते हुए अति हर्श होता है कि प ाुपालन एवं डेयरिंग विभाग के इस प्रस्ताव के आधार पर ही प्प ाुपालन एवं डेयरिंग विभाग, भारत सरकार ने अन्ततः "FMD-CP" (मुह खुर बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम) को अनुमोदित किया जो कि पूरे दे ा के लिए अनुमोदित कुल 54 जिलो में से, आरम्भिक चरण मे राज्य के आठ जिलो जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, रोहतक और सोनीपत मे कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का भाुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिला भिवानी मे तो ााम से 23–1–2004 को किया गया था और इसका प्रथम चरण पूर्ण होने जा रहा है और इस कार्यक्रम हंतु गठित की गई 400 टीमें चौबीस घन्टे कार्य करती रहती है। मुझे यह बताते हुए और भी हर्श होता है कि बाकी 11 जिलो के लिए भी राज्य सरकार एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसे भारत सरकार द्वारा

अनुमोदित किया जा चुका है और वह कार्यक्रम भीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जागरुकतर अभियान चलाया गया। सारे कार्यक्रम पर वर्तमान विता वर्श मे लगभग 12 करोड रुपये की रा ि ा व्यय होनी सम्भावित है, कार्यक्रम दसवी ंपंचवर्शीय योजना मे भी जारी रहेगा।

संक्षेप मे, यही नही, प ा उत्पादकता को बढावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ अन्य कार्यक्रम भी चलाये जा रहे है जो निम्न अनुसार हैः–

1. हरियाणा प ा चिकित्सा टीका संस्थान, हिसार को पी पी आर टीके के उत्पादन हेतु पूरे दे ा के छ केन्द्रो मे से एक के रुप मे अनुमोदित किया गया है।

2. वर्श 2002–03 मे सूखे के प्रभावो से निपटने के लिएसम्पूर्ण राज्य मे 9184वि ोश स्वास्थय सुधर कैम्पो का आयेाजन किया गया जिसका इस माननीय सदन मे भारी स्वागत किया गया था।

3. जिला अस्पतालो को चरणबद्ध रुप से पोलीक्लीनिक मे बदलने के लिए एक योजना नाबार्ड के विचाराधीन है।

4. एक विस्तृत प्रभावी स्वास्थ्या कार्यक्रम, जिसमे बांझपन प्रबंधन भी भामिल है, 2500 गावों वि ोशकर जिनमे प ा संस्थानए नही है, मे भीध्र ही चलाया जाएगा।

5. राज्य मे मुर्राह जर्मप्लाजम को बढावा देने के लिए 321.00 लाख रुपये की प्रोत्साहन रा ि ा पिछले तीन सालो के दौरान दी गई हैं

6. राज्य की सभी प ु संस्थाओ मे उतर हिमकृम वीर्य उपलब्ध है।

7. नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भादान को और बढावा देने के लिए राज्य मे काफ रैलीज कम हैल्थ कैम्प का एक वि ोश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस वित वर्श के अंत तक ऐसी 200 काफ रैलियां लगाई जाएंगी।

8. वर्श 2001–02 से अब तक 547.71 लाख रुपये की रा ि ा गौ ाालाओ को वित्तीय सहायता के रुप मे प्रदान की गई है।

9. हरियाणा प ुधन बीमा सुविधा प्रदान करने वाला दे ा का प्रथम राज्य है जहां 50% प्रीमियम राज्य द्वारा वहन किया जाता है। अब तक 6713 प ुओ का बीमा करवाया जा चुका है।

10. उच्च अनुवां ि ाक गुणवत्ता प्राप्त 353 मुर्राह सांड 2000 रुपये प्रति सांड की रियायती दर पर प्रजनन हेतु ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाये गये है।

11. राश्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड तथा भारतीय ऐग्रो इंडस्टीज जैसी राश्ट्र स्तर की प्रसिद्ध संस्थाओ को 38 मुर्राह झोटे

दिए गये है जो कि तीन वर्श की छोटी सी अवधि मे प्राप्त की गई सफलता के मुह बोलते प्रमाण है।

12 पूरे राज्य मे नई प ु संस्थाओ के खोलने मे महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और कई अन्य विचाराधीन है।

13. 204 प ु चिकित्सक, 358 प ुधन विकास सहायक भर्ती किए गए है। और तो और प ुधन की देखभाल सुनि चत करने के लिए 30 प ु चिकित्सालयो तथा 200 प ु औशधालयो के लिए भी अमला वर्तमान सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, जो कि वर्श 1989–90 तथा 1990–91 से बिना अमले के कार्य कर रही थी।

14. वि व बैंक की सहायता से (जहां पर विभागीय अमले को प्र ि ाक्षित करने के लिए एक वि ोश अभियान चलाया जा रहा है) एक प ु चिकित्सा प्र ि ाक्षण संस्थान हिसार मे स्थापित किया गया है अब तक 1882 विभागीय कर्मचारियो को 5/2001 को इसके अस्तित्त मे आने के बाद प्र ि ाक्षित किया जा चुका है।

15. 2111 महिलाओ को प ुपालन पद्धतियो मे प्र ि ाक्षण देने के लिए 3.88 लाख रुपये की रा ि ा व्यय की गई हैं।

16. इसके अतिरिक्त 93 ि ाक्षित बेरोजगार युवा उघमियो को भी हरियाण प ु चिकित्सा प्र ि ाक्षण संस्थान, हिसार

मे प्र ि ाक्षित किया गया है जिससे वे एक और सफलतापूर्वक अपनी आजीविका अर्जित कर रहे है और दूसरी ओर उन गावों मे जहां कोई प ा चिकित्सा संस्थान नही है, के प ापालको को सेवाएं प्रदान कर रहे है।

17. प ाधन भवन जिसे गत दिनो 2 करोउ रुपये की लागत से बनाया गया है और जिसमे वर्तमान हरियाणा प ाधन विकास बोर्ड एवं प ापालन एवं डेयरिंग विभाग के कार्यालय चल रहे है, के प्रांगण से भीध्र ही एडवांस ट्रेनिंग इन एनिमल ब्रीडिंग मे प्र ि ाक्षण आरम्भ किया जायेगा।

18. विभाग को न केवल मानव संस्थान विकास सुविधाएं प्रदान करके, अपितु भ्रूण स्थानन्तरण तकनीक व उत्म वीर्य उत्पादन के लिए प्रयोग ाालाओ को स्टेट आफ दी आर्ट के रुप मे सुदृढ किया गया है।

19. लगभग 20 करोड रुपये की अनुमानित रा ि ा से बनने वाला एक आधुनिक प ा ाला (Dairy Complex) हिसार मे भीध्र ही कार्यरुप में आ जाएगा।

20. हमारे द्वारा विकसित 'प ाधन नामक एक अद्वितिय ''मैनेजमैंट इन्फरमे ान सिस्टम'' MIS की भारत सरकार द्वारा प्र ासां की गई है तथा इसे पूरे दे ा के लिए एक माडल के रुप मे ंचुना गया है।

21. दाना उत्पादन की गुणवत्ता ओर इसकी किसानो को उपलब्धता के लिए एक वि ोश अभियान चलाया गया है।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, इनको इस बारे मे मालूम है कि यह जो बीमारी प्रदे ा मे फैली हुई है और मै आपके माध्यम से सी पी एस साहब से जानना चाहता हूं कि इस बीमारी के फैलने के क्या कारण है? अगर ये इस बारे मे बता दंगे तो प्रदे ाके किसानो को पता चल जाएगा कि यह बीमारी क्यों फैल रही है और वे उन कारणो को दूर करने का प्रयास करेंगे। इन्होने अभी जो जवाब पढा है उसमे इस बारे मे कोई जिक्र नही किया गया है। इसके अलावा स्वीकर सर, मै आपके माध्यम से यह भ जानना चाहता हूं कि इस बीमारी की वजह से जों प ाु मर गए है, क्या उन प ाुओ के मालिको को यह सरकार कोई अनुदान देने के बारे मे विचार करेगी? स्पीकर सर, आपको भी पता है कि वे किसान गरीब होते है और 40000 रुपये से कम मे आज कोई प ाु नही आता है। इसके साथ वे यह भी बताएकि किस की लापरवाही की वजह से यह बीमारी प्रदे ा में फैली है और इस बीमारी के फैलने के कारणो के बारे मे इन्होने पूरे आंकडे नही दिए है खासकर मेवात और हमारे फरीदाबाद जिले के बारे में। हमारे फरीदाबाद जिले मे जितनी भी नहरे और रजवाहेचलते है उनमे तो वैसे ही बहुत गंदा पानी चलता है इसलिए उनका पानी पीकर भी प ाु बीमार रहते है। अध्यक्ष महोदय, मैने तो इस बारे मे डी सी फरीदाबाद को भी फोन किया था, विभाग के

अधिकारिया`को भी फोन किया और अखबारो मे भी अपना इस बारे मे ब्यान दिया कि यह बीमारी फैली हुई है इसलिए अधिकारियो को गावों मे जाना चाहिए लेकिन इस तरफ ध्यान नही दिया गया।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब आप अपनी सप्लीमैंट्र पूछें।

श्री कर्ण सिंह दलालः सर, मै सप्लीमैंटरी ही पूछ रहा हूं। स्पीकर सर, इनके विभाग के अधिकारियो ने सरकार से मिली हुई दवाईयां उन किसानो और मजदूरो को मुहैया नही करवाई। चूंकि उन लोगो ने अपने घर से पैसा लगाया है और इनके विभाग ने प ाुओ की दवाई और इलाज के लिए किसानो और मजदूरो से पैसे वसूले है तो क्या उन किसानो और गरीब मजदूरो को सरकार अपनी तरफ से अनुदान देने पर विचार करेगी? इसके अलावा मेरी आखिरी सप्लीमैंटरी आपके माध्यम से यह है कि सरकार ने हमारे जिले के लोगो को तो दरकिनार किया ही हुआ है उनकी कोई परवाह नही हो रही है तो क्या हमारे जिले के प ाुओ की तरफ भी इन्होने ध्यान देना बंद कर दिया है क्योंकि जो इस बारे मे स्कीम इन्होने लागू की है जिसका जिक्र इन्होने अभी किया है कि 6 जिलो मे यह स्कीम लागू की गयी है लेकिन इन 6 जिलो मे इन्होने हमारे फरीदाबाद जिले को भाामिल नही किया है जबकि यह बीमारी सबसे ज्यादा फरीदाबाद और मेवात के इलाको में फैली हुई है। इनको हमारे फरीदाबाद जिले को भी इस स्कीम मे भाामिल करना चाहिए था। हमें दुख इस बात का है कि इस

विभाग का मंत्री भी उसी इलाके का रहने वाला है और उसके इलाके मे सबसे ज्यादा यह बीमारी भी है फिर भी वह उस जिले को इस स्कीम मे भाामिल क्यों नही किया गया है? इसलिए मेरा कहना है कि क्या सरकार इस स्कीम के तहत हमारे फरीदाबाद जिले को और जहां जहां पर यह बीमारी फैली है उनको भी इसमे भाामिल करने पर विचार करेगी?

मुख्यमंत्री (श्री औम प्रका ा चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सदन के सम्मानित साथी का ध्यान इस तरफ अवगत करवाना चाहूंगा कि इन्होने जो अपना ध्यानाकर्शण प्रस्ताव पढा हैउसमे इनहोन दो बीमारियां द ार्यी है जबकि ये दो बीमारी नही है। (विघ्न) इन्होने दो बीमारियो कही है जबकि एक ही है। यह मुहखुर की बीमारी है लेकिन इन्होने पढते वक्त मुह और खुर पढा है। ये दो बीमारी नही है एक ही है और सरकार इस मामले मे पूरी तरह से सतर्क है। इसकी पे ा बंदी के लिए 23 तारीख को पूरे प्रदे ा के स्तर पर तो ाम में टीकाकरण की व्यवस्था भाुरु की गयी है सरकार हर प ाु को टीका लगा रही है इसलिए यदि कोई प ाु मरा है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस किसान की लापरवाही हुई। क्योंकि हरियाणा प्रदे ा की सरकार ने तो बीमा स्केल के तहत पहले ही घोशणा की हुई है कि सरकार ने प ाुधन को बचाने के लिए एक बीमा योजना लागू की है जिसमे आधा पैसा सरकार वहन करेगी और आधा पैसा किसान का लगेगा। अध्यक्ष महोदय, हम यह मानकर चलते है कि किसान का

प ा बहुत किमती है क्योंि आज गाय, भैंस और बैल चालीस चालीस या पचास हजार रुपये मे आम बिकते है।हमारा प्रदे ा एक दुध उत्पादक दे ा है। अगर किसान का परिवार बढेगा तो जमीन की जोत घटनी स्वाभाविक है इसलिए जिंदगी की जरुरी अखरजात पूरी करने के लिए हमने प ाधन को बढावा देने के हिसाब से ही एक प ाधन विकास बोर्ड का भी गठन किया हुआ है। हम तो दुधारु प ा को ईनामात भी देते है और अगर कोई बेरी के प ा मेले से जो अच्छा गधा भी बिकता है तो उसकी भी सरकार पूरी देखभाल करती है। समय समय पर अगर कही चूक भी जाते है तो उनको पुनः अवसर प्रदान किया जाता है। इस तरह से सरकार हर वर्ग का पूरा ख्याल करती है। प ाधन इसलिए भी जरुरी है कि आज भारत वि व मे से सबसे बडा दुध उत्पादक दे ा है ओर पूरे भारतवर्श मे जितने भी प्रदे ा है उनमे हरियाणा दूसरे नम्बर पर है इसलिए हम तो चाहते है कि हरियाणा डेनमार्क को भी बीट करे ताकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो और किसान आर्थिक तौर पर समृद्ध हो। यह सरकार की नीति है।

डा0 रघुबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, बेरी में जो गधे बिकते है वह बाहर से आते है इसलिए इनको यह भी तो बताना चाहिए।

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, आपको क्यों इतना असर हो रहा है? मै भी तो यहां बैठा हूं। आप क्यों इ पर परे ाान हो रहे है? (विघ्न)

चौ0 जगतीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस बीमारी मे जिलेवार कितने प ा मरे है ओर हरेक डिस्ट्रिक्ट मे कितने प ा सारे हरियाणा मे मरे है? अकेले मुहंखुर रोग के उपर हरियाणा के अंदर सारे जिलो मे कितने पैसे दवाईयां के उपर खर्च किए है?

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, जहां तक माननीय साथी ने यह जानना चाहा कि यह जो आउटब्रेक हुए इससे कितने प ा मरे। जहां तक जिलेवार बताने की बात है फरीदाबाद जिले मे कोई प ा नही मरा, सिरसा मे कोई नही मरा, फतेहाबाद मे कोई प ा नही मरा। हिसार मे 1 हजारा इफैक्टिड हुए है और 93 की डैथ हुई है। भिवानी जिले में 2003–04 मे आउटब्रेक 6 हुई, 169 इफैक्टिड हुए, कोई डैथ नही हुई। महेन्द्रगढ मे कोई डैथ नही हुई, रिवाडी मे भी कोई डैथ नही हुई। गुडगांव मे 2 आउटब्रेक 45 इफैक्टिड, डैथ कोई नही। फरीदाबाद में 2 आउटब्रेक, 80 प्रभावित हुए, डैथ नही हुई, झज्जर में 4 आउटब्रेक, 23 इफैक्टिड, कोई डैथ नही, रोहतक में 6 आउटब्रेक, 293 इफैक्टिड, डैथ कोई नही। इसी प्रकार से सोनीपत मे कोई डैथ नही, कैथल में 6 आउटब्रेक, 2132 प्रभावित, 28 की डैथ हुई, कुरुक्षेत्र में 2 आउटब्रेक, 24 इफैक्टिड और डैथ कोई नही, अम्बाला में 4 आउटब्रेक, 195 इफैक्टिड और 5 की डैथ हुई और कुल मिलाकर 47 आउटब्रेक, 5276 इफैक्टिड और 126 की डैथ हुई। स्पीकर सर, प्रदे ा मे 1 करोड 10 लाख प ा है आप

मेजरमैंट करें, इसका अंदाजा लगाएं तो यह संख्या नगण्य है। इसमे इतना ही नही माननीय साथी कह रहे थे इनको तो खु ी होना चाहिए कि भिवानी से तो ाम से इस बीमारी की रोकथाम की भुरुआत की गई है। सम्मानित साथी श्री कर्ण सिंह दलाल कह रहे थे कि हमारे जिले को भामिल नही किया गया। मै उनको बताना चाहूंगा कि इसकी अगली योजना मे मंजूरी मिली है। 11 जिलो मे इस योजना को मंजूर कर दिया गया है अब वहां से इस रोग की रोकथम भुरु होगी। मै माननीय सदस्य की जानकारी के लिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प ा मेले लगाए जाते है, लोगो को चिकित्सा दी जाती है और यह प्रोग्राम 3 वर्श तक चलेगा। एक दिन मे यह बीमारी खत्म नही होती है तो ाम से यह बीमारी तीन साल मे खत्म करने का जनआंदोलन चलाया है।

(इस समय श्री राम पाल माजरा ने मुहंखुर बीमारी के बारे मे सदन मे एक पम्फलेट दिखाया)

स्पीकर सर, यह पम्फलेट देखकर खु ी होगी कि इसके अंदर यह दिया हुआ है कि बीमार प ाुओ को 6 महीने के अंतराल मे टीके लगाये जाते है, फिर 9 महीने मे लगाये जाते है और फिर एक साल मे लगाये जाते है। स्पीकर सर, सारे बीमार प ाुओं के लिए बकायदा एक कार्ड दिया गया है ओर इस बारे मे पूरा प्रचारित किया गया है और इस पम्फलेट मे सारी जानकी दी हुई है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप सभी सदस्य अपनी सीटो पर बैठिये। यह पम्फलेट तो मंत्री जी के जवाब का हिस्सा है इसलिए सदन मे दिखाया है। जो मैम्बर बिना इजाजत हाउस मे खडे है उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये।

डा0 रघुबीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, **********

श्री भाादी लाल बतराः स्पीकर सर, **********

कैपटन अजय सिंहः अध्यक्ष महोदय, **********

श्री राम पाल माजराः इसकी वजह से यह पम्फलेट को राश्ट्र स्तर पर भी निकाला गया है। पूरे दे ा मे इस बीमारी से 54 जिले प्रभावित है जिनमे आठ जिले हरियाणा के है। जैसा कि कर्ण सिंह दलाल ने कहा है कि हमारी सरकार ने इस बारे में क्या किया। इस बारे में मै बताना चाहूंगा कि भारत सरकार के एनिमल हस्बैंड्री के कमि नर ने हमें इस बारे मे एक चिटठी लिखी है उसको मै सदन मे पढकर सुना देता हूं:–

"I am glad to inform you that keeping in view the comprehensive functional coverage, simplicity, easy data entry protocol and user-friendly interface of the MIS developed by Haryana, it has been found to be most suitable and, therefore, chosen as a model for replication in the entire country. We appreciate the efforts of your dedicated team responsible for evolving such a beautiful system code named PASHUDHAN."

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मै एक प्र न और पूछना चाहता हूं *********

वाक आउटस

श्री अध्यक्षः आपकी सप्लीमैंट्री हो चुकी है आपको दूसरे प्र न की इजाजत नही है इसलिए अब आप बैठ जाइए। आपका जवाब दिया जा चुका है इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये।

चौ0 जगजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै भी एक प्र न पूछना चाहता हूं। *********

श्री अध्यक्षः आपकी सप्लीमैंट्री भी हो चुकी है दूसरे प्र न की इजाजत नही है आप बैठ जाइए। आपका जवाब दिया जा चुका है। इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने की इजाजत नही दे रहे है इसलिए मे सदन से वाक आउट करता हूं।

(इस समय रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया के एक मात्र सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से वाक आउट कर गये)

चौ0 जगजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, आप मुझे भी बोलने की इजाजत नही दे रहे है इसलिए मै सदन से वाक–आउट करता हूं।

(इस समय राश्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक मात्र सदस्य श्री जगजीत सिंह सदन से वाक आउट कर गये)

विधान सभा समितियो की रिपोर्टस प्रस्तुत करना

(i) अधीनस्थ विधान समिति की 34वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now Vaid Kapoor Chand, Chairperson, Committee on Subordinate Legislation will present the Thirty Fourth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 2003-2004.

वैद्य कपूर चन्द (चेयरपर्सन, अधीनस्थ विधान समिति): अध्यक्ष महोदय, मै वर्श 2003–2004 के लिए अधीनस्थ विधान समिति की 34वी ंरिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूं।

(iI) सरकारी आ वासन समिति की 34वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now Shri Nafe Singh Jundla, a Member of the Committee on Government Assurances, will present the Thirty Fourth Report of the Committee on Government Assurances for the year 2003-2004.

Sh. Nafe Singh Jundla (A Member of the Committee on Government Assurances): Sir, I beg to present the Thirty Fourth Report of the Committee on Government Assurances for the year 2003-2004.

(iii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडे वर्गो के कल्याण के लिए बनी समिति की 28वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now Shri Nishan Singh, Chairperson, Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes will present the Twenty Eighth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Schedules Tribes and Backward Classes for the year 2003-2004.

Sardar Nishan singh (Chairperson, Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes): Sir, i bed to present the Twenty Eighth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Schedules Tribes and Backward Classes for the year 2003-2004.

(iv) लोक लेखा समिति की 56वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now Shri Krishan Lal Panwar, Chairperson, Committee on Public Accounts will present the Fifty Sixth Report of the Committee on Public Accounts for the year 2003-2004 on the Report of the controller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1999 (Civil).

Sh. Krishan Lal Panwar (Chairperson, Committee on Public Accounts): Sir, I beg to present the Fifty Sixth Report of the committee on Public Accounts for the year 2003-2004 on the Report of the Comptoller and Auditor General of India for the year ended 31st March 1999 (Civil).

(v) लोक उपकम समिति की 51वी ंरिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now Shri Rajinder Singh Bisla, Chairperson, Committee on Public Undertakings, will present the Fifty First Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2003-2004 on the Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the years 1998-1999 & 1999-2000 (Commercial).

Shri Rajinder Singh Bisla (Chairperson, Committee on Public Undertakings): Sir, I beg to present the Fifty First Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2003-2004 on the Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the years 1998-1999 & 1999-2000 (Commercial).

(v) प्राकलन समिति की 35वी ंरिपोर्ट

Mr. Speaker: Now Dr. Malik Chand Gambhir, Chairperson of the Committee on Estimates will present the Thirty Fifth Report of the Committeeon Estimates for the year 2003-2004 on the Budget Estimates for the year 2003-2004 (Environment Department).

Dr. Malik Chand Gambhir (Chairperson, Committee on Estimates): Sir, I beg to present the Thirty Fifth Report of the Committee on Estimates for the year 2003-2004 on the Budget Estimate for the year 2003-2004 (Environment Departmet).

वर्श 2004–2005 के लिए बजट पर सामानय चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्षः दिनांक 13–02–2004 को बजट पर काफी लम्बी बहस हुई। मैने सदन मे उपस्थित सभी माननीय सदस्यो को बहस मे भाग लेने का अवसर प्रदान किया। उस दिन हाउस एडजर्न करने से पहले भी माननीय सदस्यो को, जो बोलना चाहे, बोलने के लिए कहा और जब कोई भी सछसय बोलने के लिए तैयार नही था तब हाउस आज तक के लिए एडजर्न कर दिया था और आज माननीय विता मंत्री जी ने बहस का जवाब देना है। अब मै माननीय वित मंत्री जी से प्रार्थना करुंगा कि वे रिप्लाई दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भाादी लाल बतराः अध्यक्ष महोदय, ********** (शोर एवं व्यवधान)

चौ0 भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अब वित्त मंत्री अपना रिप्लाई देंगे। प्लीज आज सभी बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, *********(शोर एवं व्यवधान)

चौ0 भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मांगे राम गुप्ता जी बहुत ही सीनियर मैंबर है और यह वित्त मंत्री भी रहे है। अगर ये बजट पर बोलना चाहते है तो आप इन्हे बोलने के लिए 10 मिनट

का समय दे दें। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इनको 10मिनट का समय बोलने के लिए दिया जाये।

श्री अध्यक्षः चौधरी भजन लाल जी, 13 तारीख को हाउस सवा चार बजे के करीब एडजर्न हुआ था। उस दिन मैने सभी मैंबरो को बोलने के लिए पुरा अवसर दिया था। आपकी तरफ से तीन चार बार बोलने के लिए लिस्ट आई थी। जिस समय हाउस ऐडजर्न हुआ उस समय आपकी तरफ से कोई नही बोलना चाहता था। प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप सभी बैठे।

चौ0 भजन लालः अध्यक्ष महोदय, उस दिन गुप्ता जी बीमार थे इसलिए नही बोले। गुप्ता जी वित्त मंत्री रहे है ये सरकार को अच्छे सुझाव भी देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्लीज, आप सभी बैठें। अब वित मंत्री जी अपना जवाब देंगे।

मुख्यमंत्री (श्री औम प्रका ा चौटाला): अध्यक्ष महोदय, उस दिन चौधरी भजन लाल जी सदन मे नही थे। आपकी तरफ से गुप्ता जी को कहा गया था कि गुप्ता जी आप बोलना चाहते है तो बजट पर बोलें। हम भी यह समझते थे कि गुप्ता जी वितमंत्री रहे हे और अच्छे सुझाव देंगे लेकिन इन्होने बोलने मे असर्थता व्यक्त कर दी थी। अध्यक्ष महोदय, हम तो चौधरी बंसी लाल जी का भी इंतजार कर रहे थे कि उनको भी बोलने का अवसर दिया जायेगा

आज वे हाजरी लगाने के लिए आये थे लेकिन` सदन मे उपस्थित नही है। अध्यक्ष महोदय, आपको समय का भी ध्यान रखना है। जिस समय वित्तमंत्री जी रिप्लाई दे उस समय गुप्ता जी बीच बीच मे सुझाव देंगे। अध्यक्ष महोदय, अब गुप्ता जी वित्तमंत्री थ्रो और हम अपोजी ान मे थे तब हम सदन का समय बचाने के लिए इनको कहते थे कि आप जो बजट पढ रहे है उसे हम बिना पढे ही पढा हुआ मान लेते है और इनको कहते थे कि आप बैठ जाये ताकि सदन का समय बचे।

चौ0 भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इनको बजट पर बोलने के लिए 10मिनट का समय दिया जायेगा तो ये सरकारको अच्छे सुझाव भी देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, गुप्ता जी डिमांडज पर बोल लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडडाः अध्यक्ष महोदय, उस दिन गुप्ता जी का गला खराबथा इसलिए ये नही बोले। मेरा आपसे अनुरोा है कि आज इनको बोलने का अवसर दिया जाए। ये सरकार को अच्छे सुझाव देंगे और इससे प्रदे ा को लाभ होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गुपता जी, आपको कोई प्वायंट आफ आर्डर नही है। आप किस बात के लिए प्वायंट आफ आर्डर कर रहे है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बजट पर बोलने न देना लेकिन प्वायंट आफ आर्डर पर तो बोलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, 13 तारीख को करीब सवा चार बजे तक हाउस चला और आपको बोलने के लिए भ कहा गया लेकिन आप नही बोले। अब आप ग्रांटस पर बोल लेना। प्लीज, आप बैठे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मै आपसे बजट पर बोलने की इजाजत मांग रहा हूं। मै प्वायंट आफ आर्डर पर बोलना चाहता हू।

श्री अध्यक्षः आपका किस बात के लिए प्वायंट आफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि बी ए सी के अनुसार आज के लिए जो प्रोग्राम बना है जो हमे दिया गया है उसके अनुसार आज पहले बजट पर डिस्क ान होगी और उसके बाद वित मंत्री जी की रिप्लाई होगी। यह इस प्रोग्राम मे लिखा हुआ है। इसलिए स्पीकर सर, आपने

भाुक्रवार को बोलने के लिए कहा था लेकिन हमने कहा कि हम नही बोलेंगे।

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, आप डिमांडज पर बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री औम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ये हर डिमांड पर बोल सकेंगे। ये इनका अधिकार है। ये डिमांडज पर बोल लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, हाउस आपने चलाना है। किसने कब बोलना है यह आपने देखना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, हाउस सदन के नेता और विपक्ष के नेता यानि कि सभी सदस्यो से मिलकर चलाया जाता है।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, हाउस तो आपके उसूलो के मुताबिक चलाना चाहिए। बी ए सी की रिपोर्ट मे लिखा हुआ है कि आज पहले बजट पर डिस्क ान होगी उसके बाद वित मंत्री जी रिप्लाई देंगे।

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, आज वित मंत्री जी जो रिप्लाई दंगे वह भ इसी का हिस्सा है। (शोर एवं व्यवधान) वित मंत्री जी जवाब नही देंगे क्या? वह भी डिस्क ान का हिस्सा है। प्लीज आप बैठै। (शोर एवं व्यवधान)

चौ0 भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आप गुप्ता जी को 10 मिनट का समय दे दें, उसके बाद वित मंत्री जी अपना जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, भाुक्रवार को आपसे तीन लिस्टे आई थी और आपके सभी सदस्यो को बोलने का अवसर दिया गया था तथा बाद मे भी पूछा गया था कि और कोई सदस्य आपकी तरफ से बोलना चाहता है तो बोले। प्लीज अब आप बैठें

चौ0 भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह तो आप मांगे राम गुप्ता जी को बजट पर बोलने का समया दे, नही तो हम सदन से वाब आउट करके चले जायंगे। हम विता मंत्री जी की रिप्लाई नही सुनेंगे।

श्री औम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इस बार हमने तय कर लिया है कि इनको जवाब सुनायंगे, बाहर नही जाने देंगे। इसलिए गुप्ता जी को बोलने के लिए समय दे दिया जाये। पहले हम गुप्ता जी को सुनेंगे उसके बाद वित मंत्री जी अपना जवाब देंगे।

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, आपको बजट पर बोलने के लिए पांच मिनट का समय दिया जाता है। आपके बाकी सभी साथी तो भाुक्रवार को बोल चुके है आप उस दिन मौका चूक गये। (शोर एंव व्यवधान) आपने हाउस के पांच सात मिनट खराब कर दिए है।

श्री मंगे राम गुप्तः स्पीकर साहब, मुझे आपसे यह उम्मीद नही थी। मैने कभी भी हाउस का एक मिनट का भी समय बर्बाद नही किया।

श्री अध्यक्षः अब तो अपने 5–7 मिनट खराब कर दिए। मै तो उसी दिन आपको बुलवाना चाहता था चाहे आप उस दिन एक घण्टा बोलते। चलो अब आप बोलिए।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, आदरणीय वित मंत्री जी ने 2004:2005 को जो बजट हाउस मे पे ा किया है उसमे बडे हौंसले से यह बात लिखी कि इसमे कोई टैकस नही लगया गया और बजट को 439 करोड रुपये के घाटे के साथ पे ा कर दिया। वित मंत्री जी ने अपना यह 5वां बजट पे ा किया है। इससे पहले भी 4 बजट जो पे ा किये क्या उनमे कभी हाउस के अंदर कोई टैक्स लगाया गया है। मै जानना चाहता हूं कि क्या पिछले 4 साल के दौरान हरियाणा की जनता पर टैक्स नही लगे। कमाल की बात है, यह जो वैट प्रणाली लागू की गई क्या इससे जनता पर टैक्स नही लगा या इसको आप टैक्स नही मानते। वाटर चार्जिज, सीवरेज चार्जिज, इलैक्ट्रीसिटी चार्जिज, बसो का किराया आदि जो बढाया गया है क्या उससे जनता पर टैक्स नही लगा। (विघ्न)

वित मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): यह तो हमने लोगो को सर्विसिज दी है।

श्री मांगे राम गुप्ताः नो नो दिइस आलसो टैक्सिज (विघ्न)

श्री राम कुमार नगुराः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, जब यह वित मंत्री होता था तो उस वक्त बजट लीक हुआ करता था। या तो यह जीभ काढ कर बात कर ले या बजट पर कोई ठीक बात कर लें। इसके बारे में मेरी बुआ सारी बाते बताया करती है।

श्री मांगे राम गुप्ताः कटवाल साहब, रि तेदारी की तो कुछ लिहाज कर लो। तेरी बुआ फिर तेरे कान खिंचेगी। अध्यक्ष महोदय, पिछले 4 साल के बारे मे वित मंत्री जी ने यह ढिंढोरा पिटा है कि हमने जनता पर कोई बजट मे टैक्स नही लगाये। ये कहते है कि हमने साहब जुटा कर बहुत साधन जुटाए है और आज खजाना लबालब भरा हुआ है और 44 हजार काम कर दिए जो एक रिकार्ड है। हमने इतने काम किए है कि उनका नाम गिनीज बुक मे दर्ज होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इनहोन पहले 4 प्लान पे ा किए, इन्होने बडा जोर मारा और फर्जी आंकडे तैयार करक ाहउस मे रख दिए। प्राप्तियो के इन्होने दो दो हजार करोड रुपये के आंकडे फालतू दिए। (शोर विघ्न) आपने बहुत कोि ा ा की कि आप दो हजार का आंकडा पर कर जाएं। (विघ्न) पहले 2100 का प्लान बनाया फिर पौने 2200 का बनाया। (विघ्न)

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मांगे राम गुप्ता जी ने कहा है कि 2–2 हजार करोड के आंकडे फालतू दिखा रखे है, मै इनकी इस बात का जवाब तो बाद मे दूंगा लेकिन ये यह जरुर बता दे कि किस किस चीज में आंकडे फालतू है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, स्पैसिफिकली और ईयरवाईज बताएं कि कहां कहा पर आंकडे बढा कर दिखाए गए है।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मै प्राप्ति के बारे मे कहा रहा हूं। आपने मुझे पांच मिनट का समय अपनी बात कहने के लिए दिया है अगर आप मुझे मेरी मर्जी से बोलने की छुट दे तो मै सारी बात बताउंगा। यह किताबो का जो पोथा आप देते है यह पांच मिनट मे पढ कर नही सुनाया जा सकता है। बजट तैयार करने मे सरकार को छः महीने का समय लगता है। बजट वैसे थोडे ही बन जाता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः छः महीने तो इनको लगते है आपको तो 15 दिन ही लगते है।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मै यह कह रहा था कि हमने देख लिया इन्होने जोर लगा लिया 2100, 2200 और फिर 2300 करोड का बजट बना लेकिन आप 1700 साढे 1700 सौ करोड से फालतू पैसा खर्च करने के लिए साधनो से जुटा नही सके और अगर प्लान मे ऐसा किया है तो मुझे बताइयें। अध्यक्ष महोदय, विता मंत्री जी ने सारे प्लान मे गलत आंकडे देकर पास

करवाने की कोि ा ा की है और गलत आंकडे हाउस मे दिये है इस तरह से ये आंकडे देकर पास करवाने की कोि ा ा कर रहे है। कर्जा छिपाने के लिए जो कर्जा लिया रिसोर्सिज के लिए कर्जा चुकाने का वह क्या होगा, ये जो रिसोर्सिज मे दिखा रहे है इनकी जो प्राप्तियो है 38.87 हजार करोड स्टेट का खर्च चलाने के लिए कर्जा लेते है। कर्जा छिपाने के लिए जो कर्जा लिया रिसोर्सिज के लिए कर्जा चुकाने का वह क्या होगा? ये जो रिसोर्सिज मे दिखा रहे है कि इनकी प्राप्तियां है 38.87 हजार करोड रुपये कर्जा ले कर वर्श 2004–2005 मे खर्च करेंगे। (**इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए**) उपाध्यक्ष महोदय, 29.58 करोड रुपये का तो कर्जा चुकाएंगे जो ये प्लान मे खर्चा दिखा रहे है। इस प्लान मे 44.24 करोड रुपये इन्होने कर्जा वापिस कर दिया और इनके पास 55ः रिसोस्रिज बकाया रह गए। वित मंत्री महोदय आप कृप्या यह देखना कि इतने कम बजट मे विकास के क्या कार्य होगे। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदे ा को एककृशि प्रधान प्रदे ा कहते है। वित मंत्री महोदय, आप जरा देखना कि आपने सिंचाई पर पिछले साल कितना खर्च किया था क्या इस साल उस खर्च के आपने कुछ कम खर्च नही किया है और इसके साथ ही कृशि के अदायरो मे और कृशि पर आपने पिछले वर्शो के मुकाबले काफी कम पैसा अलाट किया है और इतने कम पैसे मे आप किसान का क्या भला करेंगे। किसान के लिए सिंचाई जरुरी है और उसके बारे मे आप यहां पर बडी बडी बातें करते है और उसमे कितने कम पैसे की अलाटमैंट आपके की है। आप कृशि और सिंचाई के

लिए पूरा पैसा नही जुटा पा रहे है यही कारण है कि आपके प्रदे ा मे अन्न का उत्पादन कम हो रहा है। (विध्न) मे किसी के घर की बात नही कर रहा हूं प्रदे ा मे खाद्याान्न का उत्पादन घट रहा है। (विध्न) उपाध्यक्ष महोदय, मै माननीय वित मंत्री जी से दरखास्त करना चाहता हूं कि चौधरी बंसी लाल जी ने प्रदे ा मे भाराब बन्दी की थी और उससे स्टेट को 1600 करोड रुपये का नुकसान हुआ था लेकिन वह काज अच्छा था इसलिए हरियाणा के लोगो ने उसको बर्दा त कर लिया था। हरियाणा की जनता चिल्लाई, हरियाणा का विरोधी पक्ष चिल्लाया लेकिन मुख्यमी जी ने दो सालो मे हरियाणा का भठठा बैठा दिया और भाराब भी बन्द नही हुई। (विध्न) इसी तरह से मौजुदा सरकार ने वैट लागू किया। सारे हिन्दुस्तान के सीा राज्यो की केनद्र सरकार की अध्यक्षता मे हुई बैठक मे यह फैसला हुआ था कि टैकस के सिस्टम को बदला जाएगा और यह भी बात ाई थी कि सारे हिन्दुस्तान मे एक ही समय मेयह लागू हो। लेकिन वही भाराब बंदी वाली बात की तरह मुख्यमंत्री श्री औम प्रका ा चौटाला जी ने जिद पकड रखी थी, अपने नम्बर बनाने की चिंता थी, इन्होने अपनी जिद मे स्टेट मे वैट प्रणाली भी एक ही स्टेट मे कामायाब नही हो सकती जबकि बाकी स्टेटस भी उसको लागू न करे। लेकिन इन्होने अपनी जिद की वजह से हरियाणा मे लागू कर दी, इन्होने अपनी जिद तो पूरी कर दी लेकिन उससे लाभ क्या हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये पूरी तरह से स्टडी करे तो धान के बेचने मे इनको 2000 करोड रुपये का नुकसान हुआ है। जब तक दूसरे प्रदे ाो मे बराबर का

वैट टैक्स न हो तब तक इसका कोई लाभ नही हो सकता है। (विघ्न) मुख्यमंत्रीह जी इस बारे मे जायजा लेने के लिए गए थे, तो उनका क्या हाल हुआ था। किसानो ने काले झण्डे दिखाए थे और न ही इस बारे थैलियां दी गई थी। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, सारे दे ा मे एक साथ वैट लागू होता तो इसमे कोई दिक्कत नही थी। एक प्रणाली तभी कामयाब होती है जब पूरे दे ा मे वह एक साथ लागू हो। मेरी मुख्यमंत्री जी को यह सलाह है कि अगर वे कांग्रेस वर्ग का और व्यापारी वर्ग का फायदा चाहते है तो ये वैट टैक्स प्रणाल को विदड्रा कर लें। अगर नही विदड्रा करते है तो जिस तरह से बंसी लल जी को सरकार भी छोडनी पडी और भाराब भी बंद नही हुई, वही हालत आपकी न हो जाए।

श्री उपाध्यक्षः गुप्ता जी, आपके 10 मिनट होने वाले है। (विघ्न) जगजीत सिंह जी, आप क्यों सिफारि ा कर रहे है। आपको तो बोलने का समय दिया जा चुका है।गुप्ता जी, आप प्वायंट पर ही बोलें।

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, अब मै उद्योग की बात करना चाहता हूं कि उद्योग लगाने के लिए बहुत इन्फ्रास्ट्रकचर की जरुरत होती है। इसके अलावा सबसे पहले जो जरुरत होती है तो वह प्रदे ा मे अमर और सुख चैन की होती है ताकि प्रदे ा मे ज्यादा से ज्यादा उद्योग लग सके। व्यापारी तो पैसा हरियाणा मे लगाने के लिए तैयार है अगर यह सरकार उसको प्रदे ा मे जान माल की सुरक्षा देने का वायदा करे। आज

उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा से रोज इंडस्ट्री भाग रही है, व्यापारी इंडस्ट्रीज बंद करके हरियाणा से जा रहे है। अब यह सरकार ढिंढोरा पिटती है कि हम हरियाणा मे इतने उद्योग लगा रहे है। उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदे ा मे कीस चीज मे महंगाई कम हुई है, इस बारे मे भी ये बता दें। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः गुप्ता जी, आप दो मिनट मे वाईंड अप करे।

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, आज इनके राज मे यूरिया के खाद का कटटा सवा सौ रुपए से बढकर 250 रुपये हो गया है। (विघ्न) गरीब आदमी के लेने की या खाने की कोई भी चीज हो जैसे चाहे घी हो, गुड हो, भाक्कर हो, चाय हो, लोहा हो, या सीमेंट हो यानी सभी चीजो के दाम बढे है और महंगाई ने गरीब आदमी को मार दिया है। इसी तरह से इनके राम मे बेरोजगारी बढी है क्यांकि नौजवान के पास कोई रोजगार नही है। उपाध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था न हो, बेरोजगारी हो और प्रदे ा मे महंगाई बढ रही हो, कर्जा बढ रहा हो तो यह बडी चिंता की बात है। मुझे तो इसके लिए भार्म आ रही है। साधन है नही तो आप क्या करोगे? किस बात पर आप खु ाी मना रहे हो। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1966 से लेकर 1997तक जब हम सरकार छोडकर गऐ थे, आठ हजारा करोड रुपये का प्रदे ा पर कर्जा था लेकिन आप वह इनके पांच सालो के राज के दौरान 38 हजार करोड रुपये हो गया है। कर्जा ले कर्जा लेकिन इनकी आमदनी तो

है नही जबकि खर्चा इनका बढ रहा है। अगर आज 38 हजार करोड रुपये का कर्जा न हो गया हो तो ये हमें बता दें। जो बैंक गारंटी है या जो लोन देना है क्या वह सब इनकी देनदारी नही है वह कौन देगा?

श्री उपाध्यक्षः गुप्ता जी, अब आप बैठें।

चौ0 भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, तरीके से समाप्त करने के लिए आप उन्हे कम से कम पाच मिनट तो और दे दें।

श्री उपाध्यक्षः गुप्ता जी आप दो मिनट मे वाईंड अप करें

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मै एक ही बात पूछना चाहता हूं। वित मंत्री जी ने घाटे का बजट पे ा किया है और इन्होने अनुमान दे दिया कि अगले साल मे इसको पूरा करने का प्रयास ये करेगे ताकि यह घाटा पूरा हो जाए। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले चार सालो मे इन्होने अपने बजट का घाटा पूरा किया है? इस तरह से ये कब तक घाटा चलायंगे? इनकी कोई भी योजना पूरी क्यों नही हो रही है क्योंकि इनके पास साधन ही नही है। जब साधन होंगे तभी योजनाएं पूरी होंगी। 2100 करोड रुपये के बजट मे भी आप योजना नही बना सके। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की नाकामियां इन्ही बातों मे है।

श्री उपाध्यक्षः मांगे राम जी, आपको बोलने के लिए समय इसलिए दिया गया था ताकि आप कोई नयी चीज बताएंगे,

रिपिटि ान नही करेगे लेकिन आप तो कोई नयी बात नही बता रहे है बल्कि आप तो रिपीट कर रहे है।

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, नयी चीज आप बताएं कि क्या है?

श्री उपाध्यक्षः गुप्ता जी, बात आप कह रहे हैवह तो लगभग सभी सम्मानित सदस्य कह चुके है। इसलिए अगर कोई अलग बात हो तो आप उसको बताएं।

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, अलग बात यह है कि वैट टैक्स खत्म करना चाहिए क्या आप खत्म कर दोगे?

प्रो0 सम्पत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। गुप्ता जी, सुझाव दे रहे है ताकि मै अपना जवाब देते वक्त उन पर गौर कर सकू। मै इनसे जानना चाहूंगा कि वैट टैक्स क्या है और इसके लागू होने के बाद इससे क्या फर्क पडा है क्योंकि ये वाणिज्य परिवार से है और काफी लम्बे समय तक वित्त मंत्री भी रहे है। इसलिए मै इनसे यह जानना चाहूंगा।

श्री मांगे राम गुप्ताः वैट टैक्स यह था कि (विघ्न)

श्री भागी रामः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि अभी हमारी बहन सरिता नारायण मुझे यह बताकर गयी है कि जो जीभ निकालने वाला आदमी होता है वह बहुत खतरनाक होता है।

प्रो0 सम्पत सिंहः डिपटी स्पीकर सर, सरकार ने अभी तक ऐसी कोई प्रणाली लागू नही की है जिसमे कोई वैट हो। यह तो वैट सिस्टम लागू किया है लेकिन ये वैट की बात कर रहे है। यह वैट सिस्टम अलग है तो यह हमें बता दें।

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, यह जो वैट टैक्स है इसका तरीका यह था कि एक दुकानदार जो बाहर से किसी स्टेट से परचेज करके जाएगा और उस पर वे टैक्स लगा देंगे और वह हरियाणा स्टेट मे जाकर बेचेगा ओर उस पर जितना प्रोफिट लेगा वह वैल्यूड ऐड करके वह टैक्स लगाकर इन्होने अपनी स्टेट मे लागू कर दिया और वह दूसरी स्टेटस मे लागू नही हुआ। दूसरी स्टेट मे पूरा टैक्स लगाकर माल आ रहा है यह कंज्यूमर के उपर बडी जबरदस्ती की है, बडा जुल्म किया है।

श्री उपाध्यक्षः गुप्ता जी, अब आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, अरोडा साहब ऐक्सपोर्ट के बारे मे कह रहे है। आज जो जीरी के ऐक्सपोर्टर है, उन्होने सरकार से बार बार रिक्वैस्ट की। बार बार इनसे मिलने डैपुटे ान आए कि इस वैट टैक्स मे हमे बडी प्रौब्लम आ रही है दुकानदान जो कच्चा आढती है जो किसान की जीरी बेचता है। डीलर वैट लगाए बगैर जीरी नही देता। वह तब तक जीरी सेल नही करता जब तक कि 4 परसैंट वैट टैक्स न लगा दिया गया हो

जबकि हिमाचल और पंजाब जैसे पडौसी प्रदे ा मे 4 परसैंट वैट टैक्स नही लगता। इस बात पर उपाध्यक्ष महोदय, हमारा और आपका चैलेंज है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेंन्द्र सिंह हुडडाः उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरुरत नही है हरियाणा के किसान को बासमती का क्या भाव मिला है यह वैट का नतीजा है।

कृशि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सन्धू)ः उपाध्यक्ष महोदय, देवीगढ (पंजाब) की जीरी पेहवा मे आकर बिकती है।

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मै पूरी जिम्मेदारी के साथ हाउस मे अपनी बात कह रहा हूं कि ऐकसपोर्ट ने बहुत प्रयास किये लेकिन रजामंदी नही हो सकी और उनको टैकस की एग्जैंप ान नही मिली उन पर चार परसैंट वैट टैक्स लगाया है। कच्चा आढती तो है वह रिस्क क्यों ले उसे सरकार पर वि वास नही है। ऐक्सपोर्टर कह रहे थे कि दुकानदारो ने यह कहा कि इस सरकार पर वि वास नही है हम चार परसैंट का टैक्स अपने घर से क्यों देंगे इसलिए सबने चार परसैंट लगाकर बेचा जिससे किसान की जीरी 100 रुपये प्रति क्विंटल कम पर बिकी।

श्री उपाध्यक्षः अब आप बैठिए। अब वितमंत्री प्रो0 सम्पत सिंह जवाब देंगे।

प्रो0 सपत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैने 12 फरवरी 2004 को वर्श 2004–05 के बजट अनुमान इस सदन मे प्रस्तुत किए ओर

इस पर माननीय सदस्यो ने मुझे बहुत उम्मीद थी कि चर्चा करेंगे और चर्चा मे बहुत अच्छे सुझाव भी आएंगे। कुछ सदस्यो ने सुझाव दिए भी कुछ ने सराहा भी है और कुछ ने राजनीतिक तौर पर आलोचना करनी थी इसलिए आलोचना की है। बहुत अच्छा होता कि सभी सदस्यो के अच्छे सुझाव आते तो मुझे बहुत खु ी होती और वि ोश तौर पर मांगे राम गुप्ता जी मेरे से बहुत सीनियर रहे है और मुझ से पहले 5 वर्श तक वित्त मंत्री रहे है। मै काफी कोि ा ा करता हूं इनके समयकी बजट स्पीचेज निकालकर कि कही न कही मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री श्री चौटाला जी व स्वयं मै इस बात का दावा नही करते कि हम कोई अर्थ ाास्त्री है, हम कोई स्पे ालिस्ट है। हां इतना दावा जरुर करते है कि व्यवहारिक ज्ञान आपकी मेहरबानी से और चौधरी देवी लाल जी के वि वविधालय से सीखा है और उस व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर आज सरकार मुख्यमंत्री जी चला रहे है और वित्त विभाग का प्रबन्धन मै देख रहा हू और उस व्यवहारिक ज्ञान के कारण मै दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो वित्तीय स्थिती हरियाण प्रदे ा की है, यह मै नही कहता कि सब से अच्छी है लेकिन that is number one in India. यह मै नही कह रहा हूं यह प्लानिंग कमी ान कह रहा है और फाईनैंस कमी ान कह रहा है। मै खुद कहता तो कहते कि अपने मुह से बडाई कर ली। उनकी रिपोर्टस कहती है कि आपके वितीय प्रबंधन की स्थिती सबसे बढिया है। डिप्टी स्पीकर सर, यह बजट अनुमान तैयार करने से पहले आप स्वयं सोच सकते है कि

कितना दिमाग पर बोझ रहा होगा क्योंकि जो फाउंडे ान आपको मिलता है उसी पर आप अपना घर बनाते है, वह चाहे सरकार हो चाहे कोई संस्थान हो, आपको एक बार चार्ज प्रबन्धन जो मिलता है उससे पहले क्या व्यवस्था थी। यह सरकार बनने से पहले क्या स्थिती थी और वित्तीय व्यवस्था की क्या स्थिती थी, यह आपके सामने है ो मुलभूत संरचना थी और प्रदे ा का इन्फ्रास्ट्रक्चर था सारे हरियाण प्रदे ा का, वह आलमोस्ट समाप्त हो गया था। रोडस की कंडी ान चौधरी भजन लाल जी हमारे सामने बैठे है वे बता देंगे कि जब इस सरकार ने सत्ता संभाली थी उस समय क्या थी, नहरो की स्थिती क्या थी? डिप्टी स्पीकर सर, बिजली की स्थिती उस समय क्या थी, ट्रांसपोर्ट और रोडवेज की स्थिती क्या थी, उस समय स्कूलो मे पढने वाले बच्चो के लिए बैठने के लिए जगह नही थी और न ही उनके लिए कमरे थे और न ही उन कमरो के फ र्ा थे उनकी पोजी ान क्या थी? (विघ्न)

चौ0 भजनलालः उपाध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। वित्त मंत्री महोदय, यह भी बता दें कि जब हमारी सरकार थी उस वक्त उत्पादन क्या था और आज उत्पादन कितना है और उस समय खर्चा कितना था और आज खर्चा कितना है?

श्री उपाध्यक्षः कोई सदस्य बीच मे इन्ट्रप ान न करे जो भी सदस्य इजाजत बोल रहे है उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। (विघ्न)

Prof. Sampat Singh: I will respond.

श्री उपाध्यक्षः कोई सदस्य बीच मे इन्ट्र ान न करे सभी सदस्यो को बोलने का मौका दिया जा चुका है जो भी सदस्य बिना इजाजत बोल रहे है उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। (विघ्न)

Prof. Sampat Singh: they have spoken like anything. मेरा सभी माननीय सदस्यो से निवेदन है कि वे बीच मे इन्ट्र ान न करे अगर फिर भी करते है तो करे। मै यह कह रहा था कि अस्पतालो मे डाक्टर नही थे, कौन से विभाग की कहू। इस दे ा मे सबसे ज्यादा जो कन्ट्रीब्यू ान है वह है किसानो का (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः कोई सदस्य रनिंग कोमैन्ट्री न करे।

प्रो0 सम्पत सिंहः इस दे ा मे सबसे ज्यादा जो कन्ट्रब्यू ान है वह है किसानो का, मजदूरो का, सबसे ज्यादा अगर आज किसी को जरुरत है तो सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर जो पिछडे हुए लोग है, उनको जरुरत है। उन लोगो की उस वक्त क्या पोजी ान ीी? चाहे वे ओल्ड ऐज हो, चाहे वे हैंडीकैप हो, चाहे वे बिलो पावर्टी लाईन के लोग हो, चाहे वे विंडोज हो उनकी पोजी ान क्या थी। डिप्टी स्पीकर सर, इसी तरह से यूथ जो नौजवान है उनकी हालत उस समय क्या थी? चौधरी भजन लाल जी और हुडडा साहब जानते है कि वैल आरगेनाइज्ड और वैल प्लान्ड वे मे इन यूथ को एक्स्पलायट किया जाता था और किस बात के लिए किया जाता था चन्द एक लोगो

की जेबें भरने के लिए भाराब माफिया सारे हरियाणा प्रदे ा मे छायर हुआ था।(विध्न) At the helm of affairs जो लोगो के थे वे कमा रहे थे at the cost of youngsters. उन यंगस्टर्स के भविश्य के उपर कमा रहे थे (विघ्न)

श्री राम कि ान फौजीः उपाध्यक्ष महोदय, मै प्वायंट आफ आर्डर पर बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः आप बैठिये। फौजी साहब, आप भले आदमी हो आप इनके चक्कर मे क्यों आ रहे हो।

Prof. Sampat Singhl I have not named anybody. मै कह रहा हूं कि यह हालात थे उन लोगो के उनको ऐक्सप्लायट किया जाता था जबकि यूथ को इनकरेज करना चाहिये उनका उत्साह बढाना चाहिये। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर सर, इस तरह की पोजी ान उस समय थी। अगर वही स्थिती ज्यों की त्यों रह जाती तो पता नही यह प्रदे ा किस दि ाा में जाता। जैसे कई बार कहते है कि जो परमात्मा करता है वह ठीक करता है, अगर कोई कानून की नजरो से बच जाता है तो परमात्मा की नजरो से नही बचता और ऐसा ही हुआ। परमात्मा की नजर से ये लोग नही बचे और इनकी सरकार चली गई। उपाध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार के समय मे डेढ लाख से उपर बच्चो पर केसिज हुए थे, इनके जाने के बाद स्थिती मे सुधार आया है, पूरी तरह से सुधार आने मे समय लगता है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि उस समय

परमात्मा ऐसा नही करता तो पता नही कहां हम जाते और कहां हमारी सोसायटी जाती? उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय मे बच्चो का ही मिसयूज नही हो रहा था बल्कि महिलाओ का भी मिसयूज हो रहा था। उस समय बार्डर के एरियाज में बच्चचो को औरतो को भाराब के बस्ते पकडा दिये जाते थे। उपाध्यक्ष महोदय, अगर 200 या 250 रुपये घर बैठे किसी को मिल जाये और वह लालच मे आ जाए, लालच मे आकर गैर कानूनी काम करे और वह गैर कानूनी काम चला रहे थे ये लोग। यदि ओर लम्बा चल जाता तो पता नही हमारे प्रदे ा का क्या होता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम कि ान फौजीः उपाध्यक्ष महोदय, ******** (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः राम कि ान जी, प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) कैप्टन साहब, प्लाज आप बैठे। (शोर एवं व्यवधान)

चौ0 भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। वित मंत्री जी हमारी तरफ से जो कहा गया है उसका जवाब दें। आधे घंटै के करीब तो इन्होने भाराब पर ही लगा दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः चौधरी साहब, आधा धंटा हो गया क्या?

चौ0 भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, आधा घंटा नही तो 15 मिनट तो हो गये है और 15 मिनट से ये भाराब पर ही बोल रहे है जोकि इररैलेवैंट है।

प्रो0 सम्पत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, ये जिस तरह से लोगो को गुमराह करके गैर कानूनी काम करवा रहे थे यदि उसी तरह वह काम चलता रहता तो अनैतिकता और बढने में देरी नही होती। अगर हम अनैतिकता की तरफ बढ जाते तो यह सारी की सारी सोसायटी खत्म हो जाती। इन हालातो मे हमारी सरकार ने सत्ता संभाली और उसके बाद जिस किस्म के हालात हरियाणा प्रदे ा के बने है वि ोशतौर पर आर्थिक विकास के, ये सबके सामने है। उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा विपक्ष के सभी साथियो से निवेदन करुंगा कि ये बैठे रहे और मेरा जवाब सुनते रहे। सबको जवाब मिलेगा यदि किसी को जवाब नही मिले मेरे से स्लिप हो जाये तो मुझे बता दे सबको जवाब दूंगा। अब चौधरी भजन लाल जी की बात पर आता हूं।

श्री राम कि ान फौजीः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वयांट आफ आर्डर है। (शोर)

श्री उपाध्यक्षः राम कि ान जी जो कह रहे है वह रिकार्ड न किया जाये। राम कि ान जी, प्लीज आप बैठें।

डा0 रघुबीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। वित्त मंत्री जी रिप्लाई दे रहे है और सदन मे न तो स्पीकर सर, उपस्थित है और न ही मुख्यमंत्री जी उपस्थित है। (शोर एवं व्यवधान)

आवाजें: उपाध्यक्ष महोदय, प्वायंट आफ आर्डर पर प्वायंट आफ आर्डर थोडे होता है।

श्री उपाध्यक्षः डा0 साहब, क्या आप चेयर से संतुश्ट नही है। प्लीज आप बैठे। यह कोई तरीका नही है। आप हर बात पर खडे हो जाते है। प्लीज आप बैठें।

डा0 रघुबीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, हम कोई बात कहे तो आप खडे हो जाते है।

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, ********** (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः डा0 साहब, क्या आप डिप्टी स्पीकर से संतुश्ट नही है।

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी जो यह माहौल पैदा करना चाहते है इस बारे मेरी आपके माध्यम से इनसे गुजारि ा है कि विपक्ष के कहने पर अध्यक्ष महोदय ने मांगेराम गुप्ता जी को बोलने का समय दिया। अब वित्त मंत्री जी जवाब दे रहे है ये ध्यान से सुने। चौ0 भजन लाल जी गुप्ता जी और डा0 साहब सब सीनियर मैंबर है और दोबार अपनी बातें कह चुके है वितमंत्री जी जवाब दे रहे है पता नही क्यां इनके पेट मे दर्द होना भ्ाुरु हो गया है। ये मेहरबानी करके सुनने का कश्ट करे।

प्रो0 सम्पत सिंहः डिप्टी स्पीकर सर, मै दुबारा बजट स्पीच का जवाब भाुरु कर रहा हू। (विघ्न) मै यह कह सकता हूं कि यह बजट एक संतुलित बजट है, हर क्षेत्र को बढावा देने वाला बजट है। यह बजट वि ोश करके बिजली, पानी और सडको की जो मूलभूत संरचना होती है उसको पूरा करता है यानि इन चीजो का वि ोशकर ध्यान दसमे दिया गयाहै। औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास और समाजिक क्षेत्रो के बारे मेभी इस बजट मे वि ोश ध्यान दिया गया है इसलिए मै इस बजट को चहुंमुखी बजट कहता हू। डिप्टी स्पीकर सर, आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए क्या क्या मापदण्ड होने चाहिए, उनके बारे मे मै आपको बताना चाहूंगा। इब्राहिम लिंकन जी ने कहा था कि जो लोकतंत्र मे सरकार का मतलब है कि Government of People, for the people and by the people. यही बात चौधरी देवी लाल जी कहा करते कि राजनीति जन सेवा का एक माध्यम है जो कि कमर्ि ायल एक्टिवीटी नही है। सरकार की जितनी भी गतिविधियां होती है उन सब का एक उददे यहोता है कि आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं सरकार जितनी जुटा पाती है। मै कुछ इन्डीकेटर आपके सामने रखना चाहुंगा। पहला इन्डीकेटर होता है कि प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी है, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता कितनी है और इसी तरह से प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता कितनी है, प्रति व्यक्ति दुध कितना उपलब्ध है। प्रति व्यक्ति फल और सब्जी कितनी उपलब्ध है, साक्षरता की दर क्या है, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत क्या है, लॉ एण्ड आर्डर, राजनैतिक

स्थिरता और यूथ एण्ड फैस्टिवल एकस्ट्रा आदि सभी चीजो को ध्यान मे रखकर ही मापदण्ड निर्धारित किए जाते है। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर सर, मेरे पास इनकी हर बात का जवाब है। मैने जो मापदण्ड अभी आपके सामने रखे है उनका मै पहले थोडा सा जवाब देना उचित समझता हू। सबसे पहले मै राजनैतिक स्थिरता की बात करना चाहता हूं। कोई भी दे ा या प्रदे ा हो उसकी इकोनोमी स्थिती उसकी राजनैतिक स्थिरता पर बहुत निर्भर करती है। अगर आपके यहा पर आना जाना चलता रहे यानि आया राम गया राम चलता रहे तो उस दे ा या प्रदे ा की इकोनोमिक स्थिती बैठ जाती है। हमारे यहां सबसे बडी उपलब्धता तो यह रही है हरियाणा रकार पमे राजनैतिक स्थिरता रही है जिस वजह से निश्कण्ट सरकार जो है यानि आपकी यह सरकार जो वर्श 2000 मे बनी थी तब से लेकर आज तक कोई भी आदमी प्रदे ा की राजनैतिक स्थिरता के बारे में कुछ नही कह सकता। हालांकि हमारे सहयोगी साथी भी रहे है, जहां उनका योगदान राजनैतिक स्थिरता के बारे मे रहा, वह अलग बात है। डिप्टी स्पीकर सर, सबसे पहले मै बताना चाहूंगा कि इस हाउस के अनदर 12 फरवरी को मैने बजट पे ा किया था और इस बारे मे 14 फरवरी को बिजनैस स्टेण्डर्ड न्यूज पेपर मे बजट के बारे मे छपा है। (विघ्न) यह कोई इस अखबार की खबर नही है। डिप्टी स्पीकर सर, मै आपकी इज्जत से इस अखबार मे जो छता है उसके दो चार पैराज आपके सामने पढ कर सुनाना चाहता हूं कि राजनैतिक स्थिरता क्या होती है। जैसे कि मै कह रहा हूं कि इस अखबार की

खबर नही है बल्कि किसी का राईट अप है। (विघ्न) आप सभी साथी बैठिये। मै हरके माननीय सदस्य का बात का जवाब दूंगा। स्पीकर सर, इस अखबार मे लिखा हैः—

"When Om Parkash Chautala became Chief Minister in 2000, h einherited a huge Bansi Lal Legacy in the liquor mafia. Remember the days when, during Bansi Lal's Chief Ministership, prohibition was declared in Haryana. When Bansi Lal saw the way the law was being subverted through smuggling of alcohol, evasion of excise, etc. he lifted the prohibition. But when he was unable to dismantle was the liquor mafia.

Margins in the slae of alcohol in Haryana are huge and the network that used to function underground had now come overground. Everyone powerful had something to do with the liquor mafia. During Bansi Lal days the Government registered cases against a number of prominent politicians including relatives of leading BJP politicians- Krishan Pal Gujar, for one. The Governments case was that buses owned by Gujar were used to transport alcohol illegally. Gujar's argument was that it was a false, trumped up case.

चौ0 भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्षः भजन लाल जी, आप का प्वायंट आफ आर्डर क्या है?

चौ0 भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर यह है कि वित मंत्री महोदय जिस प्रकार से अखबार पढ रहे है क्या वे इस प्रकार से हाउस मे अखबार पढ सकते है? यह बात ठीक है कि वे कोई रैफरेंस दे सकते है और अखबार का हवाला दे सकते है लेकिन अखबार मे जो लिखा है उसका पूरा पेज ये पढ रहे है यह अच्छी बात नही है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, ये लिकर पर पहले ही बोल चुके है और इन्होने स्टार्ट भी वही से किया था और अब फिर इन्होने उसी बात को भाुरु कर दिया। (विध्न)

श्री उपाध्यक्षः चौधरी भजन लाल जी, आपने अपनी बात कह ली है इसलिए अब आप अपनी सीट पर बैठे। (शोर एवं विघ्न) जब आपका मौका था तब आप खुब बोल लिए अब आप अपनी सीट पर बैठें।

श्री औम प्रका ा चौटालाः उपाध्यक्ष महोदय, मै चौधरी भजन ला जी को याद करवाना चाहूंगा कि इन्होने इस सदन के अंदर 50 मिनट का समय जाया किया था और अखबार का पूरा का पूरा पेज पढा था। इन्होने टोटल पेपर पढा था और उसमे एक भी भाब्द इनकी अपनी जानकारी का नही था। इन्होने टोटल अखबार की बात पढी थी ओर वित मंत्री जी तो केवल रैफरैंस दे रहे है इसलिए इनको सुनना चाहिए।

चो0 भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, ये पूरे का पूर अखबार नही पढ सकते।

श्री औम प्रका ा चौटालाः भजन लाल जी, आपको सुनना चाहिए और अगर आप लांग इंट्रप्ट करेगे तो इससे सदन का समय खराब होगा। ये रैफरेंस दे रहे है और अंग्रेजी मे पढ रहे है इसलिए आपको और मेरी समझ की बात नही है। अंग्रेजी आपके और मेरे बस की बात नही है इसलिए आप इस झमेले में क्यों पडते है?

चौ.0 भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुने।

श्री उपाध्यक्षः भजन लाल जी, अब आप बैठें। आपने अपनी बात रख दी है। अब आप बैठ जाए।

प्रो0 सम्पत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, अखबार के अंदर छपी खबर, छपा हुआ कोई लेख या पब्लिक ओपीनियन का जिक हाउस मे क्यों नही कर सकते है (विघ्न) ये लोग खुद भी ऐसा करते रहे है और आज भी अखबार का जिक किया गया था और उस वक्त मैने कहा था कि उसका बाद मे मै। जवाब दूंगा।

चौ0 जय प्रका ाः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः जय प्रका ा जी, इस वक्त कोई प्वायंट आफ आर्डर नही है इसलिए आप बैठें।

चौ0 जय प्रका ाः उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्षः यह कोई तरीका नही है, इसलिए आप अपनी सीट पर बैठें।

वाक आउट

चौ0 जय प्रका ाः उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बार बार अनुरोध करने पर भी आप मुझे प्वायंट आफ आर्डर पर बोलने की इजाजत नही दे रहे है इसलिए मै इसका विरोध मे हाउस से वाक आउट करता हू। (शोर एवं विघ्न)

(इस समय इंडियन नै ानल कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री जय प्रका ा बरवाला सदन से वाक आउट कर गए)

वर्श 2004–05 के बजट पर सामानय चर्चा (पुनरराम्भ)

श्री उपाध्यक्षः प्रो0 साहब आप कन्टीन्यू करें।

Finance Minister Prof. Sampat Singh: Deputy Speaker Sir, I again read out the next para of this article-

"The Lok Sabha election will also be a test of Chautala's stewardship of his party which has performed spectaculary (considering its size) in the Rajasthan Assembly

elections, The INLD fielded candidates in 40 assembly it was not bad at all,. This has given rise to speculation that is INLD performs well in the Lok Sabha. Chautala could emerge as yet another power-broker in a hung Lok-Sabha.

In a State where tranfers and postings used to be an industry and could make the unmake ministers. Chautala rule with an iron hand and- yes, he is not afraid to say it- Fear. He has the smallest Cabined in the country.

It says that he is doing just like Sardar Patel.

(इस समय इंडियन नै ानल कांगेस पार्टी के सभी सदस्य अपनी सीटो पर खडे हो कर बोलने लगे)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडडाः उपाध्यक्ष महोदय, इनका यह क्या तरीका है। (शोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः आप सभी लोग अपनी अपनी सीटो पर बैठें। अभी मांगे राम गुप्ता जी ने क्या कहां मांगे राम जी ने सारी बातें कही और वित्त मंत्री ने उनकी बातो का जवाब दे रहे है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडडाः उपाध्यक्ष महोदय, अगर इन्होने यू ही अखबर से पढ कर रिप्लाई देना ळै तो हम वह सुनने के लिए तैयार नही है। (शोर एवं विघ्न)

प्रो0 सम्पत सिंहः इसका मतलब यह है कि आप लोग वाक आउट करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्षः अगर आप वाक आउट करना चाहते है तो कर सकते है। (शोर एवं विघ्न)

श्री भुपेन्द्र सिंह हुडडाः उपाध्यक्ष महोदय, **********(शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, **********(शोर एवं विघ्न)

आई जी रिटायर्ड (ोर सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, **********(शोर एवं विघ्न)

डा0 रघूबीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, **********(शोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः चेयरमैन साहब की परमि ान के बिना जो भी बोला जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाए।

प्रो0 सम्पत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैने सारा दिन इनकी पूरी बातें सुनी है और मै इनकी बातो का अब जवाब दे रहा हूं तो इन्हे आराम से बैठकर सुनना चाहिए। (शोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः आप सभी लोग अपनी अपनी सीटो पर बैठें। (शोर एवं विघ्न) कोई भी रैफरेंस दिया जा सकता है। (शोर एवं विघ्न) इसमे ऐसी कोई बात नही है इसलिए आप बैठें। (शोर एवं विघ्न)

चौ0 भजन लालः डिप्टी स्पीकर सर, अगर आप हमारी बात नही सुनेंगे तो हम वाक आउट करेंगे। (शोर एवं विघ्न)

मुख्य मंत्री(श्री औम प्रका ा चौटाला): भजन लाल जी, आपने खुद ही वि ोशतौर पर यह कहा था कि आप हाउस छोड कर नही जाएंगे लेकिन आप भी वाक आउट करके जाना चाहते है (शोर एवं विघ्न) आप लोगो के बीच मे जाकर क्या कहेंगे। आप लोग न तो खुद बोल सकते है और न ही किसी की बात सुन सकते है तथा न ही लोगो की दिक्कत को प्रस्तुत कर सकते है। (शोर एवं विघ्न)

वाक आउट

श्री उपाध्यक्षः आप डिस्प्लीन रखें। (विघ्न) आपकी पार्टी मे डिसिप्लीन कहां है। आई जी साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। पहले आपकी पार्टी के जय प्रका ा जी वाक आउट करके चले गए और अब आप लोग बिना इजाजत के बोल रहे है। क्या आप भी वाक आउट करना चाहते है। (शोर) आपकी पार्टी में कहां पर डिसिप्लीन है, जय प्रका ा जी के बाद क्या अब सारे वाक आउट करना चाहते है। आप सदन मे बैठें और जवाब सुनें। (शोर विघ्न)

श्री भुपेन्द्र सिंह हुडडाः अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नही सुन रहे है। वितमंत्री जी सदन मे अपनी रिप्लाई के दौरान इस तरह से अखबार नही पढ सकते है। यदि यह ऐसा करते है तो हम इसके विरोध मे सदन से वाक आउट करते है।

(इस समय सदन मे उपस्थित इंडियन कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

वर्श 2004–05 के बजट पर सामानय चर्चा (पुनरराम्भ)

वित मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, क्या अब वर्ल्ड बैंक के कर्ज की बात मै यहा पर न करुं, उसकी सैंक ान की बात मै क्या यहां पर न करुं, बजट के बारे मे कुछ जवाब देना है तो क्या मै वह भी सदन मे न दूं। दोनो के बारे मे अगले पैरा मे बात आ रही है।

"Haryana embarked on ambitious power sector reforms but the World Bank threatened to stop its Rs. 270 crore loan to the State on the gounds that it has namaged to unbundled utilities but was unable to take the next step of privatizing them. The State has an autonomous regulator who has recommended tow tariff hikes in the last four years. Chautala is clear about power- everyone has to pay for it.

ये कहते है कि मुफत देंगे Don't forget that these are the words of Mr. Chautala.

"Don't forget that I was blunt in refusing free power to the farm sector. We did promise this at one time, but later realized. Is would not be possible", he told reporters. The power situation in Haryana has improved although Chautala accepts that it is still not good enough.

Again Mr. Deputy Speaker Sir,

"The State's finance have improved. Although Haryana presented a budget with a deficit of around Rs. 400 crore this year, the chronic overdraft panic doesn't keep the finance secretary awake in the nights any more."

हर जगह रात भर फाईनैंस सैक्रेटरी फिरते रहते है। जिसकी वजह से ओवर ड्राफट हो जाता है। अब ये कहते है कि बाहर जाने की जरुरत नही है। उपाध्यक्ष महोदय, ये सूनना नही चाहते है कि (विघ्न)

"There was a time when the police and the education department used to get salaries on the 15th of every month and municipal employees would be paid six months salaries at once. Not any more."

आजकल नही है, पहले था Mr. Deputy Speaker Sir, what is bad in this.

Against Mr. Deputy Speaker Sir,

"The Government is clear that farmers are its biggest constituency and has undertaken aggressive market intervention in conditions of glut production. 90 per cent produce of farmers gets pickes up by the State."

90 प्रति ात अनाज मार्किट मे जो आया था, उसको हमने उठाया है तो भी इनके पेट मे दर्द होता है।

"Where earlier, private sector grain merchants used to form cartels to drive down prices."

पहले वे लोग अपना समझौता करके प्राईस को डाउन कर देते थे। अब इस बारे मे मै नही कहूंगा तो कब कहूंगा। इसी प्रकार से

Roads have improved some years ago, those living in Haryana would prefer to drive through Punjab rather than take the pot-holed Haryana roads."

"But despite all this, Haryana is known never to vote the same party in twice in succession and observers say this is the biggest problem Chautala is going to face both in the Lok Sabha and in the assembly election due in a year. He has an answer for this. The Supreme Court has given a verdict in the Sutlej Yamuna Link Canal case in Haryana's foavour and the only isse now is which agency wil build the canal."

अब एक ही बात रह गई है कि कौन सी एजेन्सी बनाएगी। बाकी सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुका है। इससे बढिया और क्या बात हो सकती है।

"If Chautala can bring water to south Haryana-Rewari, Narnaul, Jind, etc he is assured of victory."

उपाध्यक्ष महोदय, फाईनैंस सिस्टम मैनेजमैंट के बारे में, एस वाई एल के बारे में और सीवरेज के बारे मे हम यहां पर नही कहेंगे तो कहां पर कहेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि यहां पर माप दण्ड के बारे मे भी कहा गया है, राजनीतिक स्थिरता के बारे मे कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सदन मे कहता हूं कि पहले पर कैपिटा इन्कम 19340 थी और अब यह बढकर

26632 हो गई हैं। यह क्या इंडीकेटर है? सरकार के सतता संभालने के बाद दुध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति जो पहले 626 ग्रम थी वह अब बढकर 676 ग्रम हो गयी है। जब हमने सत्ता संभाली तो बिजली की खपत प्रति व्यक्ति 450 यूनिट थी जो अब बढकर 530 यूनिट प्रति व्यक्ति हो गयी है। उद्योग मे बिजली की खपत पहले 19337 लाख यूनिट थी जो अब बढकर 27583 लाख यूनिट हो गयी है। इसी तरह से हरियाणा मे पहले 1 लाख 74 हजार टन पैट्रोल की खपत होती थी वह अब बढकर 2 लाख 5 हजार टन हो गयी है। इसी तरह से डीजल की खपत जहां पहले 17 लाख 49 हजार टन थी वही अब बढकर 22 लाख टन हो गयी है।

श्री कर्ण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि ये जो हरियाणा के बारे मे बता रहे है यह तो हमने पढा है। यह तो इन्होने उसी दिन भी बताया था इसलिए अब इसको बताने की क्या जरुरत है? मैने यह कहा है कि जो हमारा पडोसी राज्य पंजाब है अब उससे तुलना करके बताएं कि हम कहां पर है उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है और उनके मुकाबले हरियाणा के एक आदमी को प्रति व्यक्ति कितना दुध मिलता है?

Prof. Sampat Singh: I Will twll you about Punjab. What is financial positin there? You know better than I. इसी तरह से डिपटी स्पीकर सर, जहां तक लॉ एण्ड आर्डर की बात है,

मांगेराम जी ने सरसरी तौर पर एक सैंटेन्स को छोडकर कुछ भी नही कहा है। आपका असैम्बली का रिकार्ड पडा है। आप देख सकते है कि बजट के उपर किसी भी मैम्बर ने एक सैंटैन्स नही कहा है अगर कहा हो तो सरकार उनकी बात को मानेगी। एक आदमी ने भी नही कहां इसका मतलब क्या है You are not concerned about law and order. Either you are satisfied or आपका इससे कोई मतलब नही है। अगर आप संतुश्ट है तो इसका मतलब सारी की सारी अर्थव्यवस्था ठिकी हुई है जहां तक युथ वैलफेयर की बात है, पहले इनके हालात क्या थे यह आपको भी पता है। लेकिन अब इनके लिए एक स्पोर्टस पोलिसी जिसमे आपका भी बडा भारी योगदान है, बनाकर इनको सही राते पर लाया गया है। पहले जहां यूथ क्रिमिनल था वहीं आज वह खेलो में, उत्सवो में भाग लेता है। वैसे ज्यादा तो इ बारे में मै पालिसी के टाईम मे बताउंगा लेकिन अभी तो मै इतना ही कहना चाहूंगा कि हालांकि बाईचांस कर्णम मल्ले वारी हरियाणा मे पैदा नही हुई थी वह केवल हरियाणा की रहने वाली थी लेकिन चौधरी साहब की कमिटमैन्ट थी इसलिए उन्होने उसको 25 लाख रुपये दिए वरना हरियाणा से पैदा होने वाले ने अभी तक ओलम्पिक में रिप्रेजैनट नही किया है लेकिन अब यह हरियाणा के लिए गौरव की बात है कि अब जो ओलम्पिक होने जा रहे है उनमे हिन्दुस्तान से केवल 6 लोग भाग लेने जाएंगे और उनमे पहली बार तीन रे ानल्ज हरियाणा के होंगे। This is the first time in the country for sports policy. इस तरह से कितने साल दे ा को

आजाद हुए हो गये है 57 साल हो गये है। एक भी ने ानल यूथ फेस्टिवल हरियाणा प्रदे ा में नही हुआ लेकिन फर्स्ट टाईम ने ानल यूथ फेस्टिवल हरियाणा मे हुआ ओर वह भी कैपीटल हैड क्वार्टर पर नही बल्कि डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर हआ। इसका मतलब है कि यूथ के प्रति रकार कितनी चिंतित है। डिप्टी स्पीकर सर, अब मै इन भाईयो ने जिन बातो का जिक्र किया है, उन सब पर आता हूं। जी एस डी पी एक बहुत बडा फैक्टर होता है अर्थव्यवथा के बारे में। वर्तमान मूल्यो के अनुसार सकल राज्य घरेलु उत्पादन वर्श 2001–02 मे 60212 करोड रुपये था जो अब बढकर 65387 करोड रुपए हो गया है। इसमे इंक्रीज है 9.3 परसैंट की। इस तरह से ये अच्छी अर्थव्यवस्था के इंडीकेटर है। स्थित मुल्यो मे जहां पहले यह 35 हजार 62 करोड रुपये था वही अब बढकर 36 हजार 86 करोड रुपए हो गया है इस तरह से यह वृद्धि 5.2 प्रति ात की है जबकि राश्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि केवल चार प्रति ात की है। We are better than national average. इसी तरह से कुछ माननीय सदस्यो ने ज्ञान के अभाव की वजह से प्राईमरी, सैकेण्डरी और टर ियरी सैक्टरो के बारे मे कहा। उन्होने यह भी कहा कि एग्रीकल्चर सैक्टर का कंट्रीब्य ान सैकेण्डरी सैक्टर के मुकाबले मे गिर रहा है जो कि चिंता का विशय है। इस तरह की बाते इन्होने कही लेकिन चिंता का विशय नही है बल्कि गौरव का विशय है। पहले इकोनोमी मे कंट्रीब्यू ान का भार अकेले कृशि पर ही था। अकेले एग्रीकल्चर सैक्टर पर था इसका मतलब आमदनी के साध और कोई नही थे। आप सौ रुपये कमाते थे

और 100 रुपये एग्रीकल्चर सैक्टर कमाता था आज उस बोझ को ट्रेड, इण्डस्ट्री और सर्विसिज ने भोयर किया है और जो ग्रोथ हुई है उसकी वजह से एग्रीकल्चर सैक्टर की ग्रोथ रुकी नही है। उत्पादन कम नही हुआ है। इसमे कंट्रीब्यू ान बढा है इस बात के लिए तो इनको गर्व महसूस करना चाहिए था। प्राथमिक क्षेत्र मे कितना बढा है इसमे कृशि क्षेत्र भाामिल है यह 29.4 हुआ है, द्वितियक सैक्टर मे 28 प्रति ात और तृतीयक सैक्टर में 42.6 प्रति ात इसका मतलब यह है कि अब अकेले कृशि पर बोझ नही रहा। दूसरी चीजो में भी पगति की है। (विघ्न)

डा0 रघूबीर सिंह कादियानः कृशि पर घटा है वह क्यां घटा है यह तो बताए।

प्रो0 सम्पत सिंहः मै वही बात कह रहा था आप यहां थे नही तो मै क्या करु। अकेले एग्रीकल्चर सैक्टर पर था इसका मतलब आमदनी के साधन नही थे। आप सौ रुपये कमाते थे और 100 के 100 रुपये एग्रीकलचर सैक्टर कमाता था। अब 100 रुपये जी एस डी है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले 100 का 100 रुपया एग्रीकलचर सैक्टर से आता था बाद मे ं90 हुआ, फिर 80 हुआ, 70 हुआ, 60 हुआ। यह क्यों हुआ। यह भी बता देता हू। यह नही है कि उत्पादन घटा है, उत्पादन बढा है लेकिन मै कह रहा हूं कि ट्रेड इण्डस्ट्री और सर्विसिज इनका कंट्रीब्यू ान बढा है हम प्रोग्रेसिव इकोनोमी की तरफ जा रहे है डा0 साहब यह आपको सोचना चाहिए। सर्विसिज का कंट्रीब्यू ान बढा है। that is a great

achievement. और उपाध्यक्ष महोदय, वार्शिक योजना का बडा ज्रिक किया गया 2003–04 मे हमने 2100 करोड रुपये घटाकर 1850 करोड रुपये की थी। मांगे राम गुप्ता जी बैठे है कई बार अकस्मात बहुत सी ऐसी चीजें आ जाती है जो पहले नही सोच सकते वह खर्च पब्लिक इंट्रस्ट मे खर्च है वह कोई फिजूलखर्ची नही है उसमे से योजना हर बार घटती है, मांगे राम जी के समय मे भी घटी है और चौधरी बंसी लाल जी के समय मे भी ड्रास्टिकली घटी है और हर साल घटी है मै आंकडे दे देता हू। 1991–92 मे रिवाइज्ड एस्टीमेट 722 करोड था जो 701 रहा, 97 परसैंट अचीव किया। 1992–93 मे 804 था 752 रहा, 93 परसैंट अचीव किया। 1993–94 मे 839 था घटकर 805 रह गया ओर 96 परसैंट अचीव किया। 1994–95 मे 1019 से घटकर 966 करोड किया और 94 परसैंट अचीव किया। 1995–96 मे 1225 से घटाकर 1116 करोड रहा और 91.1 परसैंट अचीव किया और चौधरी बंसी लाल जी के समय में 1996–97 मे 93 परसैंट अचीव किया। 1998–99 मे हमने संभाला था ओर 94.6 अचीव किया और आज की सरकार ने पहले ही साल 93.8 किया और दूसरे साल 94.1 परसैंट अचीव किया और तीसरे साल 97.4 परसैंट अचीव किया और मांगे राम जी का 97.1 परसैंट हाइऐस्ट था that is the highest one in the history of Haryana for the last ten years. I am not talking about all the 30 years. उसमे और किया 2002–03 मे 1816 से 1776 किया है और 97.8 परसैंट अचीव किया है जो कि और ज्यादा अचीव किया गया है। (शोर एवं

व्यवधान) यह जो मै कह रहा हं यह रिवाइज्ड आउटले प्लान था जो कि अचीव किया है that is a great achievement और जो बोझ अलग से आए जैसे नंबर एक पर केन्द्रीय करो मे हिस्सा 38.49 करोड कम आया और केन्द्रीय सहायता 45.15 करोड रुपये कम आई यह दोनो यदि मिला देता हूं तो 83.64 करोड बनता है यह कमी आई। डिप्टी स्पीकर सर, सहकारी चीनी मिलो के बारे मे मै कहना चाहूंगा कि जो गन्ना उत्पादक किसान थे उनके भुगतान के लिए 110 करोड रुपए भूगर लिो को किसानो का भुगतान करने के लिए दये गये है। इसी तरह से एल ए डी टी का जो पैसा आता है उसका बंटवारा स्थानीय निकायो को 41 करोड 70 लाख रुपये किया गया है। बिजली निगमो को वन टाईम सैटलमैंट के लिए 174 करोड रुपये ब्याज के लिए दिया है। इसलिए इन कारणो से यह प्लान कुछ कम की गई अऔर कम करना जरुरी हो गया था क्योंकि सरकार की कुछ मजबुरियां थी जो खर्चा बताया गया है इसमूे हमने कोई नाजायज नही किया। यह प्रदे ा की जनता के लिए खर्च किया गया है और वि ोशकर किसानो के लिए किया है।

डा0 रघुबीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मै वितमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बोर्डज और कारपोरे ांज से जिन लोगो को निकाला गया है क्या उनको नौकरी मे लेने के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रावधान किया गया है या नही किया गया?

प्रो0 सम्पत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इसका प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने जो रिक्रूटिंग एजैंसिज है वे जो पोस्ट एडवार्टाइज करती है उनमे अगर किसी कर्मचारी की क्वालीफिके ान पूरी होगी तो उनको नौकरी दी जायेगी और 25 प्रति ात पोस्टे उनके लिए रिजर्वा भी की गई है। इसमे एक की कोई बात नही हैं। Age is not bat. जहां तक टोटल जॉब्स की बात है जो हमारी सरकार ने टोटल जाब्स सेंक ान की है including public sector और गवर्नमैंट सैक्टर मे वे 71 हजार सैंग ान की है। इसमे से जो पूरी हो चुकी है वे 29 हजार पोस्टे है जिन पर लोग ज्वायन कर चुके है, 34 हजार पोस्टे अंडर प्रोसैस है और केवल 8 हजार पैंडिंग जाब्स है जिनकी रिक्वीजे ान भेजी जानी है। उपाध्यक्ष महोदय, कई विभागो की रै ानेलाईजे ान अभी भी चल रही है। जो 71 हजार का आंकडा है यह धीरे धीरे 90 हजार पर पहुंच जायेगा। सरकार ने छ।टनी नही की है बल्कि जाब्स सरकार बढा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि विपक्ष के साथी चाहते है तो मै सभी विभागो का पढकर सुना देता हूं लेकिन फिर चौधरी भजन लाल जी कहेंगे कि पढने लग गया। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होने fiscal deficit की बात की है। आपको यानि किसी प्रदे ा को दे ा की इकोनोमी के साथ डैफिसिट कम्पेयर करना पडता है और दूसरी स्टेट के साथ भी कम्पेयर करना पडता है। आपका जो प्रीवियर ईयर रहा है उसके साथी भी आपको कम्पेयर करना पडता है तब जा कर आपको अपनी अचीवमैंटस पता चलता है। डिपटी स्पीकर साहब, 1998–99

मे जो फिसकल डैफिसिट था वह 2240 करोड रुपये था। यह वर्श 2002–03 मे कम हो कर 1471 करोड रह गया। कहां आपका डैफिसिट 2240 करोड रुपए और कहां 1471 करोड रुपये। इससे पता चलता है कि आपका डैफिसिट घट रहा है जबकि ये कह रहे थे कि यह बढ रहा है। इसी प्रकार से वर्श 2003–04 मे 1343 करोड रुपए रहा। (विघ्न) मै उस पर भी आउंगा। I will come on each and everything. Just wait.

श्री उपाध्यक्षः आप लोग बैठिये। आप लोगो का बोलने का यह कोई तरीाक अच्छा नही है।

प्रो0 सम्पत सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, 203–04 मे फिसकल डैफिसिट 1343.88 करोड था। यह भी पहले की अपेक्षा घटा है। अब दूसरा कम्पेयर करते है सकल घरेलू उत्पाद के साथ। वर्श 2001–02 मे 4.5 प्रति ाल की तुलना मे वर्श 2002–03 मे यह भी घटकर 2.23 प्रति ात रह गया है, यानी यह भी धटा है। मै सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि चालू वित वर्श मे यह धटकर 1.83 प्रति ात रह गया है। सर, हमें अगले साल जो राजस्व प्राप्ति होगी वे 10.5 प्रति ात की दर से संभावित है। इसके मुकाबले मे जो राजस्व में वृद्धि है वह 9.4 प्रति ात है। यह भी अंडर कन्ट्रोल है और इसमे भी 1.41 प्रति ात की कमी हुई है। यह सब अच्छे वितीय प्रबंधन का ही नतीजा है। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, इन उपायो से हमें वर्श 1999–2000 मे सकल

राजस्व घरेलू उत्पादन मे जो प्राप्तियां 7.2 प्रति ात थी जो अब बढकर 8.44 प्रति ात हो गई है। (शोर)

डा0 रघुबीर सिंह कादियानः डिप्टी स्पीकर साहब,

श्री उपाध्यक्षः इनकी कोई बात रिकार्ड न कि जाये। कादियान साहब आप बैठिये।

प्रो0 सम्पत सिंहः डिप्टी स्पीकर सर, अब मै कर्जा की बात बताना चाहता हू। ये अपेाजी ान के भाई कर्जो का बडा भाोर मचा रहे थे। ये पहले सुने तो सही। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री औम प्रका ा चौटाला): डिप्टी स्पीकर सर, डा0 रघूबीर सिंह कादियान दुबारा से सदन मे इस भार्त के साथ वापस आये थे कि इनका आचरण ठीक रहेगा ओर आज मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ यह है कि आज ही मैने सवेरे एक अकस्मात सराहना कर दी। लेकिन ये फिर उसी लाईन पर आ गए। (विघ्न) आपके नेता ने यह कहा था कि आप अपना आचरण ठीक रखोगे। आप क्यों हाउस का समय खराब कर रहे है। आप बैठे और हाउस को चलने दे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडडाः डिप्टी स्पीकर साहब, वे प्वायंट आफ आर्डर पर बोलना चाहते है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः हुडडा साहब, एक सम्मानित सदस्य बिना पूछे बार बार उठता रहे, यह कोई बात है। (विघ्न)

डा0 रघूबीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, मै प्वायंट आफ आर्डर पर बोलना चाहता हू। (विध्न)

श्री उपाध्यक्षः प्वायंट आफ आर्डर का क्या आपने ठेका ले लिया है। इस हाउस मे और भी मैम्बर्ज है। इसलिए आप बैठिये। आपके पूरा मौका दिया गया है।

डा. रघुबीर सिंह कादियानः डिपटी स्पीकर साहब,

श्री उपाध्यक्षः इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। कादियान साहब, आप बैठिये। कादियान साहब, आप अपनी आदत सुधारो। आप हाउस का समय बर्बाद न करो। आप बैठो।

प्रो0 सम्पत सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मै लीडर आफ दी अपोजी ान का धन्यवाद करता हूं कि उन्होने सम्मानित सदस्य को काबू किया। परम्परा तो यही रहती है कि चेयरमैन साहब की आज्ञा से ही कोई सदस्य काबू हो जाता है, लेकिन चलो ये नही मानते तो अलग बात है। (शोर)

श्री उपाध्यक्षः कादियान साहब, आप बैठे बैठे भी नही बोलेंगे। क्या आपको बोलने का समय नही दिया गया। आपका यह कोई तरीका है, यहा पर हाउस के 90 सदस्य ओर बैठे है। (विघ्न) आप औरो के हक को नही खोओगे। आपकी यह बात ठीक नही है। आप सब को पूरा समय मिला है। आप बार बार बीच मे इन्ट्रप्ट न करे।

प्रो0 सम्पत सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, अब मै ऋणो पर आता हूं क्योंकि ऋणो का जिक्र किया गया है। मै वर्श 2002–2003 का बताउंगा क्योंकि 2004 के ऐस्टिमेटस है और 2005 के भ ऐस्टिमेट्स है लेकिन 2002–2003 की हमारे पास पूरे वर्श की एक्चुअल फिगर्ज है इसलिए वह कम्पेयर करुंगा। वर्श 2002–2003 मे 18187 हो गये है। (विघ्न) और साथ मे राय की गारन्टी का जिक्र आया। 7600 करोड रुपये की गारंटी हो गई है तो डिप्टी स्पीकर साहब, इस साल का जो अनुमानित है वह 21649 का है पिछले साल का हम डिस्कस कर चुके है। इस बार 21649 के जो 18187 से पहले आया यह लगभग तीन हजार करोड समथिंग रुपये पहुंच जाता है। कर्जा लिया है, यह ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने कर्जा लिया है इसमे कोई दो राय नही है लेकिन कर्जा खर्चा कहां पर गया है? बात यह नही है बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खच्र किया है असैट्स पर खर्च किया है और एक एक चीज मै यहां बता दूंगा कि कहां कहां पर खर्च किया गया है। उनका बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आप बनाएंगे, असैट्स आप बनाएंगे तो उसका रिटर्न भी आपको आएगा।

कैप्टन अजय सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि जो रिपोर्ट वर्श 2003 मे स्टेट की जो गारंटी थी वह 12461 करोड रुपये की थी और यह बता रहे है 4 हजार करोड रुपये, माननीय वित मंत्री जी यह बताने की कृपा करे कि ये यह कैसे बता रहे है?

प्रो0 सम्पत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक खर्च की बात है पहले की तरह जैसे पावर सैक्टर का है। (विध्न) पावर सैक्टर मे हर सरकार सबसिडी देती रही है लेकिन डिप्टी स्पीकर सर, वह केवल बुक ऐडजस्टमैंट के रुप मे देते रहे है। (शोर)

डा0 रघूबीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, ********

श्री उपाध्यक्षः कादियान साहब, आप अपनी सीट पर बैठे। (विध्न) हाउस मे एक आप ही हरी ा चन्द्र पैदा हुए है। मैने कई बार आपसे गुजारि ा कर ली है कि आप हाउस को चलने दे लेकिन आप मान नही रहे है। (शोर)

प्रो0 सम्पत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, सबसिडी फारमर्ज के हित मे दी जाती है और हर सरकार यथासम्भवदेती रही है लेकिन इसमे फर्क यह है कि पहली सरकारे केवल बुक ऐडजस्टमैंट करती थी और आपके बजट पर उसका असर नही आता था। आपकी सरकार ने 4400 करोड रुपये 4 साल मे हार्ड कै ा सबसिडी दी, that is an achievement and that is in the interest of farmers. उपाध्यक्ष महोदय, किसान के हित के लिये अगर कर्जा लेना पडेगा तो लेंगे, किसान को आगे बढाना है। किसान के बिना अर्थ–व्यवस्था समाप्त हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पावर सेक्टर मे खर्च बढा है। एच वी पी एन हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम उसके एन ओ पी सी एन एच पी सी तथा अदर्ज़ का जो कर्जा बकाया है वह 222 करोड था गवर्नमैंट आफ इंडिया

ने दे ा के सभी पावर मिनिस्टर्ज तथा सभी पावर सैक्रेटरीज़ की एक मीटिंग बुलाई थी और कहा था कि आप बौंडज खरीदे और इनको आपको लोन्ज मे डालना पडेगा और इसमे रियायत देंगे और सरचार्ज भी माफ करेंगे 222 हजार करोड रुपये की जो देनदारी थी कर्जो मे बढी थी यह कर्जो मे इस वजह से बढी क्योंकि 222 करोड रुपये एकमु त Onetime Settement Scheme के अन्दर आपने वह पैसा दिया और लोन के खाते में डाला। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** गारन्टी मे नही, गारंटी के बारे में भी मै आपको बताउंगा कि लोन्ज के खाते में 222 हजार करोड डाला और इससे फायदा कितना हुआ है। इससे उुऐल सरचार्ज का 60 प्रति ात माफ हआ यानि 100 पेमैंट करने की वजह से 649.25 करोड रुपये का फायदा हुआ है और एक इन्सैंटिव भी मिला है जो कि throughout the country केवल हरियाणा स्टेट ही ले पाई है। यह इन्सैंटिव यह है कि आपने इनटाईम पैमैंट कर दी इसलिए पहले साल की एडवासं की पेमैंट मान रहे है कि पहले साल के अंदर 1.1 की बाउंड वैल्यू के आपके पैसे की ऐडजस्टमैंट हो जाएगी और वह चार्ज आपको नही देना पडेगा। 8 प्रति ात आटोमैटिकली इसी लोन में से हो जाएगा। अगल साल 5 प्रति ात जाएगा फिर 4 जाएगा फिर 4 जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपको इतना पैसा नही देना पडेगा, इसी पैसे मे इसी लोन मे से वह रि पे आप कर चुके होंगे। तो स्पीकर सर, इन कामो के लिए पैसा लिया है। पब्लिक इन्ट्रस्ट के अन्दर लिया है। जहां तक गारंटी का सवाल है तो स्पीकर सर, अगर ये सुनेंगे तो इनके भी

कान खुल जाएंगे। चौधरी भजन लाल जी, मै गारंटी के बारे मे आपको बताता हूं कि चारो जो पावर यूटिलिटिज है उनमे 4035 करोड रुपये गारंटी है। यहां पर सबसे ज्यादा जनरे ान के बारे मे बात कही गई है। स्पीकर सर, आप पानीपत मे रहते है और जनरे ान के बारे मे आपको ज्यादा पता है। मै आपके माध्यम से सदन मे बताना चाहूंगा कि हमने सबसे पहले 210 मैगावाट की सिक युनिट के कम्पली ान का काम किया है। यह काम काफी समय से अटका पडा था। इस पर 1994 मे 239 करोड रुपये खर्च का एस्टीमेट बनाया गया था, स्पीकर सर, अब हमने इसको कम्पलीट किया है तो इस पर 985 करोड रुपये खर्च हुए है। यह खर्च क्रिमिनल/नैगलिजैंस की वजह से हुआ है। यह हमारी वजह से नही हुआ है बल्कि ये जो हमारे सामने बैठे हुए है इनकी वजह से हुआ है। अब इस बारे मे हम कुछ कह देंगे तो इनके दर्द होगा। स्पीकर सर, कहां तो खर्च 239 करोड रुपये होना था और कहां पर 900 करोड रुपये से ज्यादा खर्च हुआ है। मै आपके मायम से इनको यह बताना चाहूंगा कि इन कामो को पूरा करने के लिए लोन लेना पडता है। इन लोन्ज के अगेन्सट स्वाभाविक है कि गारंटी भी देनी पडेगी। हमे इस पर 362 करोड रुपये की गारंअी देनी पडी है। इसी तरीके से स्पीकर सर, पिछले दिनो सैकेन्ड युनिट की रिपेयर का काम 300 करोड रुपये मे दिया गया था और इस कंपनी को काम देने के बाद 72 करोड रुपये का एल आई सी से लोन लिया गया था। स्पीकर सर, यह पहली बार हुआ है कि कंपनी को ऐडवासं पेमैंट कर दी गई और वह कंपनी बीच

मे ही काम छोडकर भाग गई। स्पीकर सर, यह पैसा जर्मनी की कंपनी से 15 प्रति ात ब्याज की दर पर लिया गया था। स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से इनको यह बताना चाहूंगा कि जब पैसा लोन पर लिया जाता है तो उसकी गारंटी भी देनी पडती है। स्पीकर सर, बंसी लाल जी की सरकार के जाने के बाद जब हमारी सरकार आई तो हमने उस कंनी की गारंटी जब्त करवा दी। वह कंपनी तो भाग गई थी और यह खाता तो खत्म हो गया था। अब वह काम 35 करोड रुपये में हो गया है। इसके बाद 7वीं और 8वीं यूनिट का जिक्र आया है। इस पर लगभग 1785 करोड रुपया खच्र आया है। स्पीकर सर, इसके लिए हमने 1428 करोड रुपये का लोन सैंक ान करवाया है। स्पीकर सर, मै इनको यह बताना चाहूंगा कि ये लोन किस बात के लिए लिए जा रहे है, ये लोन इसलिए लिये जा रहे ळै ताकि आपकी जनरे ान बढे। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यू ान सिस्टम मे 2 उतरी और दक्षिणी कंपनीयां है। एक मे 278 लाख और दूसरी में 268 लाख रुपये का कर्जा लिया गया है। स्पीकर सर, अगर ये कहते है कि इन कामो को करने के लिये कर्जा लेना कोई बुरी बात है तो उसको बुराई माना जाएगा। यह पैसा पब्लिक इन्ट्रस्ट के लिए लिया गया है। (विघ्न)

श्री भुपेन्द्र सिंह हुडडाः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैने ट्रांसमि ान लोस के बारे मे बात की थी, ये उसके बारे में बताएं।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से सदन मे बताना चाहूंगा कि केन्द्र ने एक डैटसवैटस की स्कीम चलाई थी और हमने उस डैटस–वैटस की स्कीम का फायदा भी उठाया है। बंसी लाल जी और भजन लाल जी की सरकार के वक्त में 14–14 प्रति ात और 15–15 प्रति ान पर लोन लिया गया था। स्पीकर सर, उस महंगे इन्ट्रस्ट पर लिये पैसे को कम करने के लिए हमने कम इन्ट्रस्ट पर 1764 करोड रुपये का लोन लिया है। मांगे राम गुप्ता जी, अगल साल हमने 1320 करोड रुये का प्लान रखा है। मै यह भी बताना चाहूंगा कि जो लाने लिये जा रहे है ये 9.5 प्रति ात से लेकर 10.5 प्रति ात तक ब्याज की दर से लिये जा रहे है। स्पीकर सर, हमने जो यह लोन लि है इसको लेने की वजह से हमें 190 करोड रुपये का ब्याज नही देना पडा है। हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार की इस स्कीम का फायदा उठाया है जो कि हमें उठाना भी चाहिए था। इससे आज हरियाणा प्रदे ा का सुधार हो रहा है। स्पीकर सर, 2002 मे बजट घाटा 454.16 करोड रुपये हुआ था और अब यह 226.98 करोड रुपये पर समाप्त हुआ है। स्पीकर सर, 227 करोड रुपये का घाटा कम हुआ है। स्पीकर सर, आंकडे तो तब बताते जब हम कुछ छिपाते, हमने तो कुछ नही छिपाया है। हम तब छुपाते अगर हमने जो एस्टीमेट घाटे का लगाया था, उससे फालतू घाटा हो जाता और अगर ऐसा हो जाता तो ये कह देते कि देखो आपने ऐस्टीमेट उस समय छुपाये थे लेकिन ऐसा नही है कि ये घाटा 454 करोड 226 करोड रुपये तक आ गया है। यह किसान की सरकार है ओर

किसान का बेटा मुख्यमंत्री हो तथा किसान का बेटा वित मंत्री हो तो यह वह कैसे कर सकता है? अगर कोई वाणिज्य परिवार का आदमी होात तो वह ऐसा करता, वह धाट बाध कर सकता था वह तो छुपाता लेकिन हमने कुछ नही छिपाया है। जो कमियां है वह बता दी। (विघ्न) 2003 और 2004 मे यह 226.98 से 339.58 हो जाएगा। इसके कोई दो राय नही है। 99.39 का इस साल घाटा है वह होगा लेकिन स्पीकर सर, कितना बोझ आया है यह भी हमको देखना पडेगा। गुप्ता जी के समय जो पांचवा वेतन आयोग आया था उसने केवल हरियाणा की ही नही बल्कि सभी को अर्थव्यवस्था की रीढ की हडडी तोड दी लेकिन इसके बावजुद भी हरियाणा प्रदे ा मे हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह हम दे रहे है। अगर पहली तारीख की छुटटी हो तो 31 तारीख, 30 तारीा को ही कर्मचारीयो की तन्ख्वाहें दे दी जाती है। गुप्ता जी, बंसीलाल ी के समय काो तो छोडिये हमने तो आपका भी भूगता है। आप तो वाणिज्य परिवार से है इसलिए आपको इस बारे मे पता होना चाहिए। दो तीन साल जो हरियाणा मे मद्य निशेध रही तो उसकी वतह से बहुत सरकारी नुकसान हुआ, मै यह नही कहना चाहूंगा कि उनको कितना फायदा हुआ लेकिन सरकार को जो नुकसान हुआ था तो वह भी हमें ही झेलना पडा था। स्पीकर सर, आगे मै आपको बताना चाहता हूं कि यह पूरो कैसे होगा? स्पीकर सर, यह डिपैंड करता है कि आपकी विल पावर कैसी है, आपकी इच्छा भाक्ति कैसी है कैसी आप पालिसी बनाते है। कैसे प्रोग्राम आप लोगो को देते है, और क्या आप पर व्यापारियो का या मैनुफैक्चर्ज

का वि वास है या नही? क्या आपने व्यापारियो को ऐसा एनवायरमैंट दिया है जिसमे वे आपको सहयोग कर सके। अगर आपने उनको ऐसा एनवायरमैंट दिया है तो वे टैक्स पे करने के लिए तैयार होगे। स्पीकर सर, मुझे यह कहते हुए गर्व है कि आपकी सरकार ने ऐसा ऐनवार्यमैंट पैदा किया है ओर करो का सरलीकरण भी इस तरीके से किया है ताकि व्यापारियो को दफतरो के चक्कर न काटने पडे इसलिए हमें उम्मीद है कि यह घाटा पूरा होगा और राजस्व करो की प्राप्ति होगी। स्पीकर सर, इसी तरह से हुडडा साहब ने और मांगे राम जी ने वैल्यू ऐडेड टैक्स की बात कही। वैट का जहां तक सवाल है हमने एक व्यवस्था को बदला है। जो हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स है उसकी जगह वैट को रिप्लेस किया है। मै आपको बताउंगा कि कितनी चीजो पर रेट बजाए बढने के घटे है। एक व्यवस्थ ऐसी बन गयी कि किसी भी स्टेज पर आप कोई भी बिका हुआ माल छिपा नही सकते। इसी तरह से इसमे अब ट्रांसपेरैंसी आ गयी है जिसके कारण पैसा बढा है। हुडडा साहब बोलते हुए यह भी कह गए कि यह तो आम बात है। 358 करोड रुपये बढा है। स्पीकर सर, पहले इन्होने बताया कि 2001 मे 371 करोड रुपया बढा था और 2002 और 2003 मे जो 358 करोड रुपया बढा था वह टोटल रैवेन्यू था। इस तरह के टैक्सिज का था लेकिन इसमे न तो सैंट्रेल सेल्ज टैक्स आता है और न ही इसमे हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स का है। इसको हमने रिप्लेस किया है। हमने न तो सी एस टी को रिप्लेस किया है और न ही एल ए डी टी और न ही पैसेंजर टैक्स

को रिप्लेस किया है। जो टैक्स की सारी रिसीट थी आप उनके बारे मे बात कर रहे थे। (विघ्न) वैट की वजह से 22 परसेंट की इंक्रीज आयी है। यह दिसबर तक की थी। अब जनवरी के महीने मे यह 25 परसैंट हो चुकी है। स्पीकर सर, अगर आप कहे तो मै ये आंकडे भी दे सकता हू। अब 25 परसैंट इंक्रीज हो गयी है। इसी तरह से इन्होने चलते चलते धान के बारे में जिक्र कर दिया। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंहः स्पीकर सर, इनको यह भी बताना चाहिए कि वैट लगाने के बाद तीन साल के बाद कितना सैल्ज टैक्स मिलेगा?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, इस पर बहुत ऐकेडमिक डिबेट चली थी। सभी स्टेटस के फाईनैंस मिनिस्टर्ज इकठठे हुए थे। उन्होने इसको लागू कर लिया और अदरवाइज वहा ंपर 25 स्टेट लेजिस्लेटिव असैम्बलीज ने इसको पास किया है, सारे मानकर आये है और उनमे से 16 स्टेटस ने क्या किया, जो सैंन्ट्रल एक्ट से संबंधित चीजे थी जैसे कम्पनीज एक्ट, फैक्ट्रीज एकट उनमे अमैडमैंट कर दिया, इस वजह से राश्ट्रपति महोदय को भेजना पडा। आज उनका वैट का कानून राश्ट्रपति जी के पास पैंडिंग है And they are waiting for it कि वहां से क्लीयर हो कर आएगा कितना प्रोफिट होगा लेकिन हमने कंपनीज ऐक्ट की, फैक्टरीज एक्ट की अमैडमैंट तो नही दी और गवर्नमैंट आफ इंडिया को भेजा ताकि दूसरी स्टेटस से डिफर न हो। गवर्नमैंट

आफ इंडिया की होम मिनिस्ट्री इसको कोआर्डिनेट करती है वहां से क्लीयर हो गया, फाइनैंस मिनिस्ट्री से क्लीयर हो गया, सभी मिनिस्टर्ज से क्लीयर हो गया और लागू कर दिया। वे लोग इस वजह से नही कर पए क्योकि उनकी राजनीतिक इच्छा भाक्ति नही थी। दिल्ली के और राजस्थान के मुख्यमंत्री खडे होकर यह कहते थे कि हमारे यहां चुनाव आ रहे है। इसलिए इस बार इसको रोक दो। यह पहले एक अप्रैल 2002 को लागू होना था फिर 2003 से लागू होना था फिर कहने लगे कि अप्रैल 2004 कर लो, अब अप्रैल 2004 भी आ जाएगा थोडे दिनो में। हमें उम्मीद है कि यह सब जगह होगा ही। अध्यक्ष महोदय, उनकी राजनीतिक इच्छा भाक्ति कमजोर थी इस वजह से भाग गये वरना तो इससे बढिया सिस्टम हो ही नही सकता। इस बात के लिए श्रेय देना चाहिए हरियाणा प्रदे ा के मुख्य मंत्री जी को जिन्होने कि एक इच्छा भाक्ति निभाई और बकायदा उसको लागू किया। मै यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले साल के अंदर बहुत सी स्टेटस इसको फोलो करेगी और उनको फोलो करना पडेगा। मेरे साथी पडोसी प्रदे ाो की बात कर रहे थे। पंजाब की बात कर रहे थे पंजाब के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नही है। 15–20 तारीख को कही जाकर तनख्वाह मिलती है लोन एंड वेजिज की लायबिलिटी 125 परसैंट हो गयी है आपके पास तो फिर भी 20–25 परसैंट प्लान के लिए बच जाता है उनके पास एक नया पैसा नही बचता है उनके यहां तनख्वाह भी कर्ज से दी जाती है। प्लीज फोन दी गौड सेक पंजाब से हमारे साथी मुाबला न करे जहां तक पर कैपिटा इंकम की बात

हे तो कोई एन आर आई है कोई और है वह अलग बात है। पहले पंजाब प्रदे ा कितना विकसित था। थोडे दिनो मे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि हमारी पर कैपिटा इंकम कितनी बढिया होगी। पंजाब का जिक्र हमारे साथी न करे। इसी तरह से मांगे राम जी ने और हुडडा साहब ने धान का जिक्र किया। वर्श 2002–03 मे धान की जो हरियाणा में मंडियो मे आवक हुई 30.29 लाख टन और 2003–04 में 35.55 लाख टन हुई। 5.5 लाख टन धान की आवक ज्यादा हुई है आपने तो कह दिया कि 5 लाख टन धान की आवक पंजाब से ज्यादा हुई है। पंजाब हम से काफी ज्यादा प्रोडयूस करता है इसका मतलब परसैंटेजवाइज़ हरियाणा की मंडियो मे ज्यादा धान आया है। केवल मात्र सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए ये साथी बात करते है। (शोर एवं विघ्न) अगर ये कहे तो मै इनको रसीद दिखा दूं। इन्होने बोल तो लिया। 5.5 लाख टन ज्यादा हुआ है पंजाब के हिसाब से (शोर) मै बता रहा हं कि हरियाणा मे यह रेंज है वह। (विघ्न)

श्री भुपेंन्द्र सिंह हुडडाः स्पीकर सर, **********

श्री अध्यक्षः जो सदस्य चेयरमैन साहब की परमि ान के बगैर बोलता है उसकी कोई बात रिकार्ड न की जाये।

प्रो0 सम्पत सिंहः हरियाणा की रेंज 1100 से 1450 है जबकि पंजाब की रेंज एक हजार से 1400 तक है। इस प्रकार हरियाणा मे महंगा बिक रहा है पंजाब से। दूसरी एक बात मै

कहता हूं कि यह हरियाणा बनने से आज तक इतिहास रहा है जो कि टैक्स है (विघ्न) आज कुछ ऐसे लोग इकटठे हो गये जिनको ज्ञान नही है। स्पीकर सर, एक बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वह मै बताना ाहता हूं कि हरियाणा 1966 में बना था और 1996 से 1999 तक जब चौधरी बंसी लाल जी की सरकारी थी जितने भी टैक्स थे चाहे वह जनरल टैकस हो या सी एस टी हो सारे टैक्स से 16914 करोड रुपये इकटै हुए है जब से हरियाणा बना है और 1998–99 तक ओर उसके बाद जो आपने व्यवस्था स्थापित की है जिसमे व्यापारियो से, ट्रेंडर्स से, मैन्यूफैक्च्र्ज` जिनहोने आपको को आप्रेट किया है उसकी वजह से जनवरी, 2004 तक 18851 करोड रुपये टैैक्स इकटठा हुआ है जबकि 1966 से 1998 तक 149614 करोड हुआ है। अगर इसकी टोअल ऐवरेज निकाले तो सारा जोडकर अब तक 18851 करोड रुपये टैक्स इकटठा हुआ है। पहले यह पैसा लोगो की जेबो मे जाता था अब सरकारी खजाने मे जाता है। (विघ्न) इसी तरह से स्पीकर सर, एक जो वैट सिस्टम प्रणाली के बारे मे इन्होने कहां जिन चीजो पर घटा है सरकार ने छूट दी है उन चीजो के बारे में मै बताना चाहूंगा। यह जीरो से 4, 8, 12.5 को स्लैब पर 10 प्रति ात जिसका जिक मैने नही किया क्योंकि जनरल रेट आफ टैक्स आलमोस्ट दस प्रतिशत हो आता है इसलिए स्लैब इसमे रखा है और सरकार ने इसमें अपने अनुसार थोडी अमैडमैंट भी की है। ताकि स्टेट को ट्रेड सफर न करे। दूसरे बर्फ, बांस, जलाउ लकडी और लकडी बुरादे पर टैक्स 8 प्रति ात से चार प्रतिशत घटा है। मसाले पर 10 प्रति ात से 4

प्रति ात घटा है। हैंड पम्प और उसके पार्टस पर 8 प्रति ात से 4 प्रति ात घटा है। मोबाईल सैट ओर सैल्यूलर फोन पर 12 से लेकर 4 प्रति ात घटा है। पोल्ट्री फीड सप्लीमैंटस ओर केटल फीड सप्लीमैंटस पर दस प्रति ात से चार प्रति ात घटा है। प्लास्टिक के कच्चे माल पर जैसे पी वी सी कम्पोनैंटस पर दस से चार प्रति ात और पी वी सी रेजिंग और प्लास्टिक के पोलीमर पर, कच्ची रबड और रबड के कैमीकल्ज पर दस से चार प्रति ात और कार्बन ब्लैक पर दस प्रति ात से चार प्रति ात धटा है। बायो गैस प्लांट से प्रयुक्त म ाीनरी पर और बायो गैस बर्नर और बाये गैस हार्ड प्लेट को कर मुक्त कर दिया है और बायो गैस खाद और जिप्सम पर दस प्रति ात से चार प्रति ात कर दिया है। परानी कारो पर जिसमे एक हजार सी सी की गाडियो है। 12 प्रति ात से धटाकर तीन हजार रुपये सैलज टैक्स कम कर दिया है। वेट के उपर वि ोश आर्थिक स्कीम, निर्यात इकाई स्कीम आदि आदि निर्यात के सिलसिले मे विक्रय के लिए विनिर्माण के प्रयोग हेतु माल बिना कर दिये खरीद सकते है। टायर टयूब की दस प्रति ात से आठ प्रतिशत कर दी गई है। ये कह रहे है कि बढाया, हमने तो घटाया है। बिजली का सामान जो उद्योगो मे प्रयोग होता है इस प्रति ात से धटाकर चार प्रतिशत कर दिया है। रासायनिक खाद कर मुक्त है। विमान टर्बाइन इंजन, पैट्रोल गैस, तीव्र गति डीजल, सुपर लाईट डीजल, आयल लाईट डीजल, आयल मिटटी का तेल, सरल पैट्रोलियम गैस, लो सल्फर हैवी स्टोक, बेरनस आयल इसी तरह के सभी आयल एक कंपवनी दूसरी

कंपनी को बेचेगी तो कर की दर केवल चार प्रति ात होगी। स्पीकर सर, इसमे हमने रियायत दी है इसको घटाया है, कहीं बढाया नही है। जो ये बढाने की बात कर रहे थे वो यूजर चार्जिज की बात कर रहे थे। हमने तो कई चीजो पर घटाया है। स्पीकर सर, अभी कल लेजिस्ले ान आयेगा और मुख्यमंत्री जी ने पहले घाशणा कर दी कि कैबिनेट ने उसको एप्रूव कर दिया है। स्टाम्प डयूटी जो पहले 12.5 प्रति ात थी उसको कम करके 6 प्रति ात किया गया है। इसी तरीके से भाहरो में जहां 15.50 प्रति ात ये 16 प्रति ात थी उसको कम करके 8 प्रति ात किया गया है। स्पीकर सर, इसी तरीके से मार्टगेज वगैरह, ट्रांसफर फीस आदि को भी कम करके आधा रेट कर दिया गया है। इस तरह से इस सरकार ने घटाने का काम किया है बढाने का काम नही किया। बढाया है तो रैवेन्यू बढाया है और टैक्सिज घटाकर बढाया है ताकि एक अच्छा माहौल बनाया जा सके। स्पीकर सर, अब जो नुकसान हो रहा है हरियाणा प्रदे ा का वह सैंटर के फैडरल सिस्टम लागू होने से हो रहा है। इसके तहत सैंटर को सेंट्रल टैक्सिज इनका वगैरह से आमदनी तो सभी स्टेटज से होगी। हरियाणा सरकार भी एक्साईज डयूटी पे कर रही है, हिमाचल प्रदे ा, यू पी, पजाब यानि सभी स्टेटस एक्साईज डयूटी पे करते है और बदले मे इनको फैडरल सिस्टम के मुताबिक पैसे का डिस्ट्रीब्यू ान होता हैं से स्टेटो से जो पैसा आता है और सबको जाता भी है। अब इसमे क्या कर दिया ब्लू वाईट स्टेटस जैसे हिमाचल प्रदे ा मे चुनाव आएगा, ठीक है अपने लंगर कस लो,

चुनाव जीतना है इसलिए इस स्टेट की इंडस्टरी की एक्साईज डयूटी माफ कर दो, इंकम टैक्स माफ कर दो। इसका डायरैक्ट असर किस पर पडेगां। हरियाणा पर ही पडेगा। वे कोई ऐक्साईज डयूटी पे नही करेंगे लेकिन जब फंडस का डिस्ट्रब्यू ान होगा उनको भी मिल जायेगा। उनको डबल फायदा होगा एक उन्होने देना नही बल्कि ले लेना है। स्पीकर सर, इस तरह से सैंटरल गवर्नमैंट के इस बजट मे मुझे बउी हैरानी हुई कि इंकम टैक्स मे रियायत देनी चाहिए थी लेकिन उन्होने हाउसिंग बोर्ड, मार्केटिंग कमेटीज, एच आर डी एफ, पर इंकम टैक्स लगाने की योजना बनाई है जो कि बडा घातक फैसला है। इसको न लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार सैंट्रल सरकार को लैटर भी लिखे है। (विघ्न) इससे बहुत बडा नुकसार होगा। जहां हमें 800–800 करोड रुपये मार्किटिंग बोर्ड से, 700 करोड रुपये एच आर डी एफ से आ रहा था आज उन पर भी भारत सरकार इंकम टैक्स लगाने जा रही है। अर इन पर इंकम टैक्स लगाया गय तो भुगतान तो हमें ही पडेगा और बदले में फायद बीमारु स्टेटस ले जाएंगी। मै तो यही चाहता हूं कि मेरे सभी साथी भारत सरकार से अपील करे कि हरियाणा प्रदे ा को मत मारो। क्योंकि इन चीजो पर इंकम टैक्स वे लगा रहे है। (विघ्न) स्पीकर सर, केन्द्रीय सहायत भी हमें कम मिली है। बार बार हर प्लेटफार्म पर यह आवाज हम उठाते है। पीछे श्रीनगर मे इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग थी उससे पहले हर साल एन डी सी की मीटिंग होती है। हर मीटिंग के अंदर माननीय मुख्यमत्री महोदय जी ने इन बातो को

उठाया है कि भारत सरकार स्टेट के संसाधनो को कम कर रही है और सैंटर अपने संसाधन बढा रही है। स्टेटस को ऐसे समझा जा रहा है जैसे ये भिखमंगी हो। ये सैंटर से मांग मांगकर ले जायेंगी। ऐसा फैडरल सिस्टम मत करो इससे नुकसान होता है खासकर से उन स्टेटस को जो परफार्मिंग स्टेटस है। उनको आप प्रताडित करते हो और नोन परफोर्मिंग स्टेटस को उत्साहित करते हो। अध्यक्ष महोदय, ये मुददे बार बार हर प्लेटफार्म पर माननीय मुख्यमत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने उठाये हैं। इन चीजो की हमें कमी हुई है उसके बारे में भी मै बताना चाहता हू कि खास तौर पर से मेरे सीनियर साथी राव इंद्रजीत को। उन्होने एक बात फरमाई कि जो इलवैन्थ फाईनेंस कमी ान था उसको डिवोल्यू ान आफ फण्ड पहले वाल साम के मुकाबले में कम हैं। यहां पर हरियाणा प्रदे ा को सहायता देने की बात भी कही गयी है कि वो डिवोल्यू ान आफ फण्ड की एलोकेट पहले 1.238 परसैंट थी। मै सदन को बताना चाहता हूं कि ऐसी बात नही है। यह वर्श 2002 से 2005 तक की बात है। उन्होने अपनी 2002 मे रिपोर्ट दे दी जबकि खर्च तो बाद में हुआ। इसमे अधिमान किसाको दिया यानि वेटेज किसको दी। उन्होने पर कैपिटा इंकम को माना। इसमें रिवस हुआ। अगर आपकी इंकम ज्यादा है तो कम मिलेगा और अगर आपकी इंकम कम है तो ज्यादा मिलेगा। हरियाणा मे पर कैपिटा इंकम ज्याद है। पंजाब महाराश्ट्र ओर गोवा मे भी पर कैपिटा इंकम ज्यादा है। इन सभी स्टेटस को नुकसान हुआ। उन्होने वेटेज को साढे बारह परसैंट माना है, पापुले ान

को बीस परसैंट माना है, एरिया को पांच परसैंट माना है और फिजिकल मैनेजमैंट को साढे सात परसेंट माना है। इस प्रकार से उन्होने 100 परसेंट की डिवोल्यू ान की है। मै राव साहब को बताना चाहूंगा कि इस तरह की कोइ बात नही है कि कही पर खर्च में कमी थी। उन्होने हमारे को क्या मान लिया वह भी मै आपको बताना चाहूंगा। उन्होने हमारे को सरप्लस स्टेट मान लिया। मै समझता हूं कि रैवैन्यू डैफिसिट 3500 करोड रुपये था। इन्होने कह दिया कि आप का तो 1500 करोड रुपये सरप्लन है, इस बात का मुझे बड अफसोस है। यह मान करके यह निर्धारण किया और इस मापदण्ड से 1100 करोड रुपये से फालतू का नुकसान हो लिया है और डेली का नुकसान अलग से हो रहा है। स्पीकर सर, सही मायनो मे डिस्ट्रीब्यू ान सैंन्ट्रल टैक्सिज की जो आनी चाहिए थी वह 2776 करोड रुपये की आनी चाहिए लेकिन हमारे पास इसमे से 2323 करोड रुपये आए यानि 45 करोड रुपये कम आये। इसी तरह से जो केन्द्र से आम सहायता मिलती है वह 1068 करोड रुपये के मुकाबले मे 973 करोड रुपये कम मिली है। इसी प्रकार से सैंटरल स्पोसड स्कीम मे जहा हमें 1300 करोड रुपये आने चाहिए थे वहां पर हमें 756 करोड रुपये आये यानि इसमे भी हमें 544 करोड रुपये कम आये। स्पीकर सर, पैट्रोल और डीजल पर बहुत ध्यान देने की जरुरत है। भारत सरकार ने पैट्रोल और डीजल पर सैस लगाया है। इस सैस की वजह से भारत सरकार को हरियाणा प्रदे ा से 1100 करोड रुपये की आमदनी हुई है। यह पैसा किसका गया है, यह पैसा तो हरियाणा प्रदे ा

क`लोगो का ही गया है। कंजम्प ान तो सारी यही पर हुई है। अगर यही टैक्स हमारा अपना होता तो 1100 करोड रुपया हमें मिलता। वाही वाही वो लूटने की कोि ा ा करते है जबकि पैसा हमारा है। यहां पर एक साथी ने कहा कि माल किसका कमाल किसका। मै उस साथी को बताना चाहूंगा कि माल हरियाणा का और कमाल सैंटर का। सैन्ट्रल गवर्नमैंट इस सैस का 1100 करोड रुपया यहां से ले गई और बदले मे सिर्फ 174करोड रुपये दिया है। फिफ्टी फिफ्टी परसैंट डिस्ट्रीब्यूट करते है। यानि इस सेस मे जो कुल आयेगा उसका 50 परसैंट पैसा तो ट्रांसपोर्ट मीनिस्टर को जाएगा और 50 परसैंट पैसा रोड लिंकेज के लिए जायेगा। अब क्या यह हमारी बदकिस्मती है कि हमारा हर गांव सडक से जुडा हुआ है। वे यह नही देखते कि रोडज कब की बनी हुई है जबकि आज उन सडको की मैंटेनैंस की जरुरत है, उनकी वाइंडनिंग की और स्ट्रेग्थन करने की जरुरत है। लेकिन उसके लिए नही बल्कि बीमार स्टेट को ज्यादा दे करके हमें 1100 करोड रुपये मे से सिर्फ 174 करोड रुपया दिया। हमारा पैसा हमें देने की बजाये दूसरी स्टेटस को गया है। हमने तो अपने संसाधनो से काम लिया है वरना तो हमारा साढे तीन हजार करोड रुपये ओर सैंट्रल गवर्नमैंट से लेना बनता है जो हमें नही मिला यानि हमें कम आया है। यहां पर साथियो ने बोलते हुए सडको के बारे मे जिक किया कि वर्तमान सरकार ने सडको की मरम्मत पर कोई ध्यान नही दिया। वर्श 2004–05 मे इसके लिए 320 करोड रुपया रखा गया है तथा 180 करोड रुपया मार्किटींग बोर्ड का इससे अलग है। वर्श

1999–2000 मे सडको के लिए कितना पैसा था वह भी मै आपको बताना चाहूंगा। उस वक्त सडको के लिए सिर्फ 20.32 करोड रुपये था। चौधरी भजन लाल जी जब वर्श 1991–92 से लेकर वर्श 1995–96 तक जब मुख्यमंत्री रहे तो इनहोन सउको पर टोटल पांच साल मे केवल 68.90 करोड रुपया खर्च किया था जबकि आपकी सरकार के वक्त मे इस काम पर 496.54 करोड रुपया खर्च हुआ है। कहां 20 करोड रुपया और 70 करोड रुपये के करीब और कहां 496 करोड रुपया खर्च हुआ। इसके अलावा मार्किटिंग बोर्ड का जो 716 करोड रुपये खर्च हुआ वह अलग से है। यानी इस तरह से कुल मिलाकर सडको पर आपकी सरकार ने 1213 करोड रुपये खर्च किए। मेरा कहना यह है कि हमने सडको पर पैसा कम खर्च नही किया। यहां पर हुडडा साहब ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की स्कीम थी सडको के लिए कम ब्याज पर कर्जा देने की। हुडडा साहब ने कहा कि वर्ल्ड बैंक से लोन नही लिया जबकि यह सस्ता लोन था। अध्यक्ष महोदय, सडको के लिए सस्ते ब्याज पर कर्जा देने की वर्ल्ड बैंक की स्कीम थी यह स्कीम 690 करोड रुपये की थी और आपने इस स्कीम को छोड दिया और महेंगे ब्याज पर कर्जा लिया। स्पीकर सर, हमने हुडको से भी ब्याज पर लोन लिया और जगहो से भी लोन लिया। स्पीकर सर, आपको मालूम है कि 11 मई, 1998 को पोखरण न्यूकलीयर टेस्ट के तुरंत बाद अमेरिका ने इकोनोमिक सैंक ान लगा दी थी तो स्वाभाविक बात है कि आपको कर्जा नही मिला क्योंकि सब जगह सैंक ान लगी हुई थी। किसी भी स्टेट को कर्जा नही मिला सब जगह सैक ान लगी हुई

थी। इस बात को जानते हुए भी वे इस बात को उठा रहे है इसलिए हमने यह सोचा कि अगर वर्ल्ड बैंक कर्जा नही दे रहा न दे कोई बात नही। हमारे पास अगर साधन है किसी को अगर हम पर वि वास है, हमारे घर के अंदर कोई दाम है तभी कार्ज कोई दे रहा है। हमारी सोच है कि ऐसा नही होना चाहिए सउके टूटी हुई हो और लोग रोज मरते रहे इसलिए हुडडा साहब इसके लिए हमने 323 करोड रुपये का कर्जा लिया। इसमे कोई दो राय नही कि यह कर्जा हमने वर्ल्ड बैंक की सैक ान लगने की वजह से लिया। (विघ्न)

श्री भुपेन्द्र सिंह हुडडाः अध्यक्ष महोदय, वित मंत्री महोदय से मै निवेदन करुंगा कि वे कृप्या यह बताए वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए आपने कुछ पैसा कन्सलटैंसी के लिए भी दिया था, वह क्यों दिया था?

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै इनको बताना चाहूंगा कि वह तो पहले ही हो गया था लोन के लिए कोई पेपर्ज वगैरह तैयार करने पडते है और वह सब तो पहले ही हो लिया था वह हमने नही किया था। अध्यक्ष महोदय, मै माननीय हुडडा साहब की एक एक बात का जवाब दे रहा हू। इसके साथ ही इन्होने स्पै ाली पंजाब ट्रांसपोर्ट के बारे में कहा कि we are paying more passengers tax in Punjab than the K.ms we are running in the Punjab. Roughly Passengers Tax for one lac Kilometers inPunjab Something हुडडा साहब ने कहा था।

स्पीकर सर, जहां तक सवाल है पिछले अप्रैल ओर जनवरी, 2004 का हरियाणा रोडवेज 335.12 लाख किलोमीटर पंजाब टेरेटरी मे हमारी बसो ने आपरेट किया है और 796 लाख स्पे ाल रोड टैक्स आया है। ऐप्रोक्सीमैटली 2.38 प्रति ात टैक्स आया है payable in Punjab territory था वह 2.99 पर किलोमीटर भाो कर रहा है कि कोई एक्सैस पेमैंट नही की गई है बल्कि कम पेमैंट की है। दूसरी बात इन्होने यह कही Ministery of Roads and Transport Highway Government of India ने 2002–03 के अंदर के एम पी एल खर्च होता है। अध्यक्ष महोदय इसके साथ पंजाब को राजस्थान के साथ कम्पेययर किया। अब राजस्थान का कम्पैरिजल हम कैसे करेंगे। हमारा पहले था 4.54 और आज बढ कर हो गया है 4.77। स्पीकर सर, हमने इसमे सुधार किया है। हमने नई बसे खरीदी है। जब से हरियाण बना है तब से लेकर आज तक किलोमीटर के हिसाब से सब से ज्यादा पर लीटर हमारी बसें चल रही है 4.77 और राजस्थान में 4.88 है इसलिए राजस्थान का ज्यादा आ रहा है क्योंकि वहां पर लोकल रुट की बसे नही चलती है। राजस्थान की बसें नै ानल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पर चलती है। (विघ्न)

श्री भूपेंन्द्र सिंह हुडडाः वित मंत्री जी, जो पंजाब की पैसेंजर टैक्स की बात है वह मै नही कह रहा हूं यह आपकी सी ए जी 2002 की रिपोर्ट मे पेज 122 पर दिया हुआ है।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै पहले सी ए जी की रिपोर्ट का ही जवाब देता हू। जहां तक सी ए जी की रिपोर्ट का सवाल है, सी ए जी ने तो अपने कमैंट्स दिए है। इसमें कोई दो राय नही कि इसके बाद इसमें डिफरैंस डिपार्टमैंट अपना जवाब देते है फिर पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी/ पब्लिक एकाउंटस कमेटी के पास मामला जाता है वहो पर डिस्क ान होती है और यह रिपोर्ट पास होती है। यह तो केवल सी ए जी की आब्जर्वे ान है, इसके बाद इस पर गहन मनन होना है, उसके बाद उपर जवाब दिया जाएगा और अंतिम निर्णय होगा। इनको यह भी मालूम नही ळै कि सी ए जी की रिपोर्ट पर डिस्क ान कब करनी चाहिए, बडे अफसोस की बात है अब इसमे हम क्या करे। मैने स्थिती बता दी है। स्पीकर सर, राजस्थान के साथ हमारा कोई कम्पैरिजन नही है और जो हमारा डिफरैंस है वह मात्र 0.11 का है और वह भी इसलिए है कि राजस्थान नै ानल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पर ही बसे चलाते है जबकि हमारी बसें गावों तक जाती है। हमारी बसे तो गावो मे इन्टीरियर तक जाती है इस वजह से इतना फर्क है। स्पीकर सर, इन्होने एक ओर बात कि आपने ट्रैक्टर ट्रालीजपर टैक्स बढा दिया। मोटर व्हीकल ऐक्ट गवर्नमैंट आफ इंडिया का है ओर यह टैकस गवर्नमैंट ने बढाया है and we are bound by that. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जय प्रका ा जी, आप अपनी सीट पर बैठें। आपका कोई प्वायंट आफ आर्डर नही है। प्रोफेसर साहब, क्लीयर

कर रहे है। इसमे जो कुछ भी किया है वह केन्द्र सरकार ने किया है, स्टेट गवर्नमैंट ने कुछ नही किया है। (विघ्न) आप अपनी सीट पर बैठे।

प्रो0 सम्पत सिंहः यह जो ड्राइविंग लाईसैंस की बात कर रहे है तो यह मोटर व्हीकल एक्ट, गवर्नमैंट आफ इंडिया के अंडर आता है। यह फीस हमने नही बढाई है। टैक्स आन रजिस्ट्रे ान स्टेट गवर्नमैंट के अंडर नही है। इन्होने कहा है कि Tax on Maxi Cab has been increased. पहले जो टैक्स लिया जाता है तो वह 150 रुपये प्रति सीट के हिसाब से लिया जाता था, इसको हमने घटा कर 100 रुपये प्रति सीट कर दिया है। (इस समय मेजे थपथपाई गई।) (विघ्न) इस तरह से इन्होने कहा है कि नम्बर आफ टयूबवैल्ज घट गए है। अब पता नही ये आंकडे कहां से लाते है इन्होने 1998–99 मे 3 लाख 61 हजार 454 के आंकडे बताए है। 1999–2000 के 3 लाख 53 हजार 899 का फिगर बाताया है, अब ये कनैक ान बढकर 3 लाख 79 हजार 099 हो गए है। इसमे 26 हजार 800 की बढोतरी हुई हैं ये कहते है कि आंकडे घटे है। जबकि हमने टयूबवैल्ज के कनैक ान 36 हजार 858 बढाए है। डयूज की वजह से, डिस्कनैक ान की वजह से और अगर कही पर खारा पानी आता है तो कनैक ान कटवाया ही जाएगा। (विघ्न) हमने 36 हजार 858 कनैक ान दिए है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः जय प्रका ा जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (विघ्न)

चौधरी जय प्रका ाः * * * * *

श्री अध्यक्षः जय प्रका ा जी जो भी बोल रहे है वह कुछ भी रिकार्ड नही किया जाए। (विघ्न) जय प्रका ा जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, अब मै टी एण्ड डी लोसिज के बारे में कहना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः जय प्रका ा जी, आप इस तरीके से बीच में मत बोलें, मंत्री जी जवाब दे रहे है। (विघ्न) कादियान साहब, आप अपनी सीट पर बैठ जाए।

डा0 रघूबीर सिंह कादियानः * * * * * * * *

श्री अध्यक्षः कादियान जी, जो कुछ भी बोल रहे है वह कुछ भी रिकार्ड नही किया जाए।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, अब मै टी एंड टी लोसिज पर आ रहा हू। (विघ्न) टी एंड डी लोसिज पहले 17.8 था और नार्म्ज के हिसाब से लोसिज15.5 के होने चाहिए। स्पीकर सर, हरियाणा मे एक रैगुलेटरी कमी ान है। हमारी सरकार के आने से पहले जो लोसिज होते थे उस लोसिज को अनमीटर्ड सपलाई के खाते में खपा दिया जाता था। उस समय यह किया जाता था कि इतने प्रति ात खपत हुई है तो उतना ही प्रति ात फार्मर्ज पर डाल दिया जाता था। स्पीकर सर, फार्म्ज के जिम्मे सारे का सारा

पैसा डाल दिया जाता था। लेकिन सर, आज वह बात नही रही है। आज रैगुलेटरी कमी ान है, वह एक एक चीज को मानीटर करता है। स्पीकर सर, कुछ सदस्यो ने बोलते हुए यह कहा कि खपत 7 और 8 घंटो की है। मै इनको यह बताना चाहूगा कि रैगुलेटरी कमी ान उसको भी खपत नही मानता है। उसका कहना है कि अगर 4 और 5 घण्टो की एवरेज लेंगे तो उसको माना जाएगा। स्पीकर सर, 2001–02 मे 40.19 प्रति ात खपत मानी गई है। हुडडा जी, उसके बाद हमने इसको 3 प्रति ात घटाया है। 2002–3 मे यह खपत घटकर 32.27 प्रति ात रह गई थी। Nothing is hidden. हम कोई चीज छिपाते नही है और हर साल हम उसको घटाएंगे। हम ट्रांसमि ान सिस्टम को मजबूत करेंगे। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यू ान सिस्टम है इसको भी ठीक करैंगे। जो नए सब–स्टे ाज बन रहे है, जितने भी ट्रांसफामज बदले जा रहे है। (विघ्न)

डा0 रघुबीर सिंह कादियानः ********

श्री अध्यक्षः ये जो भी बोल रहे है वह कुछ भी रिकार्ड नही किया जाए।

डा0 रघुबीर सिंह कादियानः ********

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मै सदन मे यह बताना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार होती थी, उस वक्त ये एक नया पैसा भी खर्च नही करते थे। हमारी सरकार के वक्त मे लाईने

बादली जा रही है। ट्रांसमि ान सिस्टम मजबूत किए गए है और सब–स्टे ांज बनाते जा रहे है। स्पीकर सर, इसलिए वह स्वाभाविक है कि ये लोस नीचे आंएगे। इन्होने जो पंजाब के लोस 15 पति ात बताए है तो मै इनको यह बताना चाहूंगा कि वह 26 प्रति ात है। यह भी इसलिए है क्योंकि उनके पास ऐग्रीकलचर का खाता नही है। स्पीकर सर, जहां तक बिजली की प्राप्ति की बात है तो यह 561 लाख यूनिट की ऐवरेज है। (विघ्न) पहले जो ऐवरेज थी वह 367 लाख यूनिट की थी, अब इसमें 53 प्रति ात की इंक्रीज हुई हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः रघुबीर सिंह जी, आप बीच मे बिना इजाजत के न बोलें।

डा0 रघुबीर सिंह कादियानः **********

श्री अध्यक्षः कादियान जी, जो भी बोल रहे है वह कुछ भी रिकार्ड न किया जाए। (विध्न) डाक्टर साहब, आप अपनी सीट पर बैठे।(विघ्न)

डा0 रघुबीर सिंह कादियानः **********

श्री अध्यक्षः कादियान जी, be cultured. इस तरह का व्यवहार न करे। इनकी कोई भी बात रिकार्ड न की जाए।

प्रो0 सम्पत सिंहः इसी तरह से स्पीकर साहब, यहां पर एच एफ सी का जिक्र किया गया है। (विघ्न)

श्री भुपेन्द्र सिंह हुडडाः अध्यक्ष महोदय, मैने पंजाब के लाईन लोसिज 17 परसैंट बताएं है जबकि ये 15 परसैंट बता रहे है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ये पढ नही रहे है बल्कि बोल रहे है। इसलिए जय प्रका ा जी आप बैठें।

प्रो0 सम्पत सिंहः हम मेहनत करते है इनकी तरह से नही है। स्पीकर सर, इसी तरह से इन्होने फाईनें ि ायल कारपोरे ान का जिक किया। (विघ्न) इन्होने कहा है कि फाईनें ि ायल कारर्पोरे ान ने सिर्फ 19.4 करोड रुपए ही लोन दिया है। स्पीकर साहब, आपको मालूम है कि जब से लिब्रलाइजे ान की पालिसी आई है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप बैठिए। आप विदआउट परमि ान नही बोल सकते। हुडडा साहब, आप इन्हे बैठाइये।

श्री भुपेन्द्र सिह हुडडाः स्पीकर साहब, आप उन्हे अपनी बात कहने ही नही दे रहे है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, **********

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, आप बैठें सबका जवाब आ रहा है। इनकी कोई बात रिकार्ड न करे। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, हुडडा साहब ने एक भाब्द एस वाई एल के बारे में कहा था। मै इस बारे मै पहले बता

देना चाहता हू क्योंकि बाद मे कही ये वाक आउट न कर जाए। इन्होने कहा था कि एस वाई एल पर एक पैसे का बजट हमने नही रखा। हुडडा साहब, आपने केवल न्यू एक्सपैंडिचर 2004–2005 ही पढा है आप सिर्फ बजट एक ए गलांस के चार पेज पढकर ही पार हो जाते हो। अगर आपने न्यू एक्सपैंडीचर 2004–2005 पढा हो तो बताए। मै आपको इसका पेज नंबर बता देता हू। आप इसका पेज नें 362 पढ लें और इसका 110 का सब हेड भी पढ लें। यह है– ''सतलुज यमुना लिंक प्रोजैक्ट कंस्ट्रक ान वर्क्स'' पिछले 6–7 सालो से एक करोड रुपये का ने ानल हर सरकार रखती आयी है चाहे वह आपकी सरकार थी चाहे उससे पहले की सरकार थी। (शोर एवं व्यवधान) इनका यह कहना कि एस वाई एल पर एक पैसा भी नही रखा, ठीक नही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सभी बैठे। आप सुनिए ये पिछला बता रहे है। वह रख रखाव के लिए होता है।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, वह नो ानल मनी है। अब ये अपनी बात की झेंप नही मिटा सकते। इसका मतलब ये स्टडी करके नही आते क्योंकि इन्होने कहा है कि एस वाई एल पर एक पैसा नही रखा है। लेकिन एक करोड रुपया नो ानल रखा है। हाउस के सामने मै खुले दिल से कहना चाहता ं कि जब इस बारे मे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा और वह कह देगा कि फलाना एजेंसी इसको बनाएगी तो हम इसके लिए पैसा देंगे। स्पीकर सर, पहले तो पैसा खुद ही लगाना पडता है बाद मे उका

रिठम्बर्समैंट भारत सरकार करती है। इसलिए पहले पैसा खर्च करने की बात है। एस वाई एल के लिए चाहे हमें ऐस्टीमेट के अंदर कितना ही सप्लीमैंट्र ऐस्टीमैटस पास करना पडे, हम करेंगे। चाहे इसके लिए हमें कितना ही खर्चा कम करना पडे, हम करेंगे। बकायदा हम एस वाई एल पर पैसे की कोई कमी नही आने देंगे। That is a notional money और नो ानल मीन आज नही बल्कि हर साल रखी जाती है। इन्होने कहा कि एक पैसा नही रखा है। (शोर)

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, ये मजबूरी मे कह रहे है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुडडा साहब, आप इस जोडी को बैठाइये। इनको पानी की क्या चिंता है? (शोर एवं व्यवधान) यह मांगे राम जी की तरह वित मंत्री है। मांगे राम जी पानी थोडे ही मांगेगे। (विघ्न)

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। *****

श्री अध्यक्षः इनकी यह बात रिकार्ड न की जाए। (शोर एवं व्यवधान) जय प्रका ा जी, आप बैठिए। (विघ्न)बलबीर सिंह, आप बैठिए। जय प्रका ा जी, आप बैठ जाएं।

प्रो0 सम्पत सिंहः सच्चाई हमे ाा कडवी होती है इसमे केाई दो राय नही है। (शोर एवं व्यवधान) अभी लीडर आफ दि

अपोजी ान ने फारेन डायरैक्ट इन्वैस्टमैंट का जिक्र किया कि कोई एक नया पैसा नही आया है। ये सैन्ट्रल मिनिस्टर का ब्यान 22.8.03 का है कि फारेन इन्वैस्टमैंट निल आया है। उस वक्त हमारे मैंबर जाकर के उनको मिले और कहा कि ये कैसे कह रहे है तब उन्होने कहा कि इनके रजिस्ट्रे ान के आफिसेस दिल्ली में है इसलिए हम कह रहे है। तो हमने कहा कि नही यह काई क्राइटेरिया नही है। हरियाणा गवर्नमैंट ने चिटठी लिखी है और उस चिटठी का जवाब न देना इसका मतलब क्या है कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचें। एक चिटठी लिखी है और उसका भी जवाब देने में मु कल हो गई। जुलाई 1999–2000 में फारेन इन्वैस्टमैंट 474 करोड रहा है, 2000–2001 मे 347 करोड, 2001–2002 मे 400 करोड, 2002–03 में 1399 करोड, मैसर्ज एफिन इंडिया 24 करोड, वाल्को इलैक्टिकल्स 29 करोड, एफएन इंडिया 1 करोड 16 लाख, ऐस्कोर्टस 14 करोड 26 लाख, मैसर्ज जी कैपिटल पहले साल 75 करोड, दूसरे साल 115 करोड, मैसर्ज होंडा स्कूटर्स पहले साल 115 करोड और दूसरे साल 85 करोड और तीसरे साल 100 करोड, डैंसो हरियाणा 204 करोड इसी तरह से अल्काटेल 37 करोड।

श्री भुपेंन्द्र सिह हुडडाः सम्पत सिंह जी, हमें आपका ध्यान रखना पडता है आपको वैसे भी बहुत पसीना आ रहा है अब आप और आंकडे न बताएं।

प्रो0 सम्पत सिंहः आप संतुश्ट है न। आगे इन्होने कह दिया कि इण्डस्ट्रीज का नम्बर घट रहा है। (शोर एवं व्यवधान) जहां तक उद्योग लगाने की बात है पिछले साल 198 नये बडे उद्योग और 4500 लघु उद्योग स्थापित हुए है। यह कहते है कि टोटल नम्बर सैंसिज धट रहा है। स्पीकर सर, ऐसा वक्त भी था जब केवल मात्र सबसिडी लेने के लिए, केवल मात्र एच एफ सी को अपनी जेबी संस्थान बनाने के लिए लोन लिए जाते थे और लेकर पार हो जाते थे। आज रोजाना हमें उनके नोटिस मिल रहे है, यह काम कर गई पहले की सरकारे और भुगत हम रहे है। और उस समय की इण्डस्ट्री की रोजाना आक ान हो रही है जो पहले की सरकारो के समय इण्डस्ट्री लगी थी वे एक दिन भी नही चली उन इण्डस्ट्रीज का पैसा खा गई पहले की सरकारे और आज वे संख्या की बात कर रहे है। जो इण्डस्ट्री इस सरकार के समय मे लगी है उनमे से एक भी इण्डस्ट्री बन्द नही हुई है और आज पानीपत मे पैट्रो कैमिकल्ज की इण्डस्ट्री स्थापित हो रही है जिससे दस हजार रुपये का एक्सपोर्ट हो रहा है ये सारी एचीवमैंट वर्तमान सरकार के प्रयास से हुई है। (विध्न) स्पीकर सर, कई माननीय सदस्यो ने कृशि बीाम योजना के बारे मे कहा कि बाजरे, ज्वार, चने और सरसो पर तो यह योजना लागू कर दी लेकिन गेहूं, धान और गन्ने पर इस योजना को लागू नही किया। स्पीकर सर, आप किसान है ओर आप इफको के चेयरमैन भी रहे है। इसलिए आपको इन सब बातो का ज्ञान है। मै माननीय सदस्यो को बतनाना चाहता हूं और ये इस भार्त पर मानने के लिए तैयार है

सरसो पर तो बीमा रखा है इसमे एक तो ब्लाक एज ए युनिट होना चाहिए। ब्लाक एज ए युनिट होकर जो नुकसान होगा, उसमे पहली पांच साल की प्रोडक ान की ऐवरेज ली जाएगी। मान लो कि 16 क्विंटल प्रति एकड आपकी पैडी की पैदावार हुई है और एक लाख एकड आपके पास जमीन है तो इस प्रकार 16 लाख टन क्विंटल पैदावार हो गई तो ठीक है अगर नही हुई तो उसको नुकसान मानेंगे। अगर उसमे से एक, दो, तीन, चार हजार एकड जमीन की फसल खराब हो गई तो एवरेज मे अगर आपकी फसल अच्छी हुई है तो और एवरेज ज्याद आ गई तो एक भी पैसा नही मिलेगा क्योंकि ब्लाक पूरी एवरेज के हिसाब से बनाया गया था। इसलिए सरकार ने हाई रिस्क की फसलो को इसमे लिया है। सरसो जो है वह एक मिनट के अंदर साफ हो जाती है एक सेकेण्ड के अंदर साफ हो जाती है। इसी तरह कपास में अगर सुंडी लग जाए तो वह खत्म हो जाती है। ये लो रिस्क की है। पिछले सालो के आंकडे चाहे आप गेहूं के ले ले, चाहे पैडी के ले ले और चाहे गन्ने के ले ेल इतना हाई रिस्क प्रीमियम आपको देना पडे इस कारण से इन फसलो को नही लिया वरना सरकार को इस मे कोई गुरेज नही था। आज इनको क्यों तकलीफ हो रही है। अगर किसी चीज का नाम चौधरी देवी लाल के नाम पर रख दिया जैसे देवी रुपक योजना ओर देवी रक्षक योजना है, क्या बुरा कर दिया सरकार ने देवी रुपक योजना लागू करके। अगर किसी कमेरे वर्ग का आदमी मर जाता है तो उस परिवार को सरकार की तरफ से एक लाख रुपये दिये जाते है जबकि बीमा

कंपनी को सरकार थोडा सा प्रीमियम देती है लेकिन बीमा कंपनी को उस परिवार को एक लाख रुपये देने पडेंगे। इसमे बुराई क्या है। बीमा कंपनी तो आज पछता रही है कि सरकार इतना कम प्रीमियम देती है लेकिन बीमा कंपनी को ज्यादा पैसे देने पडते है। ये यह नही कहते कि ऐसी स्कीम को तो ऐडोप्ट करना चाहिए जो कि जनता के वैल्फेयर की है। ऐसी स्कीमे तो सरकार के लिए रखी है जिनमे प्रीमियम ज्यादा देना पडे। जो लोग कम जोत के है और जो फार्मरज है उनको 50 प्रति ात का प्रीमियम सरकार देती है। (विघ्न) स्पीकर सर, 1985 मे यह एक तिहाई और दो तिहाई है ये स्कीमे पुरानी है इनको थोडा बढाया है इनके स्काप को भी बढाया है। इसमें एनीमल हस्बैंड्री, हार्टीकल्चर, हाउसिंग को भी भाामिल किया गया है। लोगो के जो लोसिज है, जो मार्जिनल फार्मर्ज है, जो कमजोर है उनको 50 प्रति ात मे से आधा सैंटर और आधा स्टेट बीयर करेगा ओर 50 प्रति ात उस फार्मर को खुद देना पडेगा। अब स्पीकर सर, जिस फसल के अंदर तपो नही है उन पर किसान प्रीमियम नही दे सकता। हमने तो उल्टा इन फसलो को अलग करवाया है पहले सब फसलो को भाामिल कर रखा था आप कोई फसल टाल नही सकते थे। यह केडिट जाता है हरियाणा सरकार को। मुख्यमंत्री जी बार बार मिले, कृशि मंत्री जी बार बार मिले और इन फसलो को अलग करवाया। हमने कहा कि इन तीन फसलो का हम बीमा नही करवाना चाहते और हमं खु ाी है कि हमारी बात मानी गई। यह हरियाणा सरकार की अचीवमैंट है। स्पीकर सर, इन्होने विविधीकरण का जिक किया कि

हम पहले नही बोले, आज बोल रहे है। इस बारे में मै इनको बताना चाहूंगा कि 19 मई, 2001 को मुख्यमंत्री का सम्मेलन दिल्ली मे हुआ था। उस सम्मेलन मे हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भाब्द कहे उसकी क लाईन मै यहां कोट करना चाहूंगा ज्यादा करुंगा तो चौधरी भजन लाल जी बैठे नही है वरना कह देते पढना भाुरु कर दिया। मुख्य मंत्री जी ने सम्मेलन मे कहा कि कृशि मे विविधीकरण केवल नारो और सुझावो से नही लाया जा सकता इसके लिए ढांचागत व संस्थागत प्रबंध करने होंगे। यानि 2001 मे आज से तीन साल पहले हमने यह मुददा उठा दिया था। उसके बाद 3.1. 2003 आज से एक साल पहले हमने 1920 करोड रुपये की स्कीम भारत सरकार को प्रस्तुत की थी और ये कह रहे थे कि गठबंधन टूटने के बाद हम ऐसी बात कर रहे है। बाद मे संबंधित अधिकारियो से विचार विम र्ा करके 1960 करोड किया जा कि 16 जुन, 2003 को भेज दी थी। मै इनको कहना चाहूंगा कि यह बात कोई आज की नही है। स्पीकर सर, मुझे बडा अफसोस होता है मैने जवाब तो उसी समय दे दिया था वैसे कोई साथी खेल नीति के बारे मे बोला भी नही। हमारी खेल नीति से बढिया और कोई खेल नीति नही हैं। आज हिन्दुस्तान के अंदर कोई भी रिजनल सैंटर स्पोर्टस का नार्थ जान मे नही था लेकिन अब आपके यहां सोनीपत मे नार्थ जॉन का रिजनल सैंटर बन रहा है यह अचीवमैंट हमारी सरकार की है। हमारे यहां कि लडकियां कामप वैल्थ में, एि ाया मे गोल्ड मैंडल लेकर आती है और किसी सरकार ने ध्यान नही दिया कि घास पर हाकी वे खेलती थी। स्पीकर सर,

आप तो खिलाडी रहे है आपको मालूम है कि हाकी के ने ानल और इंटरने ानल गेम्ज एस्टोटर्फ पर होते हे, घास पर नही खेला जा सकता। पहला एस्ट्रोटर्फ गुडगांव में हमारी सरकार बनवा चुकी है और दूसरा एस्ट्रोटर्फ भााहबाद मे कम्पलीट होने जा रहा है। ये हमारी सरकार की अचीवमैंट है। स्पीकर सर, सैंट्रल मिनिस्ट्री से युनिवर्सिटी भी मंजूर करवाई है। मै उनको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने तो घोशणा की है लेकिन बनानी तो भारत सरकार ने है। इसके लिए उनको सरकार की सराहना करनी चाहिए, वैलकम करना चाहिए। भारत सरकार के साथ हम मैटर को टेकअप कर रहे है और हमें उम्मीद है कि वे जल्दी ही हमारी बात को मानेंगे और युनिवर्सिटी हरियाणा मे बनेगी। यह यूनिवर्सिटी अपने आप मे पहली यूनिवर्सिटी होगी। स्पीकर सर, जब से हरियाणा बना है और हमारी सरकार आई है उससे पहले 50 लाख से उपर खिलाडियो को टोटल ईनाम नही दिया गया जबकि हमारी सरकार ने चार साल मे 5 करोड रुपये नकद ईनाम खिलाडियो को दिए है। हमारी खेल एसोसिए ान की तरफ से बकायदा खेलोके लिए कलैंडर छपता है जैसे सरकारी कलैंडर छपता है। मै चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को बधाई देता हूं कि इन्होने इसमे बहुत बडा योगदान दिया है। इनके कलैंडर मे होता है कि कब रुरल गेम्ज होंगे, कब पंचायत गेम्ज होंगे, कब जिला स्तर के गेम्ज होंगे, कब युनिवर्सिटीज और इंटर युनिवर्सिटीज के गेम्ज होंगे, कब स्टेट चैंपियनि ाप होगी, कब नै ानल और इंटरनै ानल गेम्ज होंगे। इस कलैंडर के माध्यम से सभी खिलाडियो को पता

चल जाता है। खेल नीति मे यह भी लिखा जाता है कि फलां मैडल जीतने पर एक करोड रुपया मिलेगा, फलां मैडल जितने पर 50 लाख रुपया मिलेगा। इस नीति मे अब दो तीन खेलो को ओर सम्मिलित किया गया है। Women festival और वैटर्न को पहले छोड दिया गया था अब इसे जोडा गया है। इसके अतिरिक्त हैंडीकैप खिलाडियो की तरफ पहले कोई ध्यान नही दिया गया था अब उनको भी इसमे भाामिल किया गया है। स्पीकर सर, अब हर जगह स्टेडियम बनाये जा रहे है और हर जगह खेल और खिलाडी नजर आ रहे है। इस बात के लिए इनको सरकार की सराहना करनी चाहिए। स्पीकर सर, चौधरी भजन लाल जी चले गये अब किसको बताउ फुड ग्रेनज के बारे मे कि हमारे समय मे कितनी फुड ग्रेन पैदा हुई है। 1994 से 1996 भाुरु तक चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे उस समय 1994–95 मे 109.73 लाख टन, 1995–96 मे 101.78 लाख टन, 1996–97 मे 114 लाख टन, और उसके बाद चौधरी बसी लाल जी की सरकार आई और 1997–98 मे 113 लाख टन, 1998–99 मे 121 लाख टन और हमारी सरकार आने के बाद 1999–2000 मे 130.65 लाख टन, 2000–01 मे 132. 29 लाख टन, 2001–02 मे जो कि भयंकर सूखा पडा था उससमय 123 लाख टन फुड ग्रेन पैदा हुई। हमारे से पहले सबसे ज्यादा फुड ग्रेन चौधरी बंसी लाल जी की सरकार के समय में 121 लाख टन पैदा हुई थी। हमने सूखे के समय किसानो को पूरा पानी देकर, पूरी बिजली देकर अच्छी फसल करवाई थी। वर्श 2003–04 मे जो एस्टिमेट है वह 137.16 लाख टन है। राव साहब ने यहां

पर इक्वल डिस्ट्रीब्यू ान आफ वाटर की बात कही कि क्या यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यू ान पानी का है। कौन पानी का इक्वल डिस्ट्रीबयू ान नही चाहता सब चाहते है। सबसे ज्यादा अगर साउथ हरियाणा के हामी थे तो वे चौधरी देवी लाल जी थे। ओथ लेते ही सबसे पहले गए नारनौल। 26 जनवरी का प्रोग्राम हो या 15 अगस्त का प्रोग्राम हो, हमे ाा कहते थे कि मेरा प्रोग्राम बनओ मै वहां जाउंगा। अगर चौधरी देवी लाल जी को सबसे ज्यादा प्यार था तो वह नारनौल और महेन्द्रग के एरिया से था। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप सभी बैठिये।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, हम तो यही कर सकते है कि पूरा पानी के बारे मे जितना अवेलेबल है, वह सभी को बराबर मिले। स्पीकर सर, नरवाना ब्रांच के साथ एस वाई एल का चैनल पैरलल बनाने की बात है, वह तभी होगी जब एस वाई एल का पानी आयेगा। इससे पहले जो पानी ले करके हम आ रहे है वह पानी बाद मे यमुना सिस्टम मे एन बी के लिंक के थ्रू डालते है और एन बी के लिंक सिस्टम है और दूसरा बुडेडा काम्पलैक्स है। वहां से भी एस वाई एल चैनल मे पानी जाना है। अगर वो पानी आपका आ जाता है तो रावी ब्यास का सरप्लस वाटर और एस वाई एल का आ जाता है ाते यह बुढेडा से आगे एक जगह यह दोनो इकटठी हो जायेगी। इसके बाद एस वाई एल चैनल का पानी चला जायेगा। इधर एन बी के लिंक ब्रांच मे पानी चला जायेगा। अब वह पानी है नी। वह न होने की वजह से सिस्टम न

होने की वज से एन बी के का जो सिस्टम है उसमें वह नही आ रहा। पीछे जो पानी नरवाना ब्रांच मे ले करके आ रहे है, नरवाना ब्रच वाला जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से आपकी एन बी के के अंदर कैपिसिटी 3700 क्यूसिक से ज्याद की नही होती। हम 3700 क्यूसिक पानी आज भी दे रहे है। जितना पानी सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, वह हम दे रहे है। और इसी तरीके से इन्होने या किसी और सदस्य ने जिक्र कर दिया कि स्कूलो की बिल्डिंगो की देख रेख के लिए कोई पैसा बजट मे नही रखा गया। इसके बारे मे मै। बताता हूं कि जब चौधरी भजन लाल जी की सरकार जुलाई 1991–1996 तक थी यानि जब ये चीफ मिनिस्टर थे तब कितना खर्च हुआ। उस अवधि मे इस काम के लिए केवल 18 करोड रुपये खर्च हुए। जब ंबंसी लाल जी मुख्यमंत्री थे तो इनके समय मे स्कूलो की बिलिडंगो और कमरो की रिपेयर आदि पर केवल 11 करोड रुपये खर्च हुए जबकि आपकी सरकार अब तक इस काम पर 72.30 करोड रुपये खर्च कर चुकी है। मै सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि दो दो बार नही बल्कि 6–6 व 7–7 बार इस काम पर पैसा खर्च किया गया है। सर्व ि ाक्षा अभियान और डी पी पी वगैरह अलग है। ये पैसा भी आपके तब मिलता है जब हम अपना भोयर देते है। कई स्टेटस ऐसी होती है जो अपना भोयर नही दे पाती है वह पैसा भी हम लेते है जैसे पुलिस मार्डनाइजे ान मे हमने लिया जबकि कई स्टेटस नही ले पायी। इस पैसे को लेने के लिए स्टेट सरकार को कंट्रीब्यू ान करना पडता है। स्पीकर साहब केवल 25 परसैंट ग्रांट है और 25

परसैंट लोन जबकि 50 परसैंट पैसा आपको अपना देना पडता है तब जाकर ऐसा पैसा मिलता है। आपके पास धेला देने का न हो, लोन देने की हिम्मत न हो तो 25 परसैंट आप दे लो। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो स्टेट ऐसा भोयर नही ले पाती वह भोयर भी हमने लिया है। स्पीकर सर, ऐसी बात नही है कि कोई बात बच गई हो जिसका हमने कोई जवाब न मे दिया हो। मै एक बात और सदन के सामने कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चौधरी देवी लाल जी का रास्ता अपनाया हुआ है। चौधरी देवी लाल जी हमे ाा यही कहा करते थे कि लोक राज लोक लाज से चलता है। इस बात को किसी सदस्य ने नही उठाया। केवल माननीय सदस्य श्री बिसला जी ने यह बात उठायी थी क्योंकि ये भी उनके सही अनुयायी रहे है। बिसला जी ने पूरी स्पोर्ट की है और 1977 मे भी पूरी स्पोर्ट की थी। यहां पर बोलते हुए इन्होने प्रोफै ानल टैक्स का ज़ि किया था। इस प्रोफै ानल टैक्स के बारे मे मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी। मुझे यह बात बताते हुए खु ाी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है कि आज ही घोशणा करो और मै मुख्यमंत्री जी की तरफ से घोशणा करता हूं कि हम प्रोफै ानल टैक्स वापिस लेते है। (तालियां) आप इसके लिए तो तालियां बजा दो। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मै आपके माध्यम से सदन से निवेदन करता हूं कि सभी साथी पूरानी बातो को छोड कर और दलगत राजनीति से उपर उठकर जो संतलित बजट मैने पे ा किया है, जो चहुमुखी विकास का बजट आया है उसको सारे ध्वनिमत से पास करें, धन्यवाद।

15:00 बजे

श्री अध्यक्षः अनिल विज जी, भाायद आप कुछ कहना चाहते है, यदि आप कुछ कहना चाहते है तो कहे।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, माननीय वित मंत्री जी ने प्रोफै ान टैक्स हटाने के बारे मे जो बात रखी है मै उसके बारे मे कुछ कहना चाहता हू।माननीय मुख्य मंत्री जी तथा वित मंत्री जी ने लोगो की भावनाओ का सम्मान करते हुए इस टैक्स को हटाया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने हमे ाा लोकहित की बात को माना है। पहले भी कई बार जब गवर्नमैंट ने ऐसा कोई निर्णय लिया और हमने बताया कि यह निर्णय लोगो के हित में नही है तो सरकार ने सहर्श हमारे सुझाव को माना है और ऐसे निर्णय को विदड्रा किया। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से सरकार ने प्रोफै ानल टैक्स को वापिसलिया है इसके लिए मै अपनी तरफ से, तमाम सदस्यो की तरफ से तथा हरियाणा की जनता की तरफ से सरकार तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहता हूं तथा यह कहना चाहता हूं कि प्रोफै ानल टैक्स से लोगो को काफी कटिनाईयो आती थी, गरीब लोगो की काफी दिक्कत आती थी। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को गरीबो का मसीहा कहा ही जाता है, तो लोगो की भावनाओ की कद्र करते हुए सरकार ने इस टैक्स को माफ किया है इसके लिए मै एक बार फिर उनका धन्यवाद करता हू। (विघ्न)

डा0 रधुबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिए। (विघ्न) आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे है।

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, कोई भेदभाव नही है, सदन के नेता खडे है इसलिए अभी आप बैठें। (शोर)

डा0 रधुबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, **********

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, आप बैठे। कादियान साहब जो बोल रहे है वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री औम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय मै आपके द्वारा सदन के सभी सम्मानित सदस्यो को अवगत करवाना चाहूंगा कि यह बात पहले भी कई मर्तबा आ चुकी है और कई बार मै इसे दोहरा चुका हूं अब फिर दोहरा रहा हूं कि स्वस्थ प्रजातात्रिक प्रणाली मे इस सदन के हर सदस्यको सरकार के खिलाफ नुक्नाचीनी करने का पूर्ण अधिकार है। हम इस बात के पक्षधर है कि अगर सरकार कही कोई गलत काम करती है तो उसको भूल सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए। (विध्न)

डा0 रधुबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुन ले।

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, सदन के नेता खडे है, इसलिए अभी आप बैठें।

श्री औम प्रका ा चौटालाः कादियान साहब, आप मुझे बीच मे न टोके और मेरी बात सुने। आपने अपना आचरण ठीक रखने की बात रखी थी लेकिन फिर भी आप अपना आचरण ठीक नही कर रहे है। हुडडा साहब, अब आप ही इन्हे समझाएं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मै यह कह रहा था कि प्रजातात्रिक प्रणाली में हैल्टी कि्टिसिज्म होना आव यक है और हम उसके पक्षधर है। सदन के माननीय सदस्यो को मैने कई मर्तबा कहा है कि हैल्टी कीटिसिज्म होना करे और कोई रचनात्मक सुझाव दें, सरकार इसको मानने के लिए निरंतर तैयार रही है और तैयार है। अध्यक्ष महोदय, इसी हाउस मे टैक्स का बिल पास होने लगा तो आपने इनको एक अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए मै आपका धन्यवाद करुंगा कि आपने बडे खुले मन से इनको अवसर दिा ओर इस बिल पर बोलने की बजाए विपक्ष के साथियो ने वाक आउट किया। आपने उस वक्त हाउस को एडजार्न किया कि भाायद दोबारा आकर ये लोग इस बिल पर चर्चा करें लेकिन ` लोग फिर भी नही आए। अध्यक्ष महोदय, बिल पास हुआ और बिल पास होने के बाद भी मौजूदा सरकार ने यह कहा कि अगर इस बिल मे कोई खामी है, कोई कमी है और उसके बारे मे प्रदेश का कोई भी नागरिक कहेगा तो हम इसमे सं ाोधन के लिए तैयार रहेंगे। हम तो गांधी जी के अनुयायी है और अपने ही लिये गये निर्णय को बदलने मे हम लेशमात्र संकोच भी नही करेंगे। अगर कोई अच्दा सुझाव आएगा तो हम उसमे अमैडमैंट के लिए भी तैयार है। प्रोफै ानल टैक्स का बिल पास होने के बाद हमारे

लोकदल बाडीज मिनिस्टर ने सारे प्रदे ा के सम्मानित लोगो को, हर समुदाय से जुडे हुए लोगो को, हर किस्म की युनियनो और संस्थानो से जुडे हुए जो सम्मानित सदस्य थे म्युनिसिपल कार्पोरे ान के प्रेजीडैंटस और म्यूनिसिपल कमि नर आदि की एक मर्तबा नही बल्कि तीन मर्तबा मीटिंग बुलाकर लोगो से सुझाव मांगे और जब लोगो के सुझाव हमारे पास आए तो हमने अपने ही पास किए हुए बिल मे अगले सै ान मे सं ाोधन किया और हाउस टैक्स के पास किए हुए बिल को अमैंड किय। हम इस बात के पक्षधर है और यह हमारी जिम्मेदारी भी है। जनता ने हमारे उपर अटूट वि वास प्रकट किया है, हम उसके पक्षधर है। अध्यक्ष महोदय, सदन मे हमारे सम्मानित सदस्यो ने जो सुझाव दिए कि प्रोफै ानल टैक्स को वापिस लिया जाए तो हमने उसको वापिस लिया है। अगर आप चाहे तो सदन मे रचनात्मक सुझाव दें, सरकार का हैल्दी कि्टिसिज्म करे। यह नी की पुराने प्रसिडैंट पर चले जो कि ठीक नही है। (विघ्न)

डा0 रघुबीर सिंह कादियानः **********

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। ये जो भी बोल रहे है वह कुछ भी रिकार्ड नही किया जाए।

डा0 रघुबीर सिंह कादियानः **********

श्री औम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सदन के साथी ने जो सुझाव दिया है कि बेरी के मेले बदल दे तो मै इनको बताना चाहूंगा कि इस सुझाव पर हम गौर करेंगे।

बजट 2004–05 की अनुदानो की मागो पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now discussion and voting on demands for grants on the Budget for the year 2004-05 will take place.

As per the past practive and in order to save the time of the House, all the demands for grants on the order paper (1 to 25) will be deemed to have been read and moved together. Hon'ble Member can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise the discussion. The notices of cut motions given by Sarvshri Capt Ajay Singh Yadav, Karanl Singh Dalal and Jagjit Singh Sangwan on Deamand No. 8; Sarvshri Capt. Ajay Singh Yadav, Karan Singh Dalal and Jagjit Singh Sangwan on Demand No. 9; Sarvshri Capt Ajay Singh, Karan Singh Dalal and Jagjit Singh Sangwan on Demand No. 10 and Sarvshri Capt Ajay Singh, Karan Singh Dalal and Jagjit Singh Sangwan on Demand No. 15 will also be demand to have been read and moved.

That a sum not exceeding **Rs. 93760000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **1 – Vidhan Sabha**.

That a sum not exceeding **Rs. 1344972000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **2 – General Administration**.

That a sum not exceeding **Rs. 6750819000 for Revenue Expenditure and Rs. 300000000 for Capital Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **3- Home**.

That a sum not exceeding **Rs. 1740806000 for Revenue Expenditure and Rs. 150000000 for Capital Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **4- Revenue**.

That a sum not exceeding **Rs. 486405000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **5 – Excise & Taxation**.

That a sum not exceeding **Rs. 9023720000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **6 – Finance**.

That a sum not exceeding **Rs. 7555799000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year

2004-05 in respect of charges under Demand No **7 – Other Administrative Services**.

That a sum not exceeding **Rs. 2144733000 for Revenue Expenditure and Rs. 4383062000 for Capital Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **8- Building & Roads**.

That a sum not exceeding **Rs. 18782215000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **9 – Education**.

That a sum not exceeding **Rs. 7223221000 for Revenue Expenditure and Rs. 2280970000 for Capital Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **10- Medical & Public Health**.

That a sum not exceeding **Rs. 602255000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **11 – Urban Development**.

That a sum not exceeding **Rs. 627951000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **12 – Labour & Employment**.

That a sum not exceeding **Rs. 5453085000 for Revenue Expenditure and Rs. 17500000 for Capital Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **13- Social Welfare & Rehabilitation**.

That a sum not exceeding **Rs. 274829000 for Revenue Expenditure and Rs. 13650270000 for Capital Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **14- Food & Supplies**.

That a sum not exceeding **Rs. 15999100000 for Revenue Expenditure and Rs. 303310000 for Capital Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **15- Irrigation**.

That a sum not exceeding **Rs. 387220000 for Revenue Expenditure and Rs. 5460000 for Capital Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **16- Industries**.

That a sum not exceeding **Rs. 2663764000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **17 – Agriculture**.

That a sum not exceeding **Rs. 1389738000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray

charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **18 – Animal Husbandry**.

That a sum not exceeding **Rs. 10077227000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **19 – Fisheries**.

That a sum not exceeding **Rs. 1088527000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **20 – Forests**.

That a sum not exceeding **Rs. 2066685000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **21 – Community Development**.

That a sum not exceeding **Rs. 239843000 for Revenue Expenditure and Rs. 150800000 for Capital Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **22- Co-operaion**.

That a sum not exceeding **Rs. 5921379000 for Revenue Expenditure and Rs. 556600000 for Capital Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **23- Transport**.

That a sum not exceeding **Rs. 16207000 for Revenue Expenditure and Rs. 40000000 for Capital Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **24- Tourism**.

That a sum not exceeding **Rs. 2362437000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **25 – Loans & Advances by State Govt.**.

Demand No. 8 (Building & Roads)

Capt. Ajay Singh Yadav

Shri Karan Singh Dalal

Shri Jagjit Singh Sangwan

That the demand be reduced by Re 1/-

Demand No. 9 Education

Capt. Ajay Singh Yadav

Shri Karan Singh Dalal

Shri Jagjit Singh Sangwan

That the demand be reduced by Re 1/-

Demand No. 11 Urban Development

Capt. Ajay Singh Yadav

Shri Karan Singh Dalal

Shri Jagjit Singh Sangwan

That the demand be reduced by Re 1/-

Demand No. 15 Irrigation

Capt. Ajay Singh Yadav

Shri Karan Singh Dalal

Shri Jagjit Singh Sangwan

That the demand be reduced by Re 1/-

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, आप हमें यह बताएं कि हमारा कितना समय है। हम 5 मिनट बोल सकते है या 6 मिनट बोल सकते है। अध्यक्ष महोदय, मै डिमान्ड नं0 8 पर अपने विचार रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, बजट पर बोलते हुए हमने मिस–मैनेजमैंट की बात की थी और लोन के विशय मे अपने विचार प्रकट किए थे कि सरकार ने बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है। इसके अलावा मैने ओर भी बातें कही थी लेकिन उन विशयो के बारे मे सम्पत सिंह जी ने अपने जवाब मे कुछ नही कहा है। मैने यह भी कहा था कि रिवाडी मे बाय पास नही है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मै डिमाण्ड पर बोल रहा हूं।

वित मंत्री (प्रो0 सम्तप सिंह): स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से सदन में क्लीयर करना चाहूंगा कि कल कैप्टन साहब ने ही नही बल्कि जितने भी दूसरे सदस्यो ने अपने सुझाव और विचार

रखे है हमने उनको नोट कर लिया है और सरकार उन पर गौर करेगी। (शोर)

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, मंत्री जी ने आपकी बात का जवाब दे दिया है, अब आप अपनी सीट पर बैठ जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मै एजुके ान पर और इरीगे ान पर बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, मंत्री जी ने आपकी बात का जवाब दे दिया है, अब आप अपनी सीट पर बैठ जाए। (शोर एवं विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादवः **********

श्री अध्यक्षः इनकी बात रिकार्ड नही की जाए। कर्ण सिंह जी आप बोलें। कैप्टन साहब, क्या आपकी बात खत्म नही हुई है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मै लैंड एक्वीजि ान के बारे मे बात कहना चाहता हूं। इसमे जो सेक ान 4 और 6 है, उसके बारे मे बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो बिल्ट आप हाउस है उनमे सैक ान 4 आब्जैक ान इन्वाइट किए बिना ही सैक ान 6 भी लगा दी है। मै यह कहना चाहता हूं कि कम` कम जब उन्होने जो वह चाहते है, वह एस डी एम के सामने बता दिया था तो ऐसा नही होना चाहिए था।

श्री अध्यक्षः आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे है?

कैप्टन अजय सिंह यादवः मै डिमांड नं0 11 पर बोल रहा हू। स्पीकर सर, मै लैंड ऐक्विजी ान के बारे में कहना चाहता हूं कि कम से कम बिल्ट अप हाउस को तो छोडना चाहिए था लेकिन ऐसा नही हुआ जिसके कारण आज वहां पर लोगो की हालत खराब हो गयी है। कालोनाइर्जस ने लोगो के लिए जो कालोनीज काटी थी उसमे ंन तो सीवरेज की फैसिलिटीज दी गयी थी और न ही कोई दूसरा कार्य किया गया था। मेरा कहना यह है कि वहां पर जि समय यह कालोनीज काटी जा रही थी उस समय टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट के लोग वहां पर क्या कर रहे थे? उनकी वजह से ही गरीब आदमी पर आज मार पड रही है।

श्री अध्यक्षः आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे है?

कैप्टन अजय सिंह यादवः मैं अर्बन डिवैल्पमैंट की डिमांड पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्षः अर्बन डिवैल्पमैंट की डिमांड तो अलग है और जो बात आप कह रहे है वह अलग है दोनो महकमे अलग अलग है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपल कमेटीज भी अर्बन डिवलैप्मैंट डिमांड मे आती है। मै तहबाजारी के बारे मे कह रहा हू। रिवाडी एक ऐसा भाहर है जहां पर तहबाजारी खत्म की जा रही है। इसलिए मेरा कहना है कि सरकार इस पर विचार करे। अध्यक्ष महोदय, जो उपजाउ लैंड है वह ऐक्वायर नही

करनी चाहिए। ठीक है आप वहां पर इंडस्टरी लगा रहे है आपने गढी हरसरु के अंदर मानेसर मे जमीन ऐक्वायर करने की बात की है। मेरा कहना है कि जो उपजाउ लैंड ऐक्वायर की जा रही है उसके रेट बहुत कम दे रहे है। वह लैंड ऐक्वायर करें जहां पर पानी मीठा हो लेकिन अगर उपजाउ लैंड एक्वायर की जाएगी तो यह ठीक नही रहेगा।

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब यह तो आप बजट पर भी बोल चुके है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मै डिमांड नं0 15 पर बोल रहा हू। हमारे यहां पर कुछ ऐसे एरियाज भी है जहां पर वाटर लेवल नीचे चला गया है। दोहान पच्चीसी एरिया मे कई मीटर तक पानी नही मिल रहा है। इसलिए एक तो मै वाटर रि–चार्जिंग के बारे मे जानना चाहूंगा कि सरकार का इस बारे मे क्या विचार है? दूसरे मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि टेल एंड की जहां जहां पर डिस्ट्रीब्यूटरीज ऐसी है जिनकी टेल पर पानी नही पहुंच रहा है तो क्या इनको भी ठीक करवाया जाएगा? इसके अलावा जे एल एन कैनाल की कैपेसिटी– 25 परसैंट इन्होने बढाने की बात कही है मै जानना चाहूंगा कि यह कैपेसिटी आपने किस तरह बढा दी? क्या आपने कोई इसकी रिपेयर की है या आपने इसकी गाद निकाली है। अगर जे एल एन कैनाल की कभी सफाई हुई हो तो इसके बारे मे वित मंत्री जी बता दें कि आपने कैसे उसकी कैपेसिटी बढा दी? इसी तरह ` अध्यक्ष महोदय,

डिस्ट्रीब्यू ान आफ वाटर की बात है जो पानी बंटवारे की बात है हम उससे बिल्कुल भी सैटिसफाईड नही है। जो पानी का बंटवारा है उसका सही तरीके से बंटवारा होना चाहिए। केवल दो जिले ही पूरे प्रदे ा का पानी ले जा रहे है जो ठीक नही है।

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब आपकी बात पूरी हो गयी है अब आप बैठिए। आप भाशण न दें। अब आप बैठें।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि सेंटर की वजह से प्रदे ा को 1100 करोड रुपये का घाटा हुआ है।

श्री अध्यक्षः आप यह कौन सी डिमांड पर बोल रहे है। आपको पता ही नही है कि आप किस डिमांड पर बोल रहे है?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मै डिमांड नं0 15 पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्षः लेकिन यह तो इसमे नही है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मै इसलिए यह कह रहा हूं क्योंकि इन्होने यह पांच से घटाकर 4.33 परसैंट कर दिया कि आपको 1100 करोड रुपये कम मिले। इस बारे मे आप चार साल क्यों नही बोले, आप केन्द्र के अंदर सरकार को क्यों सपोर्ट करते रहे, आपके एम जी क्यो स्पोर्ट करते रहे उस वक्त क्यों नही मुख्यमंत्री जी एस वाई एल के उपर बोले? (विध्न)

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब आप बैठिये। आपका समय समाप्त हो गया है। दलाल साहब, अब आप बोलें।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से डिमांड नं0 8 पर सबसे पहले अपने विचार रखना चाहता हूं। मै कट मो ान के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो पी डब्लयू डी (बी एंड आर) वर्क्स डिपार्टमैंट है उसको यह चाहिए कि अगर कोई भी सडक या कोई भी भवन बनाता है तो उसके बाहर एक बोर्ड लगाना चाहिए और उस बोर्ड पर ठेकेदार का नाम लिखना चाहिए जो उस सडक या भवन को बनाता है। इस बोर्ड पर उसका खर्चा लिखना चाहिए, उसकी स्पैसिफिके ान के बारे मे जिक करना चाहिए कि इसकी स्पैसिफिके ान क्या है? इसके अलावा उस बोड पर सडक या भवन की उम्र भी लिखनी चाहिए कि कितने साल के लिए यह बनाया गया है। अगर उससे पहले वह सडक टूटती है या उस भवन में केक आती है या वह बिल्डिंग नही बनती है तो उस वकत के ऐक्सियन, जे ई और ठेकेदार की जिम्मेदारी होनी चाहिए क्योंकि अगर यह जिम्मेवारी नही होती है तो सरकार जो सडके बनाती है वह अगले ही दिन टूटनी भाुरु हो जाती है। जो ये टैंडर इसमे देते है उका प्रोविजन इनको ये करना चाहिए कि अब तो सारा सिस्टम क्म्पयूटराईज करने का प्रयास किया गया है तो कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी आदमी को टैंडर देने की इजाजत दे लेकिन इन्होने टैंडर प्रणाली का एकाधिकार किया हुआ है।

श्री अध्यक्षः अब टैंडर वैबसाइट से और सारा ठीक ढंग से लिया जाता है।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैने पहले भी कहा था आर्कीटैक्चर डिपार्टमैंट जो कि पी डब्ल्यू डी का पार्ट है, उसको रिवाइज करना चाहिए। उसमे सरकार को चाहिए कि मार्डन टैक्नोलोजी को ऐडाप्ट करके जैसे अंग्रेजो के समय मे जो भी बिल्डिंग या पुल बनते थे उसमे कभी कही कैक नही आते थे लेकिन आज जो नयी बिल्डिंग बनती है चाहे वे गांव के स्कूल है या भाहरो मे भवन है उसमे बनने के दस दिन बाद ही कैक आनी भाुरु हो जाती है और उनमे तरह तरह की खामियां नजर आने लगती है। इनको अपने आर्कीटैक्चर डिपार्टमैंट को रिवाइज करना चाहिए। अब मै डिमांड नंबर 9 पर बोलना चाहता हू। जो एजुके ान की बात है आज गावों मू जो लोग बसे हुए है उनको बडी भारी दिक्कत है और लोगो को सरकारी स्कूलो मे कोई भरोसा नही है इतनी भारी रा ि ा सरकार ि ाक्षा के उपर खर्च करती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कम से कम बडे गावों मे या आठ दस गावों का समुह बनाकर माडल स्कूल बनाएं ओर उनमे जो टीचर्ज लगाए जाएं वह बहुत अच्छे पढे लिखे होने चाहिए। उनकी क्वालिफिके ान भाहर मे पढाने वाले अध्यापको से भी अच्छी होनी चाहिए और उन स्कूलो मे लडकियो के रहने की व्यवस्था भी होनी चाहिए और जो लडकियां दूर गांव

से आती है वे वहां हास्टल मे रहकर अपनी पढाई पूरी कर सकै और उनके खेलने की व्यवस्था वहां हो।

श्री भगवान दास रावतः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। हरियाणा एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है इसमे अलग अलग मापदण्ड नही होते है। भाहर और गांव के लिए क्वालिफिके ान समान होती है। (विध्न)

श्री कर्ण सिंह दलालः मेरा आपके माध्यम से सुझाव है कि ऐसे माडल स्कूल बनाए जिनसे मां बाप को भरोसा सरकार मे बढे। आज मा बाप अपने बच्चो को सरकारी स्कूलो मे पढाना नही चाहते और जिनके पास साधन है वे अपने बच्चो को दूर दूर भाहरो मे पढने के लिए भेजते है जिससे रकार के साधनो की बडी भारी व्यथ्र की वेस्टेज हो रही है इस बारे मे सरकार को विचार करना चाहिए। पिछले दिनो सरकार ने प्राईवेट स्कूल डी रिकग्नाइज करने का मूव चलाया है अगर स्कूलो की डी–रिकग्नाइज करते है वे आपके द्वारा बनाई गई मान्यता को पूरा नही करते है जो स्कूल डी–रिकग्नाइज होगा उके बच्चे कौन से स्कूल मे जाएंगे। इस बारे मे सरकार को इंतजाम करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब मै डिमांड नं0 11 जो अर्बन डिवैल्पमैंट के बारे में है बात करना चाहता हू। इसमें एक कानून मारे हरियाणा में लागू हुआ और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट है कि अगर कोई भी जमीन अर्बन डवल्पमैंट डिपार्टमैंट ऐक्वायर करता है तो सरकार को कोई हक नही है कि उस जमीन को

सरकार वापिस रिलीज करे। होई कोर्ट की जजमैंट यह है कि उसकी आक ान होगी। जबकि यह सरकार हाईकोर्ट की जजमैंट को इग्नोर करके उन जमीनो को अपने * को वापस करती है।

श्री अध्यक्षः यह भाब्द रिकार्ड न किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलालः मै आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि गलत परम्परांए नही डलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष (श्री गोपी चन्द गहलोत): माननीय कर्ण सिंह दलाल चौधरी बंसी लाल जी की सरकार मे साढे तीन साल तक मंत्री रहे है। मै इनको बतना चाहता हूं कि मेरे झाडस गांव की जोहड की जमीन जोकि सलोगढा के पास है उस जमीन को ऐक्वायर किया गया था और उस जमीन को यूनिटैक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी को दिया गया था जिस जमीन पर आज बिल्डिंग बनी हुई है ये उस टाईम को याद करे। इस तरह का एक उदाहरण मेरे पास है। यहां पर आज छः कालोनीज है जिसमे चौ0 देवी लाल नगर, विकास नगर, ऋशि नगर, रवि नगर आदि बनी हुई है। और चौधरी भजन लाल जी जो कि 12 साल तक इस प्रदे ा के मुख्यमंत्री रहे उनके समय मे भाम ाान घाटो की जमीन तक नही छोडी थी। सात कालोनीज जिनमे 80 प्रति ात से ज्यादा बनी हुई है आप बेचारे कोर्ट के चक्कर काट रहे है। मै माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारि ा करुंगा कि वे इस एरिया को रिलीज कर दे क्योंकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ही उम्मीद कर सकते

है पहले हम चौधरी देवीलाल जी से उम्मीद करते थे। यह सब सरकार पर निर्भर करता है।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, जो ये सैक्टर बनाये है। स्पीकर सर, गुडगांव आज हरियाणा का दिल है जहां हर आदमी की नजर आज गुडगांव पर है और आज वक्त आ गया है कि गुडगांव मे हाउसिंग और कमर्शियल चीजे नही करनी चाहिए। आज वहां पर इतनी भीड हो चुकी है क्योंकि वह डिपटी स्पीकर का इलाका है और मेरी ससुराल है इसके अलावा मै वहा पढा भी हू। मेरा आपके माध्यम से सरकार को एक सुझाव है कि आज अगर गुडगांव के अंदर किसी की मौत हो जाती है तो भामाशान घाट तक ले जाने मे बडी भारी दिक्कत आती है। इसलिए सैक्टर मे ही भामाशान घाट की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

श्री गोपी चन्द गहलोतः चौधरी भजन लाल जी बैठे नही है। मैने पहले भी इस बारे मे कई बार कहा है कि चौधरी भजन लाल जी की सरकार के समय गावों के भामाशान घाट की जमीन भी एक्वायर की गई थी। मै आज आभार प्रकट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का और चौधरी धीरपाल जी का कि जिनहोने मेरे गांव के जो दो भामाशान घाट थे, जिनकी जमीन पहले ऐक्वायर की गई थी आज सरकार ने रिलीज ही नही की बल्कि डिवैल्पमैंट वर्क करवाकर भाहर की तरफ वहां पर भामाशान घाट बनाया है। इसी तरह से मोलाहेडा और दूसरे गावों की जमीन को भी रिलीज किया गया है।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, अब मै डिमांड नं0 15 पर बोलना चाहता हू। इस बारे मे श्री सम्पत सिंह जी ने एस वाई एल के बारे मे चर्चा की है। इस बारे मे मै सरकार को सुझाव देना चाहता हू। फरीदाबाद और मेवात का इलाका जिसमे आगरा नहर से पानी आता है। आगरा मेन नहर जो बरसो से है जब से यह नहर बनी है यह अंग्रेजो के जमाने से लेकर अब तक पहली दफा उतर प्रदे ा सरकार ने इस नहर की खुदाई का काम करवाया है जो कि बडे सुनियोजित ढंग से नीचे तक खुदवाकर नहर की खुदाई करवाई है। स्पीकर सर, हमारी समस्या यह है कि नहर की खुदाई होने के प चात जो इसके रजवाहे थे वे उंचे हो गये है इसलिए इन रजवाहो मे पानी कम आता है। मै सरकार से अनुरोध करुंगा कि इन रजवाहो की खुदाई भी सराकर द्वारा करवाई जाये ताकि उनमें पूरा पानी आ सके। इससे पहले हमारे समय की सरकार ने उतर प्रदे ा की सरकार को पत्र लिखकर आगरा नहर के पानी को ज्यादा करवाया था लेकिन वर्तमान सरकार ने उस पानी को घटा दिया है। इसलिए फरीदाबाद के किसानो को पूरा पानी नही मिलता है इसका कारण यह है कि इस सरकार की यूपी की सरकार से मिली भगत है इसलिए पानी घटा है इसलिए उस पानी को बढवाया जाये। नहर की खुदाई हो चुकी है इसलिए रजवाहो की खुदाई भी होनी चाहिए जिसके कारण किसानो के खेतो मे अंतिम छोर तक पानी पहुंच सके।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, जब आप कृशि मंत्री थे उस समय इसकी खुदाई नही हुई क्या?

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, दूसरी नहरो की तो हुई थी लेकिन मेन आगरा कैनाल की नही हुई।

श्री अध्यक्षः आपने क्यों नही करवाई?

मुख्यमंत्री (श्री औम प्रका ा चौटाला): अध्यक्ष महोदय, श्री कर्ण सिंह दलाल जी जब विपक्ष मे थे और कांग्रेस की यहां सरकार थी तब ये इस बात का बहुत जिक किया करते थे कि कभी इनकी सरकार आई तो ये आगरा कैनाल का कंट्रोल अपने हाथ मे ले लेंगे। ताकत के बलबुते पर ले लेंगे। चौधरी बंसी लाल जी की सरकार बनी ओर साढे तीन साल तक रही। उसमे ये पावर मंत्री भी रहे लेकिन इन्होने एक सैकिण्ड भी आगरा कैनाल का जिक नही किया। अब ये या तो पुरानी बात को भूल गये या इनकी पावर खत्म हो गई होगी। अध्यक्ष महोदय कर्ण सिंह जी जब विपक्ष में बैठते है तब जनहित की बातो की तरफ ध्यान जाता है। बदकिस्मती से जब ये सत्तापक्ष मे आते है तो इनकी जनहित की बाते दिखाई नही देती। जब ये कृशि मंत्री थे तब ये कहते थे कि सारी नी लगाय पकड लेंगे। उस समय दो नी लगाय पकडी गयी थी और एक नी लगाय पर 1.50 लाख रुपये के करीब खर्चा आया था। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, ये पूरानी बाते भूल गये है।

श्री जगजीत सिंह सांगवानः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से डिमांड नं0 8 के बारे मे सुझाव देना चाहता हूं कि पी डब्ल्यू डी (बी एंड आर) महकमे ने बडी बडी बिल्डिंग भाहरो और गावों मे बना रखी है। उन बिल्डिंग की टूट फूट ठीक नही होती और न ही उनकी सफाई हो पाती है। किसी भी बिल्डिंग में जाकर देख लो सभी के भाी ो टूटे हुए है। उनको ठीक करने के लिए हर साल बजट बनता है लेकिन वे ठीक नही होती। उन बिल्डिंगज की तरफ ध्यान देन बहुत जरुरी है। कई गांव ऐसे है जहां एक एक या दो दो बिल्डिंगज बनी हुई है। ये जिस प्रयोजन के लिए बनाई गई थी वे प्रयोजन नही चल रहे। बहुत से विभागो के लिए बिल्डिंग बनी हुई है, प्राथमिक स्वास्थय केन्द्रो की बिल्डिंग बना दी गई, मिनी बैंको के लिए बिल्डिंग बना दी गई। कई जगहो पर रिहाय ाी मकान बने हुए है। लेकिन उनके रखरखाव की तरफ कोई ध्यान नही दिया जा रहा, उनको रखरखाव की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मै यह कहना चाहूंगा कि किसी गांव मे विभाग के लिए बन गया और वह विभाग वहा कार्य नही कर रहा तो वह बिल्डिंग किसी दूसरे विभाग को ट्रांसफर कर दी जाये न कि दूसरे विभाग के लिए अलग से बिल्डिंग बनाई जाए। बहुत से गावों मे इस तरह की बिल्डिंग बनी हुई है। इसके अतिरिक्त मै कहन चाहूंगा कि विभागो के जो स्टोर है वे कागजो मे तो पूरी तरह से भरे हुए है। उनमे साल मे, दो साल मे या तीन साल में अफसर बदलने पर हर बार दूसरा अफसर आने पर कागजो में रिकार्ड पूरा दिखा दिया जाता है लेकिन असल मे पूरा सामान नही

होता। इस बारे में मै कहना चाहूंगा कि समय समय पर मौके पर जाकर सामान की चैकिंग होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय अब मै मांग संख्या 9 के बारे में कहना चाहता हूं कि जो सरकारी स्कूल है इनके अंदर बच्चो की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ज्यादा बच्चे पढते प्राईवेट स्कूलो मे है और उनके नाम सरकारी स्कूलो मे लिखे हुए है। ज्यादातर सरकारी स्कूलो की यही हालत है। इस बारे में मै कहना चाहता हूं कि चैकिंग करके पता लगाया जाये कि ऐसे कितने बच्चे है जिनके नाम सरकारी स्कूल मे लिखे हुए है और वे पढते प्राईवेट स्कूलो में है या अध्यापको के घर पढते है। इस बारे में भी कमेटी बनाकर चैकिंग होनी चाहिए। जैसा कि वितमंत्री जी ने बताया कि सर्व ि ाक्षा अभियान जिसे पहले प्रौढ ि ाक्षा कहा जाता था इसके उपर करोडो रुपया खर्च होता है लेकिन लक्ष्य कम अचीव होता है। अध्यक्ष महोदय, दादरी तहसील मे झोजू गांव है वहां पर गांव वालो ने और इलाके के लोगो ने मिलकर बहुत ज्यादा पैसे से लडकियो का कालेज बनाया है। मेरी मुख्यमंत्री जी से और ि ाक्षा मंत्री जी से प्रार्थना है कि लडकियो के उस कालेज को तुरंत मान्यता दी जाये।

श्री रणबीर सिंह मन्दोलाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मै आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जिस झोलू गर्ल्ज कालेज की बात ये कर रहे है उसके बारे में आदरणीय सांसद भाई अजय सिंह चौटाला जी पहले ही घोशणा कर चुके है।

श्री जगजीत सिंह सांगवानः यदि वे घोशणा कर चुके है तो बहुत बढिया बात है। अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए मै सांसद महोदय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होने हां कर दी लेकिन मै बताना चाहता हूं कि सांसद सरकार नही है। मै सरकार से निवेदन कर रहा था कि वह इसे मान्यता दे और सरकार घोशणा करे कि इस आने वाले सै ान से वहां पढाई भाुरु हो जायेगी। (विघ्न) हमारी घोशणा का कोई अर्थ नही है। यहां पर सी एम साहब बैठे है। एजुके ान मिनिस्टर बैठे है। (विघ्न) मै उनकी घोशणा का स्वागत करता हू।

श्री अध्यक्षः सांगवान साहब, अब आप बैठिये।

श्री जगजीत सिंह सांगवानः स्पीकर सर, अभी तो मैने दो डिमांडज पर और बोलनता है। स्पीकर सर, मै उस बात के लिए ना नही करता, मै उसका स्वागत करता हू। अगर सरकार की तरफ से मान्यता दे दी जायेगी तो यह अच्छी बात होगी। हम इस बात के लिए सरकार का स्वागत करेंगे, इसमें कोई राजनीति नही करेंगे।

स्पीकर सर, अब मै ंडिमांड नं0 11 पर बोलना चाहता हू। मै नगर विकास के बारे मे सुझाव देना चाहता हूं कि अभी पिछले मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि जिस कालोनीज के अंदर नक ो पास नही होगें उनके अन्दर कोई सुविधा नही देंगे लेकिन उन कालोनीज में जिस किसी कालोनी मे 400–500 का घर है

और उनमे से 300 के पास नक ो पास हो गये है और 100 घरो के नक ो पास नही हुए है तो जिन लोगो के नक ो पास हुए है उनको भी वह सुविधा नही मिल पाती जबकि उनके नक ो आदि पास कर दिए गए है। ऐसा इलिए हो रहा है कि जिन लोगो ने नक ो पास नही करवाए है। जिन लोगो ने टैक्स दिया है, नलके लगवा लिए है, बिजली की तार सरकार ने उनको दे दी है, वे लोग बिजली के बिल दे रहे है और अब आगे बकाया लोगो के पास नक ो पास नही हो रहे है यानि जो 100–150 घर बन गए है उनकी वजह से वे बेचारे 300–400 घर बेचारे ख्वामखाह खामियाजा भूगत रहे है, इसमें मेरा एक सुझाव है कि जिनहोने नक ो पास करवाए है उनको तो सारी सुविधाए मिले। ओर दूसरा यह है कि एक सडक को पहले ईंटो का बनाया जाता है और फिर कंकरीट का बनाया जाता है। लेकिन उसके नीचे मल निकासी का, सीवरेज का या पानी को कोई काम नही देखता। कहने का मतलब यह है कि वहां पर बिना प्लानिंग के सारा काम होता है जिस कारण बाद मे वे सारी की सारी सडके टूट जाती है। फिर बाद मे उसकी रिपेयर आदि का बार बार बजट बनता है और उस पर बार बार पैसा लगता है। वह टूट जाती है, वह खराब हो जाती है तो इस किस्म का वहां पर सबसे पहले सीवरेज का काम होना चाहिए। बिजली वालो को काहना चाहिए कि वह अपनी तारे डाल ले इसी प्रकार से टेलीफोन वालो को कहो कि वे भी अपनी तार पहले ही खिंच ले ताकि वे सडके बार बार न टूटे। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस किस्म का एक ज्वायंट प्रयास सभी महकमो को

मिल कर करना चाएि ताकि जो सडके बनें उस पर जो कार्यवाही करनी है, सुविधा देनी है वह पूरी कर लें ताकि वह बार बार न टूटे।

अध्यक्ष महोदय, अब मै मांग संख्या 15 जा इरीगे ान से संबंधित है इसमे भी मोटे तौर पर तो स्टोर वाली बात आती है जो मैने बी एण्ड आर वाली डिमांड में कही है। मै सरकार के नोटिस मे लाना चाहता हूं कि सभी विभागो मे सरकारी टेलीफोनो का बडा मिसयूज होता हैं किसी भी विभाग मे प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक जाकर टेलीफोन करेंगे तो वह बिजली रहेगा। कोई अपनी साली को, कोई मामा को, कोई फुफा–बुआ को फोन करने लग जाते हैं इसलिए मेरी मांग है कि सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए ताकि सरकार का पैसा बच सके। यह रोक हरेक लैवल पर होनी चाहिए। स्पीकर सर, मेरे हलके मे इमलोटा का माईनर आर है। इस पर मैने पहले भी एक दो बार हाउस मे आपके माध्यम`स सरकार को यह सुझाव दिया है कि इसके अंदर डबल मोटर लगनी चाहिए। इस वक्त वहां पर एक मोटर लगी है जिसका कोई फायदा नही है। दूसरी मोटर न लगने के कारण पहली मोटर का भी पैसा बेकार हो गया। अगर यह दूसरी मोटर लगेगी तभी जाकर वहां पर सिंचाई हो सकेगी, यही मेरा आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है।

राव इन्द्रजीत सिंहः स्पीकर सर, मैने भी एक नोटिस आपकी सेवा मे दिया था।

श्री अध्यक्षः आपका भाार्ट नोटिस जो था वह डिस अलाउ कर दिया है।

राव इन्द्रजीत सिंहः स्पीकर सर, जिस दिन इन्होने दिया था उसी दिन मैने भी अपना नोटिस दिया था। मेरे अकेले का नोटिस डिस अलाउ क्यों कर दिया गया?

श्री अध्यक्षः आप अब बैठिये।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now voting on Demands on the Budget for the year 2004-05 will take place.

First, I will put cut motions on the demands to the vote of the House and then I wll put the demands to the vote of the House.

Demand Nos. 1 to 7

That a sum not exceeding **Rs. 93760000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **1 – Vidhan Sabha**.

That a sum not exceeding **Rs. 1344972000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **2 – General Administration**.

That a sum not exceeding **Rs. 6750819000 for Revenue Expenditure and Rs. 300000000 for Capital**

Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **3- Home**.

That a sum not exceeding **Rs. 1740806000 for Revenue Expenditure and Rs. 150000000 for Capital Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **4- Revenue**.

That a sum not exceeding **Rs. 486405000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **5 – Excise & Taxation**.

That a sum not exceeding **Rs. 9023720000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **6 – Finance**.

That a sum not exceeding **Rs. 7555799000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **7 – Other Administrative Services**.

The motion was carried.

Demand No. 8

Question is-

That the Demand be reduced by Re 1/-

That a sum not exceeding **Rs. 2144733000 for Revenue Expenditure and Rs. 4383062000 for Capital Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **8- Building & Roads**.

The motion was lost.

Demand No. 9

Mr. Speaker: Now, I put cut motion No. 2 on Demand No. 9 given by Capt. Ajay Singh Yadav, Shri Karan Singh Dalal and Shri Jagjit Singh Sangwan to the vote of the House.

Question is-

That the demand be reduced by Re 1/-

The moton was lost.

Mr. Speaker: Question is

That a sum not exceeding **Rs. 18782215000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **9 – Education**.

The motion was carried.

Demand No. 10

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding **Rs. 7223221000 for Revenue Expenditure and Rs. 2280970000 for Capital Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **10- Medical & Public Health**.

The motion was carried.

Demand No 11

Mr. Speaker: Now, I put cut motion No. 3 on Demand No. 11 given by Capt. Ajay Singh Yadav, Shri Karan Singh Dalal and Shri Jagjit Singh Sangwan to the vote of the House.

Question is-

That the demand be reduced by Re 1-

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is

That a sum not exceeding **Rs. 602255000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **11 – Urban Development**.

The motion was carried.

Demand No. 12 to 14

That a sum not exceeding **Rs. 627951000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **12 – Labour & Employment**.

That a sum not exceeding **Rs. 5453085000 for Revenue Expenditure and Rs. 17500000 for Capital Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **13- Social Welfare & Rehabilitation**.

That a sum not exceeding **Rs. 274829000 for Revenue Expenditure and Rs. 13650270000 for Capital Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **14- Food & Supplies**.

The motion was carried.

That a sum not exceeding **Rs. 15999100000 for Revenue Expenditure and Rs. 303310000 for Capital Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **15- Irrigation**.

Demand No. 16 to 25

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding **Rs. 387220000 for Revenue Expenditure and Rs. 5460000 for Capital Expenditure** be granted to the Governor to defray charges

that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **16- Industries**.

That a sum not exceeding **Rs. 2663764000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **17 – Agriculture**.

That a sum not exceeding **Rs. 1389738000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **18 – Animal Husbandry**.

That a sum not exceeding **Rs. 10077227000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **19 – Fisheries**.

That a sum not exceeding **Rs. 1088527000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **20 – Forests**.

That a sum not exceeding **Rs. 2066685000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **21 – Community Development**.

That a sum not exceeding **Rs. 239843000 for Revenue Expenditure and Rs. 150800000 for Capital Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **22- Co-operaion**.

That a sum not exceeding **Rs. 5921379000 for Revenue Expenditure and Rs. 556600000 for Capital Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **23- Transport**.

That a sum not exceeding **Rs. 16207000 for Revenue Expenditure and Rs. 40000000 for Capital Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **24- Tourism**.

That a sum not exceeding **Rs. 2362437000 for Revenue Expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No **25 – Loans & Advances by State Govt.**.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House stands adjourned till 9:30 A.M. tomorrow, the 17th February, 2004.

15:38 hrs.

(The Sabha then * adjourned till 9:30 A.M.on Tuesday, the 17th February, 2004)